हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

13 फरवरी, 2004

खण्ड–1; अंक– 6

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 13 फरवरी, 2004

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(6) 1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(6) 19
सर्वश्री रघुवीर सिंह कादियान तथा जय प्रकाश बरवाला, एम०एल०एज० के निलम्बन संबंधी सदन के निर्णय को रद्द करना।	21
राज्यपाल की ओर से संदेश	24
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं	24
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—	25
हरियाणा राज्य में चिकित्सा उपचार के लिए शुल्कों के बढ़ाने सम्बन्धी वक्तव्य—	26
उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी स्वास्थ्य राज्य मंत्री द्वारा सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र	33
वर्ष 2004–05 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा	34
बैठक का समय बढ़ाना	59
वर्ष 2004-2005 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	59
वाक–आउट	69
वर्ष 2004–05 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	70
बैठक का समय बढ़ाना	73
वर्ष 2004–05 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	74
बैठक का समय बढ़ाना	88
वर्ष 2004–05 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	

मूल्य :

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 13 फरवरी, 2004

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

———

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल-जवाब होंगे।

———

Construction of New Water Courses

***1598. Dr. Sita Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the district-wise number of new water courses constructed / repaired in the State during the period from 1st January, 2000 to till date ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct new water courses in District Sirsa particularly in Dabwali, if so, the details thereof ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : (क) हरियाणा के जिलों में पहली जनवरी, 2000 से आज तक काडा एवं हरियाणा राज्य लघु सिंचाई व नलकूप निगम ने पक्के खालें बनाये गये और हरियाणा राज्य लघु सिंचाई व नलकूप निगम एवं सिंचाई विभाग ने मरम्मत करवाये गये खालों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	जिले का नाम	पहली जनवरी, 2000 से आज तक पक्के करवाये गये खालों की संख्या			पहली जनवरी, 2000 से आज तक मरम्मत करवाये गये खालों की संख्या		
		एच०एस०एम० आई०टी०सी०	काडा	कुल योग	एच०एस०एम० आई०टी०सी०	सिंचाई विभाग	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	रोहतक	–	20	20	—	9	9
2.	सोनीपत	–	49	49	–	44	44
3.	झज्जर	–	20	20	–	6	6
4.	पानीपत	–	47	47	–	1	1

[श्री राम पाल माजरा]

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	जींद	55	114	169	2	16	18
6.	भिवानी	50	1	51	43	59	102
7.	फरीदाबाद	–	79	79	–	7	7
8.	कैथल	31	–	31	1	3	4
9.	हिसार	137	77	214	78	11	89
10.	फतेहाबाद	6	4	80	23	33	56
11.	सिरसा	206	1	207	128	76	204
12.	करनाल	--	--	--	--	4	4
	कुल योग	555	412	967	275	269	544

(ख) हाँ, श्रीमान जी

भाखड़ा कैनाल कमाण्ड में खालों को पक्का करने के लिए योजना का शुभारम्भ नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 1-11-03 को हो चुका है। इस योजना के द्वारा 31946 लाख रुपये की लागत से 2,39,154 हैक्टर एरिया को लाभ पहुंचेगा। यह योजना हरियाणा के आठ जिलों अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जीन्द, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में क्रियान्वित होगी। डबवाली विधान सभा क्षेत्र में इस योजना के अन्तर्गत खालों को पक्का किया जायेगा।

जिला सिरसा में तकरीबन 170 नये खालें पक्के करने की योजना है। जिनमें से 50 नये खालें डबवाली विधान सभा क्षेत्र में पक्के करने की योजना है। इस समय जिला सिरसा में तकरीबन 18 नये खालों को पक्का करने का कार्य चल रहा है। जिसमें से 14 खालें डबवाली विधान सभा क्षेत्र में पड़ते हैं।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय, सी०पी०एस० महोदय जी से जानना चाहूँगा कि जो खालें पक्की करने का कार्य काडा द्वारा किया जा रहा है, उसमें मेन खाल को कितने परसेंट तक पक्का किया जाता है और सिंचाई विभाग जो खालें पक्की करता है, उनको पक्का करने का क्या क्राईटेरिया है। किसान को अपनी खालें पक्की करने के लिए बार-बार विभाग के चक्र लगाने पड़ते हैं, ऐसा क्यों है? क्या विभाग में स्टाफ की कमी है और अगर है तो वहां पर स्टाफ को पूरा करने के लिए क्या सरकार द्वारा कोई प्रयास किए जाएंगे ताकि खालों को पक्का किया जा सके ?

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यक्रम एक ऐसी स्कीम है, जिसको 50-50 के शेयर के हिसाब से स्टेट गवर्नमैंट और केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाया जाता है। इसमें किसान 20 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खालों को पक्का करवाने के लिए अपनी वाटर यूजर एसोसिएशन में जमा करवाता है। पैसा जमा करवाने के बाद टैण्डर काल किए जाते हैं और वाटर यूजर एसोसिएशन की देख-रेख में खालें पक्की करवाने का काम स्टेट गवर्नमैंट की तरफ से करवाया जाता है। जहां तक रिपेयर करने की बात है तो इसमें भी सेम फार्मूला प्रयोग होता है। इसमें भी किसान 20 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खालों की रिपेयर करवाने के लिए अपनी वाटर यूजर एसोसिएशन में जमा करवाता है। पैसा जमा करवाने के बाद टैण्डर काल किए जाते हैं और वाटर यूजर

एसोसिएशन की देख-रेख में खालें रिपेयर करवाने का काम स्टेट गवर्नमैंट की तरफ से करवाया जाता है। जहां तक स्टाफ की कमी की बात है तो मैं इनको यह बताना चाहूँगा कि काडा अभी अस्तित्व में आया है और इसमें 319.46 करोड़ रुपये की योजना शुरू की गई है, इसमें और ज्यादा स्टाफ की जरूरत है। हमने नहरी डिपार्टमैंट से इसमें स्टाफ दिया है लेकिन इसमें फिर भी कमी है और जो स्टाफ की कमी है उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जाएगा ताकि इस स्कीम को क्रियान्वित किया जा सके।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं माजरा साहब का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने मेरे निवेदन पर मेरी कांस्टीच्यूएंसी के छांयसा गांव में लिफ्ट डिस्ट्रीब्यूटरी को पक्का करवाया था। लेकिन मैं इनको यह बताना चाहूँगा कि यह डिस्ट्रीब्यूटरी पूरी तरह से चल नहीं पा रही है। मुख्य मंत्री जी के आदेश हैं कि हर डिस्ट्रीब्यूटरी पक्की होनी चाहिए और उसके टेल तक पानी पहुंचना चाहिए। जब इसमें पानी चलता है तो यह टूट जाती है। मेरा निवेदन यह है कि पानी चलने से यह क्यों टूट जाती है, इस बारे में इन्क्वायरी करवाई जाए और इसमें जो भी आफिसर दोषी हो उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए और इस डिस्ट्रीब्यूटरी को ठीक करवाया जाना चहिए ताकि उसमें पानी टेल तक पहुंच सके।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न हरियाणा प्रदेश के कृषक के हितों से जुड़ा हुआ है चाहे वह डिस्ट्रीब्यूटरी का मामला हो या चाहे वह खालों का मामला हो। बिसला जी की मंशा डिस्ट्रीब्यूटरी के बारे में जानने की ही थी इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। मौजूदा सरकार चौधरी देवी लाल जी की उस नीति का पालन करने की पक्षधर है कि बिजली पानी का प्रबन्ध और भ्रष्टाचार बन्द। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिंचाई हो सके क्योंकि हमारे साधन तो सीमित हैं लेकिन हम उन सीमित साधनों का समुचित सदुपयोग करना चाहते हैं और इसी के दृष्टिगत हमारी सरकार बनने के बाद कई दर्जनों डिस्ट्रीब्यूटरीज बनायी गयी हैं, कितनों की टेल बढ़ायी गयी है, डिस्ट्रीब्यूटरीज और माईनर्ज को राईज भी किया गया है और उनमें पानी की कैपेसिटी भी बढ़ायी गयी है। बिसला जी डिस्ट्रीब्यूटरी की बात कह रहे हैं मैं बताना चाहूँगा कि अतीत की सरकारों ने कुछ इस किस्म की भी डिस्ट्रीब्यूटरीज पक्की की थी जिससे किसी एक व्यक्ति विशेष को लाभ हो। उस समय ये पीछे नीची कर दी जाती थी और आगे से ऊपर उठा दी जाती थीं। टेल वाले रोते रह जाते थे और किसी एक व्यक्ति विशेष का पानी लगता रहता था। लेकिन अब हमने आदेश इंजीनियर्ज को दे दिया है, इरीगेशन विभाग के सभी अधिकारियों को कि इस प्रकार की जो भी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं जिनका लेवल ठीक नहीं है उनको तोड़कर नये सिरे से ठीक करवाया जाए। अगले किसी भी किसान या किसी गांव की तरफ से इस बारे में दरख्वास्त आएगी तो बाकायदगी से उसको टैक्नीकली ऐग्जामिन करके ठीक करेंगे। जहां तक प्रश्न खालों का है हम चाहते हैं कि सारे के सारे खालें पक्के हों ताकि थोड़े पानी से ज्यादा सिंचाई हो। अतीत में एक ऐसी सरकार भी आ गयी थी जिसके मुखिया ने एक अव्यवहारिक निर्णय लिया था। वह व्यवहारिक निर्णय नहीं था कि जो खालें टूट जाएंगी उनकी मरम्मत किसान करेंगे। जबकि इनको मरम्मत करना किसान के बस की बात नहीं है हम कच्ची खांड भी नहीं संवार सकते हैं। सीमेंटेड खालें जब टूट जाए और जिसकी सतरौजा बारी में से आधे घंटे की या चालीस मिनट की बारी हो तो वह समझेगा कि तेरी बारी तो गयी इसलिए अब अगला वाला इसको ठीक करवा लेगा। इसका परिणाम यह निकलता है कि सारी खालें टूट जाती हैं और इससे किसान का बड़ा भारी नुकसान होता है, इससे पानी का नुकसान है, इससे रैवेन्यू का नुकसान होता है इसलिए हमने एक निर्णय और लिया

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

है। पता नहीं भजनलाल जी तो ठेकेदारी कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि यह प्रजातंत्र है इसमें पता नहीं जनता कब किसको ले आये।

चौ० भजन लाल : हमने ठेकेदारी नहीं करी है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : लेकिन आईन्दा से चौधरी बंसी लाल जी जैसा और पचूड़ा फिर ऐसा आदेश न दे दे कि टूटे हुए खालों की मरम्मत किसानों को करनी पड़ेगी इसलिए अब हमने एक पुख्ता निर्णय कर लिया है कि इनके दोनों पारे 9-9 इंच के बनाएंगे ताकि अगर कोई इनको कुल्हाड़ा लेकर भी तोड़ना चाहे तो वह नहीं टूटेंगे इससे पानी की बचत होगी तथा किसान का लाभ होगा। हमने और अखराजात में कटौती करके खालें बनाने के लिए अलग से 319.46 करोड़ रुपया दिया है। हम यह मानते हैं कि स्टाफ की कमी है इंजीनियर्ज की कमी है इसलिए हमने दूसरे विभाग के इंजीनियर्ज इसमें जोड़े हैं। हमने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द खालें बनें ताकि पानी का सदुपयोग हो सके। हमें उम्मीद है कि पुरानी वाली व्यवस्था को जल्दी हम ठीक करेंगे। भजन लाल जी, आपके पड़ोस में बैठने वाला व्यक्ति इस सैशन में नहीं है जब एस०वाई०एल० बनने जा रही थी तो उन्होंने उसके लिए दूसरे ढंग से काम शुरू किया था। उन्होंने वह टेल से बनवानी शुरू करवायी थी जबकि भजन लाल जी को पता है कि उस वक्त के इंजीनियर मि० पाठक बड़े सयाने थे उन्होंने इसका ऐतराज किया था कि नहर हमेशा मूड से बनती है और ड्रेन हमेशा टेल से खुदती है लेकिन चूंकि कमीशन खाना था इसलिए ऐसा किया। प्रादेशिक सरकार जो काम करेगी तो उसमें प्रदेश के लोगों का कमीशन होता है। जैसे आपकी आगरा कैनाल का मामला है भाखड़ा का मामला है यह पंजाब से जुड़ा हुआ है पैसा हमारा लगता है काम पंजाब के लोग करते हैं इसलिए चौधरी बंसी लाल जी ने केवल कमीशन खाने के लिए इस एस०वाई०एल० के मुद्दे को इतना उलझा दिया कि जिसका हम पिछले 16 सालों से कितना भारी नुकसान उठा रहे हैं। उन्होंने इसका काम गोदबलावा से शुरू करवाया था जो कि व्यावहारिक नहीं था। अगर शुरू से बनाते तो यह कभी की बन जाती। कितने हजारों करोड़ों रुपयों का हमारे रैवेन्यू का नुकसान हो गया है। कितना प्रदेश का विकास होना था। यह नेशनल लौस भी है क्योंकि वह पानी पाकिस्तान को जा रहा है। इसलिए हमारी मंशा मात्र एक है कि इस सारी व्यवस्था को जो हमारी है, जल्द से जल्द हम ठीक करेंगे और जब हमने यह निर्णय ले लिया था कि एस०वाई०एल० की नहर का पानी हमें मिलने से पहले-पहले सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज और माईनर्ज पक्की करेंगे और जो टूटी हुई हैं उनकी मरम्मत करेंगे।

भजन लाल जी, चौधरी बंसी लाल जी आपके पड़ोस में बैठते हैं इसी सदन में वे पिछली दफा कह रहे थे कि पहले से पैसा खर्च कर रहे हैं। जब जरूरत नहीं थी तब तो इन्होंने टेल से काम शुरू किया था और जब समुचित फैसला हो गया सर्वोच्च न्यायालय और पंजाब के फैसले के बाद जब इस बारे में हाउस में चर्चा आयी थी तो बंसी लाल जी ने कहा था कि अभी से क्यों बनाते हो, अभी से क्यों पैसा खर्च करते हो पानी आ लेने दो फिर बनाएंगे। नहर का फैसला जो हमारे पक्ष में हो चुका है, तो पानी तो हमें मिल गया है अब तो केवल यही तय होना है कि कौन सी ऐजेन्सी बनाए और कैसे बनाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहूँगा कि हम सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज, सारी खालें पक्की करेंगे। हम बहुत जल्दी में हैं और जल्दी से जल्दी सारा काम करेंगे ताकि पानी जाया न जाए। मैं पूरे सदन को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ खासकर इस मामले में कि जहां कहीं भी पक्के खालें बनवाने वालों को अपना शेयर आ जाएगा सरकार फौरी तौर

पर कार्यवाही करके दूसरे विभागों से इंजीनियर्ज लेकर वारफुटिंग पर इस काम को शुरू करेगी।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए, आपका कोई प्वाईंट-ऑफ ऑर्डर नहीं है।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, क्वैशचन आवर में कोई प्वाइंट-ऑफ ऑर्डर नहीं होता है, यह इनको मालूम होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

Repair of the Hospitals in the State

***1710. Sh. Jasbir Mallour :** Will the Minister of State for Health be pleased to state whether any action has been taken or proposed to be taken by the Government for the repair of the Hospitals in the State; if so, the details thereof ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डॉ० एम०एल० रंगा) : जी हाँ, स्वास्थ्य संस्थाओं के भवनों का रख-रखाव जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से करवाया जा रहा है, जिसके लिए तीन करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

श्री जसबीर मलौर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जो 3 करोड़ रुपया स्वास्थ्य सेवाओं के भवनों के रख-रखाव के लिए जारी किया गया है उसमें से डिस्ट्रिक्टवाईज कितना पैसा खर्च हुआ है और अम्बाला में कितना पैसा खर्च हुआ है। दूसरा मेरा सवाल यह है कि मेरे हल्के में पी०एच०सी० नूरपूर जो कि 1970 में बनी थी और पी०डब्ल्यू०डी० विभाग ने उसे काफी पहले अनसेफ डिक्लेयर कर दिया है। पिछले सत्र में भी मैंने इस बारे में मांग उठाई थी तो मंत्री जी ने कहा था कि पंचायत जमीन दे दे और रिजोल्यूशन दे दे तो हम विचार करेंगे। उसके मुताबिक हमने जमीन दे दी है और रिजोल्यूशन भी दे दिया है मैं जानना चाहूँगा कि कब तक इसके लिये पैसा जारी करेंगे और इस पर कब तक काम शुरू हो जाएगा ?

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि हमने रिपेयर हैड में जिला स्वास्थ्य समितियों को 3 करोड़ रुपये की राशि दी है उसके अतिरिक्त यूरोपियन कमीशन जो अम्बाला, करनाल और यमुनानगर में कार्यरत है, जिन्होंने अलग से इसके लिए पैसा मंजूर किया था उसमें 57 लाख रुपया अलग से मंजूर किया है। पूरे हरियाणा में 3 करोड़ 57 लाख 65 हजार रुपया मंजूर किया है जिसमें से अम्बाला में रिपेयर के लिए 10 लाख रुपया दिया है और पी०एच०सी० व सी०एच०सी० की रिपेयर के लिए 9 लाख दिया है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और सब-सैंटर्ज के लिये 1 लाख 35 हजार दिया है, इस तरह से 20 लाख 35 हजार रुपया अम्बाला जिले व जिले के अन्तर्गत आने वाले अस्पतालों के भवनों की रिपेयर के लिए दिया है, भिवानी के लिए 38 लाख 25 हजार, फरीदाबाद 23 लाख 45 हजार, फतेहाबाद 15 लाख 50 हजार, गुड़गांव में 15 लाख 50 हजार, हिसार में 29 लाख 85 हजार, झज्जर में 15 लाख 30 हजार, जींद में 18 लाख 10 हजार, कैथल में 16 लाख 20 हजार, कुरुक्षेत्र में 13 लाख 85 हजार, करनाल में 18 लाख 25 हजार, नारनौल में 16 लाख, पंचकूला 9 लाख 15 हजार, पानीपत 13 लाख 5 हजार, रिवाड़ी 13 लाख 45 हजार, रोहतक 15 लाख 90 हजार, सिरसा 18 लाख 20 हजार, सोनीपत 19 लाख 30 हजार, यमुनानगर के लिए 18 लाख 17 हजार दिया है। इस तरह से 3 करोड़ 57 लाख 65 हजार रुपये दे चुके हैं। जो नूरपुर की पी०एच०सी० की बात माननीय सदस्य ने कही है यह ठीक है कि वह जीर्ण-

[डॉ० एम०एल० रंगा]

शीर्ण अवस्था में है। उसके लिए सरकार की ओर से जमीन स्थानांतरण हो चुकी है इसके लिए वित्तीय व्यवस्था होने पर हम अलग से बजट का प्रावधान करेंगे और उस बिल्डिंग का रिपेयर और निर्माण कार्य करा दिया जाएगा।

सरदार निशान सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी से इससे संबंधित एक सवाल की जानकारी चाहूँगा कि टोहाना हल्के के गांव पिर्थल में माननीय चौधरी देवी लाल जी की जो 1987 से 1991 के समय जो सरकार थी उस समय एक पी०एच०सी० बनाई गई थी जिसका भवन अभी तक नहीं बनाया गया है। डॉक्टर तथा अन्य स्टॉफ वहां पर जाते हैं उनको बैठने के लिए पंचायत ने जगह दी हुई है। मैं जानना चाहूँगा कि पिछली सरकारों के समय उस भवन को नहीं बनाया गया, क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतायेंगे कि उस भवन को कब तक बना दिया जायेगा ?

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से हमारे साथी बता रहे हैं कि उस भवन को बनाने की घोषणा हो चुकी है और उनके अनुसार जमीन भी दी जा चुकी है। यह प्रस्ताव मैं विभाग से निकलवाकर देख लूंगा और अगर जमीन ली जा चुकी होगी तो उस हिसाब से पी०डब्ल्यू०डी० विभाग को एस्टिमेट के लिए केस भेज दिया जायेगा और वहां से एस्टिमेट आने के बाद यह केस वित्त विभाग को भेज कर वित्त की व्यवस्था करवा दी जाएगी।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी मंत्री महोदय ने बताया कि जो होस्पिटल्ज हैं उनकी रिपेयर के लिए 3,57,65,000/- रुपये सरकार ने मंजूर किए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि अम्बाला कैंट का जो अस्पताल है पहले वह खैराती होस्पिटल के नाम से जाना जाता था आज उस अस्पताल की जर्जर हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। कन्टोनमैंट बोर्ड से यह भवन मिलने के बाद आज तक हम उस भवन की हालत को बदलने में कामयाब नहीं हुए हैं। होस्पिटल के भवन निर्माण और रिपेयर के लिए यूरोपियन कमीशन के माध्यम से 60 लाख रुपये स्वीकृत हो चुके हैं। उसके टैण्डर भी काल हो चुके हैं और टैण्डर खुल भी गये हैं लेकिन उसके बाद न जाने किन कारणों से आज तक उस भवन की रिपेयर नहीं हुई है। मैं कारणों को जानना नहीं चाहता लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि क्या वे इस सदन में आश्वासन दे सकते हैं कि उस अस्पताल की जर्जर हालत को सुधारने के लिए और उसका रख-रखाव करने के लिए भवन का पुनर्निर्माण कर दिया जायेगा।

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारे सम्मानित सदस्य स्वयं यूरोपियन कमीशन के सदस्य हैं और ये हर मीटिंग में बैठते हैं और मेरे से ज्यादा जानकारी उन्हीं को होनी चाहिए कि यूरोपियन कमीशन को पैसा किस तरह से खर्च किया जा रहा है। फिर भी इन्होंने पूछा है कि यह पैसा किन कारणों से रह गया है उस समिति में यह पूछ सकते हैं। जहां तक रख-रखाव और रिपेयर की बात है अम्बाला में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में जो पैसा दिया गया है वह अस्पतालों की रिपेयर के लिए ही दिया गया है और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में कोई अस्पताल ऐसा नहीं रहेगा जिसकी रिपेयर नहीं हुई हो।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो बड़े अस्पताल हैं वहां पर तो रिपेयर की जाती है लेकिन जो गांवों में सब-सैंटर हैं, पी०एच०सी० हैं जिनकी हालत खस्ता है उनके बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है क्योंकि मेरे हल्के के दो गांव

जेरपुर और हैसका में जो पी०एच०सी० हैं उनके लिए आपने पैसा रखा है परन्तु इन दोनों सब-सैंटर्ज की हालत बहुत खराब है।

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, तीन करोड़ रुपये जो पी०डब्ल्यू०डी० विभाग को रिपेयर के लिए दिया करते थे उसमें कई सब-सैंटर रिपेयर के लिए रह जाते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने अलग से तीन करोड़ रुपये हमारे विभाग को दिए हैं हमने इन तीन करोड़ रुपये को खर्च करने के लिए एक समिति बनाई हुई है। यह समिति राज्य में यह देखेगी कि जिस भी अस्पताल के या पी०एच०सी० के दरवाजे और खिड़कियां टूटे हुऐ हैं उनको लगवायेगी और जहां पर रिपेयर की जरूरत है वहां पर रिपेयर करवायेगी जहां पर पैसे की जरूरत पड़ेगी हम और पैसा देंगे। फिर भी माननीय सदस्य ने रेवाड़ी के गावों का जिक्र किया है मैं उनको बताना चाहूँगा कि रेवाड़ी जिले को हमने 13 लाख 40 हजार रुपये रिपेयर के भिजवाये हुए हैं ताकि सभी भवनों की रिपेयर करवा दी जाए अगर और धन की आवश्यकता होगी तो हम और राशि भी भिजवा देंगे।

Construction of Power House/Sub-stations in District Jhajjar

*** 1686 Shri Nafe Singh Rathi :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of Power Houses/Sub-stations are being constructed in district Jhajjar during the year 2003-2004 ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : झज्जर जिला में वर्तमान 132 के०वी० उप-केन्द्र मातनहेल तथा 33 के०वी० उप-केन्द्र माछरौली की पहले ही क्रमश: सितम्बर तथा दिसम्बर, 2003 के दौरान क्षमता वृद्धि कर दी गई है तथा 33 के०वी० उप-केन्द्र झज्जर की क्षमता वृद्धि मार्च, 2004 तक की जाएगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 2004-05 के दौरान पटेल पार्क (बामनौली) तथा एम०आई०ई० (ए) बहादुरगढ़ में 2 नये 33 के०वी० उप-केन्द्रों का निर्माण करने तथा 33 के०वी० उप-केन्द्र एच०एन०जी० बहादुरगढ़ की क्षमता वृद्धि करने की योजना है। इस क्षेत्र में वोल्टेज स्तर तथा बिजली की आपूर्ति की स्थिति में सुधार लाने के लिए बहादुरगढ़ में एक नया 220 के०वी० उप-केन्द्र सेक्टर-9 बहादुरगढ़ में 132 के०वी० उप-केन्द्र का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इन उप-केन्द्रों का निर्माण कार्य वर्ष 2005-06 में पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

चौ० नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, बहादुरगढ़ आज से 40 साल पहले 1964 में इण्डस्ट्रियल एरिया बना था। पिछली सरकारों के समय में वहां पर कोई काम नहीं हुआ। अब हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे प्रदेश में विकास कार्य करवाये हैं और आज से चार दिन पहले दो सब-स्टेशनों की आधारशिला बहादुरगढ़ में रखी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि बहादुरगढ़ में 850 एकड़ भूमि नया इण्डस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए अधिग्रहण की गई है, बहादुरगढ़ में जो ये 220 के०वी० और 132 के०वी० के पॉवर हाउस बनाने के बारे में मंत्री जी ने बताया है, इन पर कार्य इसी साल शुरू हो जायेगा या समय लगेगा।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने ठीक ही बताया है कि बहादुरगढ़ में बहुत पुराना इण्डस्ट्रियल एरिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि बहादुरगढ़ में जो ये 220 के०वी० और 132 के०वी० के उप-केन्द्र लगाने की स्वीकृति मिली है ये

[श्री राम पाल माजरा]

उप-केन्द्र इंटरलिंक होंगे। 400 के०वी० का उप-केन्द्र जो तावोदाखुर्द में पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया ने बनाना है उससे ये दोनों उप-केन्द्र इंटरलिंक होंगे और इनको वर्ष 2005-06 में पूरा किया जाना प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, 400 के०वी० का उप-केन्द्र तावोदाखुर्द में और 220 के०वी० और 132 के०वी० के उप-केन्द्र बहादुरगढ़ में बनने के बाद वहां पर इण्डस्ट्रियल एरिया के लिए बिजली की किसी तरह की समस्या नहीं रहेगी। जिस प्रकार हरियाणा हर क्षेत्र में प्रगति के पद पर बढ़ रहा है, ठीक उसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। वहां पर उद्योग लगने पर बिजली की समस्या नहीं होगी।

Compensation to Farmers on Burning of Wheat Crops

* **1750 Shri Balbir Singh :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the wheat crops were burnt during the harvesting seasons every year in the State ; if so, the districtwise loss occurred during the last four years ; and

(b) whether any compensation has been given to the farmers of the State on this account; if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) : इस सम्बन्ध में सूचना सदन के पटल पर रखी गई है।

सूचना

पिछले चार वर्षों के दौरान राज्य में किसानों द्वारा स्वयं गेहूँ की फसल जलाने की कोई सूचना नहीं है, किन्तु कटाई कार्य करते समय दुर्घटनावश आग लगने की छुट-पुट घटनाएं हुई हैं। जली हुई गेहूँ के क्षेत्र तथा मुआवजे में प्रदान की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :—

जिला	प्रभावित क्षेत्र (एकड़ में)					मुआवजे की राशि (रुपयों में)				
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	योग	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
फतेहाबाद	27.1	4.6	1.9	-	33.6	54062	9375	3800	-	67237
नारनौल	3.0	0.1	7.0	0.2	10.3	4500	2680	11380	1510	20070
झज्जर	19.2	14.5	25.2	2.0	60.9	33463	29653	52208	4000	119324
जीन्द	-	-	-	23.2	23.2	-	-	-	41230	41230
यमुनानगर	-	-	-	-	-				-	-
भिवानी	11.1	-	-	-	11.1	20992	-	-	-	20992
पंचकूला	2.5	1.5	-	1.7	5.7	11406	3000	-	3725	18131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सिरसा	–	4.1	3.3	4.0	11.4	63328	8250	6750	13915	92243
कुरुक्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
फरीदाबाद	19.0	12.0	5.5	19.5	56.0	34860	21505	13038	30774	100177
कैथल	49.8	228.6	–	–	278.4	10250	450400	–	–	460650
अम्बाला	1.4	93.4	–	–	94.8	450	29736	–	–	30186
रोहतक	1.5	23.0	54.2	–	78.7	3760	45850	108636	–	158246
पानीपत	8.6	–	–	–	8.6	4960	–	–	–	4960
हिसार	–	–	1.0	1.0	2.0	–	–	2950	695	3645
करनाल	317.3	–	325.7	–	643.0	613067	–	640350	–	1253407
रिवाड़ी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सोनीपत	17.0	18.0	94.0	–	129.0	26228	30410	175870	–	232508
गुड़गांव	7.0	10.2	10.0	15.3	42.5	5650	15380	4800	12382	38212
कुल योग	484.5	410.1	527.8	66.9	1489.3	886966	646239	1019782	108231	2661218

बिजली की तारों व वितरण ट्रांसफार्मों से चिंगारी निकलने के कारण भी आग लगने की घटनाएं होती हैं। किसानों द्वारा बिजली वितरण निगमों के पास दावे प्रस्तुत किए गए थे। प्रस्तुत किए गए दावों व अदा की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :—

जिले का नाम	पिछले चार वर्षों में किसानों द्वारा दायर किए गए दावों की संख्या	दावा राशि (लाख रुपये में)	अदा की गई राशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4
उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम			
अम्बाला	0	0	0
पंचकूला	0	0	0
यमुनानगर	5	4.15	0
कुरुक्षेत्र	30	6.84	5.04
कैथल	15	1.68	0
करनाल	15	3.96	0
पानीपत	9	1.45	0
सोनीपत	11	2.55	0
रोहतक	0	0	0

[सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू]

1	2	3	4
झज्जर	0	0	0
जीन्द	12	8.51	0
कुल योग	97	29.14	5.04
दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम			
फरीदाबाद	47	16.45	0
गुड़गांव	3	1.68	0
नारनौल	0	0	0
रिवाड़ी	0	0	0
भिवानी	1	0.32	0
हिसार	8	1.98	0
फतेहाबाद	0	0	0
सिरसा	1	0.5	0
योग	60	20.93	0
कुल योग	157	50.07	5.04

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि राज्य में प्रत्येक वर्ष कटाई के सीजन में गेहूँ की फसल बिजली के शार्ट सर्किट से जल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इससे गत चार वर्षों में जिलावार कितना नुकसान हुआ है और किसानों को कितना मुआवजा सरकार की तरफ से दिया गया है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी पूछना चाहूँगा कि क्या पिछली सरकारों के समय में भी फसल नष्ट होने पर कोई मुआवजा किसानों को दिया जाता था यदि दिया जाता था, तो कितना पैसा दिया जाता था?

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि पिछले चार साल में 1489 एकड़ फसल नष्ट हुई है और उसके लिये सरकार ने 26,61,218 रुपये मुआवजा किसानों को दिया है। जहां तक इस बारे में पिछली सरकारों के समय के बारे में पूछा गया है इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि 1987 में जब हमारी सरकार आई उससे पहले 400 रुपये मुआवजा फसल नष्ट होने पर प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को देने का प्रावधान था लेकिन हमारी सरकार ने इसे 400 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से कर दिया था। स्पीकर सर, उसके बाद चौधरी भजन लाल जी की सरकार पांच साल रही और चौधरी बंसी लाल जी की सरकार साढ़े तीन साल रही, तकरीबन नौ साल में जितनी राशि हमारी सरकार छोड़कर गई थी उतनी ही मिली उसमें कोई बढ़ौतरी नहीं हुई। जब चार साल पहले हमारी सरकार आई हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने यह राशि 600 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये तीन गुणा से भी अधिक कर दी।

10.00 बजे

श्री बलवंत सिंह मायना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से

जानकारी चाहूँगा कि आगजनी की दुर्घटना से फसलों को जो हानि होती है, उसको बचाने के लिये सरकार की तरफ से क्या कदम उठाये गये हैं ?

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : सर, आग लगने के कई कारण हैं। इनमें कई बार जो तारें होती हैं उनमें चिंगारी आने के कारण भी आग लग सकती है, कई बार किसी व्यक्ति से गलती से बीड़ी-सिगरेट आदि जलती फैंकने के कारण भी आग लग जाती है। कई बार किसान अपनी दूसरी फसल बोने की जल्दी में पहली फसल का जो वेस्टेज होता है उसको जब जलाते हैं तो भी हवा का रुख चेंज होने के कारण आग लग जाती है। इनकी रोकथाम के लिये हरियाणा सरकार ने बिजली विभाग द्वारा जो पुरानी तारें थीं, उनको बदला है। इसके अलावा हरियाणा में किसान क्लब बनाये गये हैं, जिनमें समय-समय पर किसानों को इन क्लबों के माध्यम से जानकारी दी जाती है और उनको बताया जाता है कि यदि आग लग जाये तो उसके बचाव के क्या-क्या उपाय करने चाहियें।

तारांकित प्रश्न संख्या 1760

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री जरनैल सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Power Generated from Thermal Power Stations

* **1723 Dr. Malik Chand Gambhir :** Will the Chief Minister be pleased to state the total Megawatt of power generated from the State's own Thermal Power Stations during the last four years and during the year of 1997-98 and 1998-99 separately ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : राज्य के अपने थर्मल पावर स्टेशनों से विद्युत उत्पादन इस प्रकार रहा :—

वर्ष 1999-2000 में, 3811.38 मिलियन यूनिट

वर्ष 2000-2001 में, 3550.60 मिलियन यूनिट

वर्ष 2001-2002 में, 4932.00 मिलियन यूनिट

वर्ष 2002-2003 में, 5965.40 मिलियन यूनिट

वर्ष 2003-2004 में जनवरी 2004 तक, 5451.10 मिलियन यूनिट।

वर्ष 1997-98 तथा वर्ष 1998-99 में विद्युत उत्पादन क्रमश: 3510.74 मिलियन यूनिट तथा 3515.41 मिलियन यूनिट रहा।

डॉ० मलिक चन्द गंभीर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने तफसील में बताया है कि इस दिशा में कितनी वृद्धि हुई है। आज बिजली की कितनी जरूरत है कि बिना बिजली के किसी का गुजारा नहीं हो सकता। मेरे हल्के यमुनानगर का थर्मल प्लांट काफी समय से नहीं चल पा रहा जबकि इस सरकार के आने से पहले भी दो सरकारें जा चुकी हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि अब मौजूदा सरकार द्वारा इस पावर प्लांट को चलाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर साहब, वैसे तो इस सप्लीमेंटरी का इस मेन सवाल से कोई संबंध नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपकी इजाजत से माननीय साथी को बता देना चाहूँगा कि विभाग

[श्री राम पाल माजरा]

की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उनमें संबंधित विभागों से अनापत्ति सर्टिफिकेट लिए जा रहे हैं। पोल्यूशन विभाग से अनापत्ति सर्टिफिकेट लिया जा चुका है और नहर विभाग से यह सर्टिफिकेट लिए जाने की कार्यवाही जारी है। इस समय इस प्लांट को लाईन पर लाने के लिए काफी कार्य प्रगति पर है।

Financial Assistance to Gaushalas

***1756. Sh. Ram Phal Kundu :** Will the Minister of State for Animal Husbandry be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to provide financial assistance to the Gaushalas in the State, if so, the assistance provided to Gaushalas by the Government from the period 2001-02 till to date?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : श्रीमान् जी, गोशालाओं को वित्तीय सहायता देने की कोई नियमित योजना नहीं है फिर भी वर्ष 2001-02 से आज तक विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से राज्य की गोशालाओं को 574.71 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिये गये है।

श्री रामफल कुण्डू : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि हरियाणा में कुल कितनी गऊशालाएं हैं और उनको मौजूदा सरकार की तरफ से कितना-कितना पैसा दिया गया है।

श्री राम पाल माजरा: सर, मौजूदा सरकार की तरफ से 189 गऊशालाओं को 12 लाख रुपया दिया जा चुका है। स्पीकर साहब, इन गऊशालाओं में रजिस्टर्ड और अन-रजिस्टर्ड गऊशालाएं भी हैं। इन 189 गऊशालाओं में से 151 गऊशालाएं रजिस्टर्ड हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से 96 गऊशालाओं को 51 हजार रुपया प्रति गऊशाला दिया गया है। इसी प्रकार से पशु धन विकास बोर्ड की तरफ से इन गऊशालाओं को 1 करोड़ 32 लाख रुपया दिया जा चुका है। सर, जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा भी जितनी गऊएं गऊशालाओं में होती हैं उनकी संख्या के हिसाब से 151 गऊशालाओं को पैसा दिया गया है। इसी प्रकार से 147 गऊशालाओं को 75 हजार रुपया प्रति गऊशाला के हिसाब से सूखा राहत कार्यक्रम के तहत मदद दी गई थी। जिन गऊशालाओं में 200 गऊओं की संख्या है ऐसी 102 गऊशालाओं को भारत सरकार के सूखा राहत कार्यक्रम के तहत भी पैसा दिया गया है।

श्री रामफल कुण्डू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहूँगा कि मेरे हल्के में घड़ोली में एक बहुत बड़ी गऊशाला है जिसमें हरियाणा सरकार के सहयोग से एक रिसर्च सैन्टर भी बन रहा है। इस रिसर्च सैन्टर के लिए अभी तक वहां पर पूरा स्टाफ नहीं पहुंचा है, मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि वहां पर कब तक स्टाफ भिजवाने का काम पूरा कर पाएंगे?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर साहब, यह ठीक है कि घड़ोली में एक रिसर्च सैन्टर बनाया जा रहा है। इसके लिए सरकार की तरफ से 1 करोड़ 60 लाख रुपये दिए जा चुके हैं। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि रोहतक में भी एक इसी तरह की गऊशाला है उसको भी 19 लाख 5 हजार रुपये दिए गए हैं। जहां तक मैनेजमेंट का सवाल है, उसको पैसे की कमी नहीं आने दी जा रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मुँह की बीमारी का इलाज वहां पर किया जायेगा इस पर 11 करोड़ 64 लाख रुपये खर्च होंगे। इसी प्रकार से कल वित्त मंत्री जी ने भी बताया कि इस प्रकार

अनेक इन्स्टीच्यूशन्ज हैं जो इस मामले में काम कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री हरियाणा में पशुधन को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं, जिनमें नई-नई डिस्पैंसरीज व पशु अस्पताल खोले गए हैं। हरियाणा सरकार के "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत पशुधन को बचाने के लिए बहुत सारे काम प्रत्येक हल्के में किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से हरियाणा में पशुधन को बढ़ावा देने का काम मौजूदा सरकार द्वारा किया जा रहा है उसकी प्रशंसा भारत सरकार द्वारा की गई है। इस संबंध में भारत सरकार ने हरियाणा सरकार को एक पत्र लिखा है। आपकी इजाजत से मैं इस पत्र की दो लाइनें पढ़कर सुनाना चाहूँगा। इस पत्र में लिखा है :—

> I am glad to inform you that keeping in view the comprehensive functional coverage, simplicity, easy data entry protocol and userfriendly interface of the MIS developed by Haryana, it has been found to be most suitable and therefore, chosen as a model for replication in the entire country. We appreciate the efforts of your dedicated team reasponsible for evolving such a beautiful system code named "PASHUDHAN"

इस पत्र में भारत सरकार ने हरियाणा सरकार द्वारा पशुधन को बढ़ावा देने के लिए प्रशंसा की है। चौधरी देवी लाल जी की गऊओं के प्रति आस्था थी इसलिए माननीय मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनके निधन दिवस की पहली पुण्य तिथि पर कोई गाए भूख से या बीमारी से न मरे इन गऊशालाओं के इन्फ्रास्ट्रक्टर को मजबूत करने के लिए 51 हजार रुपये देने का काम किया है जो कि अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कार्य है।

तारांकित प्रश्न संख्या 1725

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री बन्ता राम सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Financial Assistance to Sarva Shiksha Abhiyan

***1757 Sh. Ramesh Khatak :** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether any financial assistance has been provided under "Sarva Shiksha Abhiyan" during the period from March, 2003 to date; if so, the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (चौ० बहादुर सिंह) : जी, हाँ। भारत सरकार ने वर्ष 2003-04 में सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के लिए 149.78 करोड़ रुपये की योजना अनुमोदित की है। इसमें से भारत सरकार परियोजना के लिए 112.31 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। भारत सरकार से अब तक 43.75 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है।

श्री रमेश कुमार खटक: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के लिए 43.75 करोड़ रुपए की राशि आई है, यह कैसे और कहां-कहां पर खर्च की गई है। इसके साथ ही पिछली सरकारों द्वारा इस योजना के लिए कितनी राशि दी गई थी ?

चौ० बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि सर्व शिक्षा

[चौ० बहादुर सिंह]

अभियान 2002-03 से लागू किए गए इस अभियान की निम्नलिखित उपलब्धियां हैं :—

2002-03 के अन्दर 83 प्राईमरी स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर के प्राथमिक स्कूल किया गया है, प्रत्येक 83 स्कूलों में दो-दो अध्यापकों के पद सृजित किए गए हैं। 126 प्राईमरी स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर राजकीय माध्यमिक स्कूल किया गया है और प्रत्येक स्कूल में दो-दो मास्टरों के पद सृजित किए गए हैं। कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने वाले 21,775 अध्यापकों को 500 रुपये प्रत्येक अध्यापक की दर से अध्यापक ग्रान्ट भी देने का काम किया गया है, इस पर 108.68 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 532 स्कूलों में 2000 प्रत्येक स्कूल के हिसाब से स्कूल सुधार के लिए ग्रान्ट दी गई है, इस बारे में 100.640 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसी तरह से 7848 स्कूलों में मरम्मत और रख-रखाव के लिए 5000 रुपये प्रति स्कूल की दर से ग्रान्ट दी गई है, इस बारे में टोटल 397.40 लाख रुपए खर्च किये गए हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्वयं शिक्षा का कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। रोहतक, गुड़गांव, पंचकूला इत्यादि चार जिलों में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है और कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने वाले अध्यापकों को 14-14- दिनों का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा प्राईमरी कक्षाओं के पाठ्यचार्य, रिविजन पर आधारित पाठ्य पुस्तकें विकसित करनी हैं। 176 प्राईमरी स्कूलों की ब्रांचों का दर्जा बढ़ाकर प्राथमिक पाठशालाएं बनाने का कार्य किया गया है तथा उन स्कूलों में अध्यापकों के पद सृजित करने हैं। 5000 रुपए प्रति स्कूल की दर से स्कूलों की मरम्मत तथा रख-रखाव ग्रान्ट, 2000 रुपए प्रति स्कूल के हिसाब से स्कूल ग्रान्ट तथा 500 रुपए प्रति अध्यापक के हिसाब से अध्यापक ग्रान्ट दी गई है। इस पर हमने 11 करोड़ रुपये की राशि व्यय की है। यह सर्व शिक्षा अभियान का वार्षिक कार्यक्रम है।

श्री नफे सिंह जुण्डला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो ब्लाक हैडक्वार्टर्ज में आफिसिज खोले गए हैं, उन पर पूरे हरियाणा में कितना खर्चा आया है और क्या सभी ब्लाक हैडक्वार्टर्ज की बिल्डिंगज बन कर तैयार हो गई हैं ?

चौ० बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, सभी ब्लाक हैडक्वार्टर्ज और सारे रिसोर्स सैन्टर्ज हैं, उनकी बिल्डिंगज अभी तैयार नहीं हुई हैं। हमारा प्रोग्राम 85 स्कूल भवनों को बनाने का है। 48 बी०आर०सी० सैन्टर्ज, 100 सी०आर०सी० सैन्टर्ज, 1284 अतिरिक्त कक्षा रूम, 2842 शौचालय बनाएंगे तथा इसके साथ ही 1595 पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने के बारे में भी निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए 47.95 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

श्री कंवर पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से क्या कुछ अध्यापकों की भर्ती हुई है और अगर हुई है तो कितने अध्यापकों की भर्ती हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि मेरे हल्के में कई ऐसे स्कूल हैं, जहां पर अभी भी कई-कई अध्यापक के पद खाली पड़े हुए हैं। छछरौली में 58 अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं, इसके अलावा एक और जगह पर 7 अध्यापकों के पद खाली पड़े हुए हैं। क्या मंत्री जी, जहां-जहां पर भी जो अध्यापकों के पद खाली पड़े हुए हैं, उन पदों को भरने का कष्ट करेंगे क्योंकि स्कूलों में अध्यापक न होने की वजह से बच्चों की एजुकेशन पर फर्क पड़ता है।

चौ० बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से यह कहना

चाहूँगा कि यह जो रिक्त पदों से सम्बन्धित प्रश्न इन्होंने पूछा है यह एक अलग प्रश्न है और ये इस बारे में अलग से डिटेल में लिखकर भेज दें तो हम इसका जवाब दे देंगे। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, मैं इनको यह भी बताना चाहूँगा कि जहां पर भी अध्यापकों के रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए प्रोसैस जारी है।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने सवालों का जवाब देते हुए सभी बातें विस्तार से बताई हैं। माननीय सदस्य कंवर पाल जी ने बहुत ही उचित सवाल पूछा है। अध्यक्ष महोदय, जब स्कूलों में शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चों की पढ़ाई सफ्फर करेगी। मुख्यमंत्री जी ने इस विषय में शिक्षा विभाग को कहा है कि जितने टीचर्ज की चाहे जे०बी०टी० की, मैथ, साईंस और दूसरे किन्ही भी सब्जैक्ट के टीचर्ज की पोस्टस खाली हैं, उनकी रिक्वीजिशन बना कर भेजें। अध्यक्ष महोदय, वह रिक्वीजिशन आ गई है और उसको रिक्रूटमैंट एजेंसी को भेजा जा चुका है। और जहां तक जे०बी०टी० की बात है, तो इनके लिए प्रोसैस ही नहीं बल्कि अब तो इंटरव्यू भी लिए जा चुके हैं और यह तो रिक्रूटिंग एजेंसी का काम है कि वह इनका रिजल्ट कब आउट करती है लेकिन सरकार की यह मंशा है कि रिक्रूटिंग एजेंसी इनका जल्दी से जल्दी रिजल्ट आउट करे। स्पीकर सर,जब यह चार हजार जे०बी०टी० टीचर्ज स्कूलों में लग जाएंगे तो इसके बाद किसी भी प्राईमरी लेवल के स्कूलों में कोई स्कूल ऐसा नहीं बचेगा जिसमें कोई टीचर्ज न हो। इसी तरह से जहां तक हायर क्लासिज के टीचर्ज की बात है, इनकी भर्ती भी रिक्रूटिंग एजेंसी के पास है और जब भी इनका रिजल्ट आ जाएगा तो सरकार इनको लगा देगी।

तारांकित प्रश्न संख्या 1709

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री राम भगत सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या 1737

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री भाग सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Upgradataion of Purchase Centre, Keorak

***1661. Shri Lila Ram :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Purchase Centre, Keorak in district Kaithal, if so, the time by which the said proposal is likely to be upgraded ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) : नहीं, श्रीमान् जी।

श्री लीला राम : अध्यक्ष महोदय, क्योड़क एक बहुत बड़ा गांव है और वह किसानों के लिए एक सैंटर प्लेस पड़ता है। इस गांव की अकेले की ही आबादी 25 हजार है तथा इसके साथ-साथ

[श्री लीला राम]

नोल, दयोरा, बलबन्ती, जसवन्ती, उझाना और बरोट गांव पड़ते हैं इसलिए अध्यक्ष महोदय, क्योड़क गांव एक सैंटर प्लेस में पड़ता है लेकिन वहां पर परचेज सैंटर बहुत ही छोटा है। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि कैथल जिला पूरे हरियाणा में फसल पैदा करने में शायद पहले या दूसरे नम्बर का जिला है। वहां पर जब फसलों को दोनों सीजन में जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि वहां पर किसानों की फसलें मिट्टी में या कच्ची जगहों पर पड़ी रहती हैं, इसलिए मेरा आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि क्या वहां पर परचेज सैंटर को अपग्रेड किया जाएगा?

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा मार्कीटिंग बोर्ड ने जहां कहीं भी मंडी बनानी है, परचेज सैंटर बनाना है या सब-यार्ड बनाना है तो इनके लिए कुछ नोर्म्ज तय किए हुए हैं। इन नोर्म्ज के तहत ही आज सारे हरियाणा प्रान्त में 106 मुख्य केन्द्र हैं, 178 सब-यार्ड हैं और लगभग 172 परचेज-सैंटर्ज हैं। सारे हरियाणा प्रान्त में किसी भी किसान को अपना अनाज बेचने के लिए 6 से 8 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा नहीं जाना पड़ता। जहां तक क्योड़क में परचेज सैंटर का दर्जा बढ़ाने की बात है, वहां क्योड़क गांव की गुमथला और सीवन से ज्यादा दूरी नहीं है जहां पर मुख्य मंडी बनी हुई है इसलिए क्योड़क में परचेज सैंटर का दर्जा बढ़ाना विचाराधीन नहीं है।

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि प्रदेश के अंदर जो सब-सैंटर्ज या सब-यार्ड हैं जिनकी अराईवल ज्यादा है क्या सरकार ने वहां का कोई सर्वे करवाया है कि जिनकी अराईवल ज्यादा है उनको अपग्रेड किया जाएगा क्या ऐसा कोई मामला सरकार के विचाराधीन है?

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, जहां कहीं से भी इस तरह की रिपोर्ट मिलती है और यदि वह नोर्म्ज के तहत मार्केटिंग बोर्ड की सारी शर्तें पूरा करता है तो हम बिना डिमांड के भी उनको अपग्रेड करने का काम करते हैं।

श्री बलवन्त सिंह साढौरा : अध्यक्ष महोदय, गांव रसूलपुर में दस या बारह गांवों को मिलाकर एक परचेंज सैंटर बना हुआ है, जमीन कम होने की वजह से जब सीजन में वहां पर फसल आती है तो वह खराब हो जाती है तो क्या वहां पर मंडी बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हम ऐग्जामिन करवा लेंगे।

Release of Funds from Local Area Development Fund

***1755. Sh. Rajinder Singh Bisla :** Will the Minister of State for Urban Development be pleased to state —

(a) whether there is a scheme of local area development fund with Government ; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to release / provide funds from local area development fund to the Municipal Corporation, Faridabad for the development works of the Corporation ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) :

(क) हाँ, श्रीमान जी।

(ख) सरकार द्वारा 80.00 लाख रुपये नगर निगम, फरीदाबाद को स्थानीय क्षेत्र विकास कर से निगम के विकास कार्यों हेतु राशि पहले ही रिलीज की जा चुकी है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जो ऑक्ट्रॉय समाप्त किया गया था उसके पश्चात् एल०ए०डी०टी० लगाया गया था उसके द्वारा 80 लाख रुपये की राशि एम०सी०एफ० को जारी की गई थी। एम०सी०एफ० की आबादी, वहां की इंडस्ट्रियल बैल्ट है, झुग्गियां हैं वहां की सारी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 80 लाख रुपये की राशि न के बराबर है। दूसरे 80 लाख रुपये की राशि जारी करने मात्र से ही समस्या का समाधान नहीं होता है क्योंकि वहां जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंटर है और जो चुने हुए लोग हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, वह पूरी तरह से पैरालाइज्ड है रोजाना अखबारों में आता है कि नगर निगम नगर निगम न होकर नरक निगम है पूरे नगर निगम के एरिया में सीवरेज चोक है, इस प्रकार के जहां हालात हों तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मंत्री जी वहां आकर अधिकारियों के साथ और चुने हुए लोगों के साथ जब तक परिवार के रूप में नहीं बैठेंगे और काम नहीं करेंगे तब तक आम आदमी को सुविधा नहीं मिलेगी। क्या मंत्री जी इस प्रकार का कोई आश्वासन देंगे ताकि समस्या का समाधान हो।

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने बताया है कि ऑक्ट्रॉय की समाप्ति के पश्चात् एल०ए०डी०टी० लगाया गया और उसके द्वारा यह राशि जो इनको रिलीज की गई वह बहुत कम है, मैं सम्मानित सदस्य को और सदन के समस्त सदस्यों को बताना चाहूँगा कि एल०ए०डी०टी० का प्रोसैस जब से हुआ इसके बारे में शुरू में अड़चनें आईं। अब वह अड़चनें दूर हो कर पैसा आना शुरू हुआ है। एल०ए०डी०टी० का मतलब है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डस्ट्री लगी हुई हैं और जो शहरी क्षेत्र में लगी हुई हैं उनके बारे में सरकारी तौर पर निर्णय लिया हुआ है कि इसके कलैक्शन का 5 परसेंट ऐक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट कलैक्ट करके उसके पश्चात् 65 और 35 की रेशो में 65 ग्रामीण क्षेत्रों में और 35 शहरी क्षेत्रों के लिए आबंटित किया जाएगा। जैसे-जैसे यह पैसा आ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 करोड़ रुपये की राशि सारे हरियाणा प्रदेश के लिए रिलीज की है उसमें 80 लाख रुपया आपके शहर के लिए आया है मार्च अप्रैल में और राशि मुख्यमंत्री जी द्वारा आबंटित कर दी जाएगी उसमें फरीदाबाद का शेयर भी दिया जाएगा। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि सीवरेज व्यवस्था चोक है अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी आपके रूबरू वहां के अधिकारियों से बात की थी उन्होंने मुझे चैक करके बताने के लिए कहा है। मैं जब भी स्वयं हो पाया वहां जाकर इनकी समस्या का समाधान करवाने का काम करूंगा।

चौ० राम फल कुण्डू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि कौन सी म्युनिसिपल कमेटी और कौन से नगर निगम को कितना पैसा देने जा रहे हैं।

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जो 30 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है, उसमें से यमुनानगर में 1 करोड़, नरवाना के लिए 75 लाख, अम्बाला सदर 45 लाख, नारायणगढ़ 10 लाख, भिवानी में 1 करोड़ 75 लाख, चरखी दादरी में 1 करोड़, बवानी खेड़ा व सिवानी में 75-75 लाख, फरीदाबाद में 80 लाख, पलवल में 65 लाख और फतेहाबाद में 75 लाख दिये हैं। रतिया में 60 लाख, टोहना में 50 लाख,

[श्री सुभाष गोयल]

गुड़गांव में एक करोड़, सोहना में 12 लाख, तावडू में 3 लाख, हांसी में 80 लाख, हिसार में 90 लाख, झज्जर में 30 लाख, नरवाना में 25 लाख, सफीदों में 30 लाख, पुण्डरी में 40 लाख, चीका में 10 लाख, कैथल में 90 लाख, इंदरी में 50 लाख, करनाल में 50 लाख, नीलोखेड़ी में 75 लाख, तरावड़ी में 40 लाख, घरोंड़ा में 15 लाख, थानेसर-लाडवा में 40 लाख, पेहवा में 15 लाख, शाहबाद में 8 लाख, नारनौल में 40 लाख, पंचकूला में 12 लाख, कलानौर में 50 लाख, महम में 50 लाख, रोहतक में 70 लाख, खरखौदा में 50 लाख, गोहाना में एक करोड़, सोनीपत में 90 लाख, गन्नौर में 20 लाख, जगाधरी में 50 लाख, कालांवाली में 160 लाख, सिरसा में दो करोड़, ऐलनाबाद में डेढ़ करोड़, रानिया में डेढ़ करोड़। इसी प्रकार से अब तक यह आबंटन 30 करोड़ रुपये है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जिन कमेटियों ने अपने प्रस्ताव और एस्टिमेट भेजे हैं उसके मुताबिक यह पैसा रिलीज कर दिया है। यदि किसी सदस्य को शंका हो कि हमारी कमेटी में पैसा नहीं भेजा गया तो जो कमेटियां जैसे अपना प्रस्ताव और जैसे एस्टिमेट भेजेंगी उनको पैसा भेज दिया जायेगा।

Widening of Roads

***1678. Shri Shashi Parmar :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to widen and strengthen the following roads :—

(i)	Rohtak	-	Bhiwani ;		
(ii)	Bhiwani	-	Meham	-	Gohana road ;
(iii)	Lohani	-	Bahal	-	Jhupa road ;
(iv)	Hansi	-	Bhiwani road ?		

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : हाँ, श्रीमान जी।

श्री शशि परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जहां हरियाणा प्रदेश में इतने नये रोड्ज बनाये गये हैं विशेष कर भिवानी जिले में जोकि 10-15 साल तक खत्म नहीं होंगे जिन पर 90 से 100 करोड़ रुपये लगाया है और कार्य अभी भी चल रहा है विशेषकर रोहतक से भिवानी रोड़, कोटपुतली से भिवानी रोड़, भिवानी से महम रोड, जींद से भिवानी रोड़। इन पर सरकार ने इतना पैसा खर्च किया है फिर भी कुछ हमारे जो छोटे-छोटे टुकड़े थे इनकी रिपेयर रह गई है विशेषकर बामला से रेवाड़ी खेड़ा, सै से चांग, भिवानी से तोशाम और साकरोड़ से कोंगट के बीच में छोटा सा टुकड़ा इनकी भी अगर रिपेयर हो जाये तो मैं सरकार का धन्यवादी हूँगा।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मेरे माननीय सदस्य ने पहले ही कह दिया कि सड़कों का बहुत अच्छा सुधार हुआ है। उन्होंने खुद माना है कि रोहतक से भिवानी सड़क पर काम प्रोग्रैस पर है। जो इन्होंने कुछ टुकड़े बताये हैं उन पर किसी टुकड़े की तो वाईडनिंग होनी है और किसी की स्ट्रैंग्थनिंग होनी है। कई जगह वाईडनिंग तो पूरी हो गई है और स्ट्रैंग्थनिंग पर कुल खर्चा 3 करोड़ 86 लाख रुपये खर्च होंगे और इसके लिए सी०आर०एफ० ने कुल छः करोड़ 49 लाख रुपये जारी कर दिये हैं। इसी प्रकार से भिवानी से महम रोड़ पर जो काम पूरा हुआ है उस पर 1 करोड़ 74 लाख 79

हजार रुपये खर्च हुआ है। इसी प्रकार से रोहतक से भिवानी की जो सड़क है उसका टैण्डर हो चुका है और उस पर कार्य चालू है, जिस पर 11 करोड़ 61 लाख रुपये खर्च होंगे। लोहारू से बहल तोशाम सड़क पर 88 लाख 55 हजार रुपये खर्च हुये हैं और कार्य पूरा हो गया है। इसी प्रकार से हांसी भिवानी रोड़ पर हुडको द्वारा 8 करोड़ 90 लाख रुपये खर्च होंगे। इस इलाके में जो काम होंगे जो हाई-वे के अपग्रेडेशन के फेज 3 और 4 में होगा जिस पर 183 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि सड़कों की मरम्मत, वाईडनिंग, स्ट्रैंथनिंग का काम जितना हरियाणा प्रदेश में हुआ है उतना सारे भारत वर्ष में कहीं पर नहीं हुआ और आज हरियाणा की सड़कों पर गाड़ियां 150 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कुछ विपक्ष के साथियों ने कहा कि इन सड़कों के काम का जो ठेका दिया जाता है वह सरकार अपनी मर्जी से दे रही है। शेर सिंह जैसे कई सदस्यों ने यह बात कही है। स्पीकर सर, हम टैण्डर की जानकारी वैब साईट और इंटर नैट पर देते हैं जिस पर दुनिया में कहीं भी बैठा आदमी वह साईट खोल सकता है चाहे वह बंगलौर में बैठा हो या हैदराबाद में वहां से अपना टैण्डर भेज सकता है। अच्छी गुणवत्ता के टैंडर लिए जाते हैं और अच्छी गुणवत्ता की सड़कें बनाई जाती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Construction of Roads

***1718 Shri Sher Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the roads in the following sectors :—

(i) Igrah to Buana to Boorader ;

(ii) Kharainty to Buana ;

(iii) Dhigana to Nandgarh ;

(iv) Behbalpur to Kinana ; and

(b) if so the, details there of ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : (क) तथा (ख) इगराह से बुआना से बुराडैहर तथा खरैन्टी से बुआना योजक सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव हैं। इस समय ढीगाना से नंदगढ़ तथा बेहबलपुर से किनाना योजक सड़कों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। इगराह से बुआना से बुराडैहर तथा खरैन्टी से बुआना योजक सड़कों को वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है।

Setting up of 33 KV Sub-station in Pathera and Seiang, District Mahendergarh

***1695 Rao Dan Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

[Rao Dan Singh]

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up 33KV Sub-Station in the villages Pathera and Selang in district Mahendergarh ; and

(b) if so, the time by which it is likely to be set up ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) तथा (ख) नहीं श्रीमान।

Recovery made by H.F.C.

***1734 Sh. Bhagi Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state the total amount recovered by the Haryana Financial Corporation from the Industrialists during the year 2003-2004 ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : मान्यवर, हरियाणा वित्त निगम ने वर्ष 2003-2004 में 11 फरवरी, 2004 तक 135.00 करोड़ रुपये की राशि उद्योगपतियों से वसूल की है।

Construction of Bye-Pass in Hathin

***1590. Shri Bhagwan Sahai Rawat :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct new bye-pass near Hathin in Hathin Constituency ; if so, the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : नहीं, श्रीमान जी।

Scheme for Sarva Shiksha Abhiyan

***1754. Sh. Ramesh Rana :** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any scheme namely 'Sarva Shiksha Abhiyan' in the State, if so, the aims and objects of the said scheme ?

शिक्षा राज्य मन्त्री (चौ० बहादुर सिंह) :

जी, हाँ।

इस अभियान के मूल उद्देश्य निम्नलिखित है :—

* सभी बच्चों के लिए वर्ष 2003 तक स्कूली शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना।

* सभी बच्चे वर्ष 2007 तक पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
* सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्ष की स्कूल शिक्षा पूरी कर लें।
* संतोषजनक कोटि की प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें जीवनोपयोगी शिक्षा को महत्व दिया गया हो, पर बल देना।
* स्त्री-पुरुष असमानता तथा सामाजिक वर्ग-भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा वर्ष 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करना।
* वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को स्कूल में बनाए रखना।

———

Reducing of the Stamp Duty in the State

***1748. Sh. Pawan Kumar Diwan :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to reduce the stamp duty in the State; if so, the time by which the said proposal is likely to be materialized ?

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : जी हाँ, इस हेतु भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) बिल 2004 चालू विधान सभा सत्र में विचारार्थ सचिव, विधान सभा को प्रस्तुत कर दिया गया है।

———

सर्व श्री रघुवीर सिंह कादियान तथा जय प्रकाश बरवाला, एम०एल०एज० के निलम्बन संबंधी सदन के निर्णय को रद्द करना

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के दो साथी निलम्बित हैं। मेरी आपसे और सरकार से प्रार्थना है कि यह आखिरी बजट अधिवेशन है कृपा करके उनको सदन में आने की इजाजत दी जाये।

श्री धर्मवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, दो दिन का अधिवेशन शेष बचा है और यह आखिरी बजट अधिवेशन है मेरी आपसे और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि हमारे निलम्बित दोनों साथियों को सदन में आने की इजाज़त दी जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आपकी तरफ से रिक्वैस्ट आ चुकी है, प्लीज आप बैठें।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विपक्ष के साथियों को बताना चाहूँगा कि यदि विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सरकार बे-लगाम हो जायेगी और विपक्ष तभी मजबूत हो सकता है जब वे आपस में साथ मिलकर चलें। लेकिन ये साथ मिलकर नहीं चल रहे, यह अच्छी बात नहीं है। हुड्डा साहब ने प्रार्थना कर दी लेकिन भजन लाल जी भी खड़े हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रजातान्त्रिक प्रणाली में हल्की क्रीटीसिजम अति आवश्यक है। मैं इस बात का पक्षधर हूँ और सदन के सभी सम्मानित सदस्य किसी भी मुद्दे को लेकर सरकार पर कटाक्ष कर सकते हैं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर सकते हैं और उत्तेजना में सरकार की बुराई भी कर सकते हैं तथा सभ्य लोग न हों तो असभ्य भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अधिकार सभी सदस्यों को हैं। लेकिन प्रजातांत्रिक प्रणाली में यदि सम्मानित चेयर की उपेक्षा होनी शुरू हो गई तो कंट्रोल होना संभव नहीं

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

होगा। आखिर एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में यदि हम अध्यक्ष महोदय की चेयर का सम्मान नहीं करेंगे तो यह सदन इस हिसाब से चलेगा जिस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, सदन में चर्चाएं चलती हैं और कई दफा ऐसी चर्चाएं आ जाती हैं जिन पर बोलना आवश्यक होता है। सदन के सभी सदस्यों को किसी भी प्रकार का प्रश्न करने का अधिकार है और ये प्रजातांत्रिक अधिकार है और ये इनकी उल्लंघना नहीं कर सकते। माननीय सदस्य द्वारा एक प्रश्न पूछा गया और प्रश्न का उत्तर देना सरकार की जिम्मेवारी है और उस प्रश्न का उत्तर सरकार की तरफ से दिया जा रहा था लेकिन बीच में ही विपक्ष के साथी इतने उत्तेजित हो गये कि उस मुद्दे को छोड़कर कहीं और बात करने लगे। सरकार का जवाब नहीं सुना गया। अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में महिलाओं को सम्मान प्रदान किया जाता है। यदि किसी महिला के खिलाफ किसी प्रकार की ज्यादती होती है और वह महिला सम्मानित सदस्यों से मिल करके, टैलीफोन पर बात करके, रोकर अपनी बात कहती है तो क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम उसको सद्भावना प्रदान करें और जो ज्यादती उस महिला पर हो रही है उसका समाधान करें? यदि वह मामला श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का पारिवारिक मामला था तो ये ही स्पष्टीकरण दे देते। इस बात पर इतने ज्यादा उत्तेजित होने की क्या जरूरत थी लेकिन विपक्ष के साथी उत्तेजित हो गये और इस प्रकार के शब्द अध्यक्ष के प्रति बयां किये गये जिन्हें मैं दोहरा नहीं सकता। सदन में माननीय सदस्यों का इस तरह का व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है। हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ द्वेष की भावना से कार्यवाही करने के पक्षधर नहीं हैं। चौधरी भजन लाल जी, आप और हम दोनों तो भुगतभोगी हैं। ऐसे-ऐसे स्पीकर चेयर पर बैठा करते थे जो अपोजीशन के लीडर को बिना किसी बात के सदन से निष्कासित कर देते थे। जब आपको और हमें बोलने तक का समय नहीं दिया जाता था। आपको स्पीकर साहब की सराहना करनी चाहिए और यह प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए कि मौजूदा विधान सभा के अध्यक्ष ने इस सम्मानित सदन के सदस्यों को बोलने के लिए पूरा समय दिया। आपको यह प्रस्ताव पास करना चाहिए। भजन लाल जी, आप असैम्बली की प्रोसीडिंग्ज उठा कर देखें, सभी सदस्यों को बोलने के लिए पूरा समय दिया जाता है। यहां तक कि आपकी पार्टी के सदस्यों को तो दूसरी बार बोलने के लिए कहा गया था और आपको भी कहा गया था कि आप और बोल लीजिए। आपकी पार्टी के लोगों को समय दिया जाता है लेकिन वे बाथरूम में घुस जाते हैं, फिर भी अध्यक्ष महोदय आपको पूरा समय देते हैं इसलिए उनका सम्मान और आदर करना हमारी भी तो जिम्मेदारी है इसलिए हम किसी दुर्भावना से नहीं कहते हैं। जिन सदस्यों को निष्कासित किया गया है विपक्ष के नेता से मैं यह कहूँगा कि वे सदस्य आ कर क्षमायाचना करें तो हम इस बात के पक्षधर हैं कि उन्हें वापिस बुला लिया जाए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि उनको बुला लिया जाए इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, वे लोग तो क्षमा याचना तभी करेंगे जब वे हाउस में आ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि अगर कोई ऐसी बात हुई है जिससे चेयर की गरिमा को ठेस पहुंची है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। आगे से हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की स्थिति पैदा न हो।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हुड्डा साहब, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने सदस्यों को कण्ट्रोल में रखें। (विघ्न) अगर कोई ऐसी बात होती है तो आखिर हम तो आप ही को कहेंगे और स्पीकर साहब भी आपसे ही कहेंगे। आपके सदस्य अगर आपकी बात नहीं मानते हैं तो फिर आपको इस पद पर नहीं रहना चाहिए। (विघ्न) ********

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जैसे ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं वैसे ही मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता भी हूँ।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : क्या आप खेद व्यक्त करते हैं ? आपके सदस्यों ने चेयर के प्रति जो अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए हैं क्या उनके लिए आप खेद व्यक्त करते हैं ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अगर किसी के दिल को ठेस लगी है तो ठीक है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हुड्डा साहब, यह मामला स्पीकर साहब से जुड़ा हुआ है और स्पीकर साहब से क्षमा मांगने में आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब से मैं यह कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी बात हुई है जिससे उनको ठेस लगी है तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आगे से आप यह कोशिश भी करें कि आपके सदस्य सीमा के अन्दर रहें। (विघ्न) हुड्डा साहब, क्या आप इस सदन को आश्वस्त करेंगे कि आगे से आप अपने सदस्यों को कण्ट्रोल में रखेंगे ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैं आगे इस बात का पूरा प्रयास करूंगा कि ऐसी स्थिति न आए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि विपक्ष के नेता ने कह दिया है कि वे अपना कर्त्तव्य और जिम्मेदारी निभाएंगे इसलिए दोनों सदस्यों को हाउस में बुला लिया जाए।

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will move a motion

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir I beg to move —

> That the decision of the House taken on the 11th February 2004, in respect of Sarvshri Raghuvir Singh Kadian and Jai Parkash Barwala suspending them for the remainder of the present session be rescinded.

Mr. Speaker : Motion moved —

> That the decision of the House taken on the 11th February, 2004 in respect of Sarvshri Raghuvir Singh Kadian and Jai Parkash Barwala suspending them for the remainder of the present session be rescinded.

Mr. Speaker : Question is —

> That the decision of the House taken on the 11th February, 2004 in respect of Sarvshri Raghuvir Singh Kadian and Jai Parkash Barwala suspending them for the remainder of the present session be rescinded.

The Motion was carried.

श्री अध्यक्ष : दोनों सदस्यों को सदन में आने की अनुमति प्रदान की जाती है।

———

राज्यपाल की ओर से संदेश

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a communication from His Excellency Babu Parmanand, Governor of Haryana on 13th February, 2004 which reads as under :—

"Dear Shri Kadian ji,

I have received your demi-official communication dated 11th February, 2004, No. HVS-LA-40/200/2232, alongwith a copy of "Motion of Thanks" passed by the Haryana Vidhan Sabha on my Address on 11th February, 2004.

Please do convey my profound appreciation and acknowledgement regarding the same to all the esteemed Members of the Haryana Vidhan Sabha.

With best wishes,"

On behalf of His Excellency, the Governor of Haryana, I thank all the Hon'ble Members of this House.

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं उनकी मांग है कि एच०सी०एस० की परीक्षाओं का माध्यम हिन्दी होना चाहिए। जब यू०पी०एस०सी० में परीक्षा का मीडियम हिन्दी हो सकता है तो फिर हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, यह डिसअलाउ कर दिया गया है अब आप बैठें। (विघ्न)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं पूरे हाउस को अवगत करवाना चाहूँगा कि सदन के दो सम्मानित सदस्य श्री धर्मबीर जी और श्री कर्ण सिंह दलाल जी मटका चौक पर कुछ बैनर्ज लगा कर आए थे और उन्हें उम्मीद थी कि वहां पर बहुत से स्टुडैंटस आएंगे और उनकी मौजूदगी में फोटो खिंचवाने के लिए बहुत ही सजधज कर गए थे लेकिन वहां पर एक भी व्यक्ति नहीं था। मैं इन सम्मानित सदस्यों को खासतौर पर कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस प्रकार के लोगों से हमदर्दी है और आप लोगों की मौजूदगी में फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो आज उसी मटका चौक पर एक महिला मुक्ति मोर्चा की तरफ से 25-30 महिलाएं धरने पर बैठी हैं, जिनमें श्री बी०एस० हुड्डा की पुत्रवधु और उसके मां बाप भी हैं और दूसरी महिलाएं भी हैं, वहां जाएं। वैसे तो मैं इस बात की चर्चा नहीं करना चाहता था क्योंकि यह उनका पारिवारिक मामला है और वह खुद इसका इलाज करें लेकिन पता नहीं घर की इस प्रकार की बातों को सदन के बीच में क्यों ले आते हैं ? अध्यक्ष महोदय, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। ये लोग वहां पर जा कर फोटो भी खिचवाएं और उनको सांत्वना भी दें। मैं विपक्ष के नेता से भी कहूँगा कि मिल बैठकर इस मसले को सुलझा लें चौधरी भजन लाल तो इस मामले में टंगली लगाएंगे ही। (हंसी)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमने पशुओं में मुँह-खुर की बीमारी के संबंध में एक कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया था उसका क्या फेट है ?

श्री अध्यक्ष : वह सोमवार के लिए ऐडमिट किया हुआ है इसलिए अभी आप बैठें। (विघ्न) कैप्टन साहब, अब आप अपना कॉलिंग अटैंशन नोटिस पढ़ें।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव —

हरियाणा राज्य में चिकित्सा उपचार के लिए शुल्कों के बढ़ाने सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice from Capt. Ajay Singh Yadav and two other M.L.As regarding increasing of charges for medical treatment in the State of Haryana. I Admit it. Capt. Ajay Singh Yadav may read his notice.

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने जनवरी, 2004 से आम आदमी के लिए अधिकतर स्वास्थ्य सेवाओं को निजी हाथों में सौंप कर गरीबों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को सस्ती व सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना प्रत्येक प्रजातांत्रिक सरकार का नैतिक दायित्व है परन्तु अब सरकार ने स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं का बाजारीकरण करके अपना दायित्व नहीं निभाया है। यूरोपियन कमीशन के एंजेन्डे के अधीन लागू नई दरें राज्य की 80% जनता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं तथा अब राज्य के सरकारी अस्पतालों में सस्ता व सुलभ इलाज करवाना एक सपना बन कर रह गया है। राज्य में अधिकांश सरकारी अस्पतालों में मामूली चीरफाड़ से ऑपरेशन तक मोटी फीस वसूली जा रही है। उपचार, स्वास्थ्य, जांच, एक्सरे तथा ऑपरेशन के लिए लागू नई दरों के लिए 100 रुपये से 1000 रुपये तक की फीस निर्धारित की गई है। उन्होंने आगे कहा है कि इनमें से अधिकांश सेवाएं पहले ही मरीजों को नि:शुल्क उपलब्ध होती थी। परामर्श के लिए 5 रुपये सरकारी फीस तथा बीमारियों के कई टैस्टों के लिए फीस राज्य सरकार द्वारा पहले ही वसूल करनी प्रारम्भ की जा चुकी थी। अब जनवरी से प्रसव ऑप्रेशन (सिजेरियन) के लिए फीस 1000 रुपये, गर्भाशय निकालने अथवा ऑप्रेशन के लिए फीस 1000 रुपये तथा पट से संबंधित ऑप्रेशन के लिए 500 रुपये लागू कर दी है। इसके अतिरिक्त मरीजों से पत्थरी, आंत, गुर्दे व गुर्दे की पत्थरी के ऑप्रेशन के लिए फीस 500 रुपये से 1000 रुपये तक निर्धारित कर दी गई है। टांके काटने के लिए फीस 50 रुपये तथा रक्त जांच व रक्त ग्रुप के लिए फीस 50 रुपये मरीजों को अदा करने पड़ेंगे। छात्रों तथा सरकारी कर्मचारियों को दाखिले तथा नियुक्ति के लिए चिकित्सा जांच के लिए क्रमश: एक सौ से दो सौ रुपये देने पड़ेंगे। आपात् स्थिति में या पी०जी०आई० में मरीजों को लाने के लिए प्रयोग की जाने वाली स्टाफ के साथ एम्बूलैंस 500 रुपये की अदायगी पर ही उपलब्ध हो सकेगी जबकि पहले यह सेवा नि:शुल्क थी। एक तरफ सरकार अस्पतालों में फीस में अप्रत्याशित बढ़ोतरी कर रही है दूसरी तरफ कैंसर, हृदय रोग, टी०बी० जैसी घातक बीमारियों की रोकथाम तथा उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों में कोई प्रबन्ध नहीं है। सरकारी अस्पतालों का कार्य केवल मैडीकल लीगल रिपोर्ट तैयार करना रह गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रजातन्त्र में अपने नागरिकों को सुलभ तथा सस्ता चिकित्सा उपचार उपलब्ध करवाना प्रत्येक सरकार का नैतिक कर्तव्य है। परन्तु वर्तमान सरकार स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं का व्यापारीकरण करके अपने दायित्वों से पल्ला झाड़ने का काम कर रही है। सरकार को सरकारी अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों के लिए एक जनवरी से लागू की गई फीस वृद्धि को तुरन्त वापिस

[कैप्टन अजय सिंह यादव]
लेकर अपना दायित्व निभाना चाहिए।

इसलिए, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचना के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

———

वक्तव्य—

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी स्वास्थ्य राज्य मंत्री द्वारा

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए अनेक नए कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए तथा इनमें कार्य कुशलता लाने के लिए निजी क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ है। इसका अर्थ यह नहीं है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी में आम जनता को सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा बल्कि इससे सरकारी अस्पतालों में कार्य कुशलता बढ़ेगी तथा बेहतर सुविधाएं कम दामों पर उपलब्ध होंगी। यह कहना गलत होगा कि सस्ता व सुलभ इलाज गरीब लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, फिलहाल जैसा कि सम्मानित सदस्य ने कहा है कि जनवरी, 2004 से प्राईवेटाईजेशन किया है तो मैं आपके माध्यम से इनको यह बताना चाहूँगा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, 3 सितम्बर, 2001 को चार्जिज की पैनोग्राफी की गई थी, उसके बाद हमने कोई वृद्धि नहीं की है। केवल मात्र करनाल स्वास्थ्य जिला अधिकारी ने 1-1-2004 को अपने सर्कुलर के माध्यम से कुछ चार्जिज बढ़ाए थे और 7-1-2004 को वह सर्कुलर वापिस ले लिया गया है। आज के समय में किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य सेवाओं का कोई व्यापारीकरण नहीं है, कोई निजीकरण नहीं है क्योंकि हमारी मान्यता है कि **''शरीरं आद्यं खलुधर्म साधनम्''**। यदि आप हरियाणावासियों के अपने धर्म का सही निर्वहन करवाना चाहते हैं, तो वो सही काम करें। अध्यक्ष महोदय, उनके स्वास्थ्य की जिम्मेवारी हमारा स्वास्थ्य विभाग लेता है ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। अध्यक्ष महोदय, पहली बार **''आपका स्वास्थ्य हमारा कर्त्तव्य''** के स्लोगन को साबित करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को हमने बेहतर बनाया है। उन्हें बेहतर बनाने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं वे इस प्रकार हैं, पहली बार 3 साल के अर्से के दौरान 388 नए डॉक्टरों की भर्ती करके अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दिया है। अध्यक्ष महोदय, गांवों में डॉक्टर्ज रहें, उनकी उपस्थिति को हमने एनश्योर करने के लिए कम्पयूटराईजेशन मोनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है। इसी प्रकार से दवाईयों की परचेज और वितरण की जो पॉलिसी थी, उसको हमने एक सही और नया रास्ता दिया है। अब हम जैनरिक दवाईयों की परचेज कर रहे हैं। पिछली सरकार के वक्त में जितने पैसे से जितनी दवाईयां ली जाती थी, अब उतने ही पैसे से दोगुणी दवाईयां खरीदी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग में 295 दवाईयों की सूची थी, उसमें से 181 तरह की दवाईयां आज पी०एच०सीज०, सी०एच०सीज० और हॉस्पिटलज् में उपलब्ध हैं। इस प्रकार से हमारी सरकार द्वारा लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। जो दवाईयां पहले बाहर दुकानों में बिकती थी उसको रोकथाम के लिए हमने स्टोर में डबल लॉक सिस्टम लगाया है। हमने दवाईयों की मोनिटरिंग का कम्पयूटराईजेशन किया है ताकि दवाईयों का सही उपयोग हो सके और जरूरतमंदों को दवाईयां मिल सकें। अध्यक्ष महोदय, आज से तीन साल पहले जो आंकड़ें मरीजों के थे, वे आंकड़े आज बढ़कर दोगुणे हो गए हैं। यह आंकड़े यह दर्शाते हैं कि हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं, लोगों को दवाईयां दी जा रही हैं और

लोगों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पिछली सरकार के वक्त में जो 21 पत्थर 10-10 साल पहले लगाए गए थे, इस सरकार के आने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 45 नए भवनों का उद्घाटन करके जनता को समर्पित किए हैं। इसके साथ मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग के 20 नए भवन निर्माणाधीन हैं, 34 भवनों की स्वीकृति आ चुकी है और आने वाले वित्तीय वर्ष में उनको तैयार करके जनता के स्वास्थ्य में सुधार के लिए जनता को समर्पित कर दिए जाएंगे। जहां तक मरम्मत का सवाल है तो पहले पी०डब्ल्यू०डी० और पब्लिक हैल्थ विभाग पर मरम्मत कार्य के लिए निर्भर करना पड़ता था, अब हमने इसके लिए अलग से 3 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है ताकि किसी भी प्रकार की रिपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं आए। हम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय एजैन्सियों से धन लेने के लिए प्रोजैक्ट प्रपोजल बना रहे हैं और उन्होंने वायदा किया है कि स्वास्थ्य सेवाओं के वर्धन के लिए हरियाणा को सुविधा दी जाएगी। पिछली बार जिस समय भारत सरकार के स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय की मीटिंग हुई थी तो वहां पर हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की सराहना की गई थी और दूसरों को अनुकरण करने के लिए कहा गया कि यदि आपने अनुकरण करना है तो हरियाणा स्वास्थ्य विभाग का अनुकरण करें।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं सदन में यह भी बताना चाहूँगा कि हमने एक नया पायलट प्रोजैक्ट 500 करोड़ रुपए का भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसको ठीक माना है और उसको भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को रिकमैंड किया है कि इस प्रोजैक्ट को वर्ल्ड बैंक के लिए रिकमैंड किया जाए ताकि हरियाणा में और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दी जा सके।

अध्यक्ष महोदय, यूरोपियन कमीशन की पहली बार 2001 में मीटिंग हुई थी। हिन्दुस्तान की सभी स्टेट्स ने उसमें भाग लिया था। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने अपना केस अच्छी तरह से प्लीड किया और पूरे हिन्दुस्तान में जब 21 जिलों को ग्रांट दी गयी तो इनमें हरियाणा के तीन जिलों को भी शामिल किया गया और इन तीन जिलों में करोड़ों रुपये की ग्रांट यूरोपियन कमीशन के तहत आयी। आज से 6 महीने पहले यूरोपियन कमीशन की टीम आयी और उन्होंने भी देखा की हरियाणा में सबसे बेहतर काम हुए हैं। मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही ये काम हुए। आज पूरे हरियाणा के 19 के 19 जिले यूरोपियन कमीशन में शामिल हो गये हैं। इसके अलावा जर्मनी को भी हमने 8 करोड़ रुपये का एक प्रोजैक्ट भेजा है और इसके लिए उनकी सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति आ गयी है। मार्केटिंग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वे हमें इसके तहत आठ करोड़ रुपये अलग से दे रहे हैं। इसी तरह से यू०एस०ए० आई०डी० पायलट प्रोजैक्ट भी अंतिम चरण में है, इस पर भी विचार किया जा रहा है, इसके तहत भी हमें पैसा मिलेगा। इसी तरह से हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए 407 करोड़ रुपये का बजट कल सदन में रखा है जोकि आपके सामने है। हर एक नागरिक पर 204 रुपये का जो खर्चा हम कर रहे हैं इतना खर्चा पूरे हिन्दुस्तान में किसी भी राज्य में नहीं किया जा रहा है लेकिन यह हरियाणा में किया जा रहा है। अभी पिछले 10-15 दिन पहले हमने मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर एक प्रोजैक्ट बनाया था जोकि इस तरह का पूरे हिन्दुस्तान में पहला प्रोजैक्ट है। शायद किसी ने इस बारे में सोचा नहीं था कि हरियाणा में इस तरह का प्रोजैक्ट बनेगा। जो आर०सी०एस० स्कीम पहले से चल रही थी वह रूरल एरिया के लिए ज्यादा थी। जो अर्बन एरियाज हैं और जो गरीब लोग अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, हमने उनके लिए भी प्रोजैक्ट बनाया है यदि वे गरीब लोग भी प्राईवेट नर्सिंग होम के डॉक्टर्ज से

[डॉ० एम०एल० रंगा]

दवाई लेते हैं तो इनकी किस प्रकार से मदद की जाए। इस तरह का हमने एक पायलट प्रोजैक्ट बनाकर भारत सरकार को भेजा कि जो गरीब लोग अर्बन एरियाज में रह रहें हैं वे प्राईवेट नर्सिंग होम के डॉक्टर्ज के पास जाकर कंसल्ट करके दवाई लें। अध्यक्ष महोदय, इसका यह पैसा भारत सरकार ने देना मंजूर कर लिया है। इसके तहत 12 करोड़ रुपये का हमारा प्रोजैक्ट मंजूर हुआ है। ऐसा प्रोजैक्ट पूरे हिन्दुस्तान में किसी भी स्टेट का नहीं हुआ है क्योंकि किसी भी स्टेट ने ऐसा प्रोजैक्ट सबमिट ही नहीं किया। इस प्रोजैक्ट के तहत एक नागरिक का एक डॉक्टर के लिए एक कार्ड बनेगा। यह कार्ड सौ रुपये का साल के लिए होगा। इसमें से उसको बीस रुपये की दवाई दी जाएगी और अस्सी रुपये के जो कंसलटेशन चार्जिज हैं वह सरकार प्राईवेट डॉक्टर्ज को देगी। एक योग्य प्राईवेट डॉक्टर जो नर्सिंग होम का होगा उसके पास 1500 परिवारों के कार्ड दिए जाएंगे। वह इन 1500 परिवारों के लिए ए०एन०एम० रखेगा। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने को यदि हमारे ये साथी प्राईवेटाईजेशन कहते हैं, निजीकरण कहते हैं या व्यापारीकरण कहते हैं तो ये सम्मानित सदन के साथी की भूल होगी क्योंकि हम तो केवल प्राईवेट डॉक्टर्ज की सहायता ले रहे हैं, प्राईवेट नर्सिंग होम्ज की सहायता ले रहे हैं और इससे कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ रहा है। जो थोड़ा सा वित्तीय बोझ है वह हरियाणा सरकार वहन कर रही है, भारत सरकार वहन कर रही है। इस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का यह एक अनूठा प्रयास होगा। 6 महीने के बाद जब हमारा यह प्रयास सफल होगा तो दूसरे जिलों के लिए भी 70 करोड़ रुपयों का प्रोजैक्ट मंजूर किया जाएगा जिससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हो पाएंगी। इसके साथ ही साथ आर०एन०टी०सी०पी० का प्रोग्राम सन् 2000 में केवल मात्र तीन जिलों के लिए टी०बी० का था। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय में जाकर लगातार तीन मीटिंग्ज की और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके आशीर्वाद से ही जो हरियाणा के 19 के 19 जिले हैं वह इस आर०एन०टी०सी०पी० में शामिल कर लिए गए हैं। एक करोड़ रुपये की दवाई और उपकरण हर जिले के लिए दिए जा रहे हैं। आज टी०बी० के मरीज को किसी के पास जाना नहीं पड़ता है क्योंकि हमारा स्वास्थ्य कर्मचारी टी०बी० की दवाई लेकर उसके घर पर जाता है और अपने सामने ही उसको डोज देता है ताकि वह कोई दवाई की डोज लेना भूल न जाए। इस तरह से हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि टी०बी० के लिए भी एक नया पैसा मरीज को अपनी जेब से न खर्च करना पड़े। इसी तरह से सम्मानित साथी ने कैंसर की बीमारी का जिक्र किया। पी०जी०आई० रोहतक में हमने करोड़ों रुपयों के उपकरण कैंसर डिपार्टमैंट के लिए खरीदे हैं तथा उस डिपार्टमैंट को लेटैस्ट इक्विपमैंट देकर हमने बेहतर सुविधाएं दी हैं जिसके बाद अब वहां पर कैंसर के मरीजों का उचित तरीके से इलाज किया जा रहा है। वहां ऑपरेशन किया जा रहा है। इसी प्रकार से पंचकूला के होस्पिटल के अंदर ओंकोलॉजी विंग भी हम तैयार कर रहे हैं जहां पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाएंगे ताकि कैंसर के पेसेंट यहां पर आकर अपना इलाज करवा सकें या थैरेपी ले सके। इसी तरह से गवर्नमैंट होस्पिटल, भिवानी में कोबाट थैरेपी यूनिट तैयार की जा रही है जहां पर कैंसर के मरीजों के लिए थैरेपी लगायी जाएगी। उनका इलाज किया जाएगा। हार्ट के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया। हार्ट के ऑपरेशन हरियाणा में पहली बार हुए हैं। वर्तमान सरकार के दौरान ही मेडीकल कालेज रोहतक में हार्ट के ऑपरेशन सफल रूप से हुए हैं। हमने उस डिपार्टमैंट को बेहतरीन सुविधाएं दी हैं। लेटैस्ट जो मशीन जापान और कनाडा की है वह हमने लाकर लगायी है। अढ़ाई करोड़ रुपये की स्पायरल सिटी स्कैन की मशीन जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी वह मेडीकल कालेज रोहतक के अंदर प्रदान की गयी है। सभी जिला

हैडक्वार्टर्ज के जितने हमारे अस्पताल हैं उनमें हमने कार्डियक मौनीटरिंग सिस्टम रखा हुआ है। ताकि तुरन्त रोग की पहचान की जा सके और पता लगाया जा सके कि हार्ट के पेशेन्ट को कितनी बीमारी है और उसका सही मात्रा में इलाज किया जा सके। कई बार चार्जेज लगाने की बात सदन में आई कि चार्जेज लगा दिए। हमने सितंबर, 2001 को पर्ची फीस लगानी शुरू की थी और पहली जनवरी, 2004 से केवल करनाल में छोटे-छोटे 2-4 चार्जेज और लगाए थे और वह भी 7 फरवरी, 2004 को विदड्रा कर लिए। हरियाणा प्रदेश के लोगों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पर्ची फीस में हमने जो छूट दी है वह इस प्रकार से है पी०एच०सी० और सी०एच०सी० जो हमारे सब सैण्टर्ज हैं उनमें कोई भी मरीज आएगा उससे अब कोई पर्ची फीस नहीं ली जाती है फैमिली प्लानिंग के कार्यक्रम और टी०बी० व ऐड्स के पेशेंट्स से कोई पर्ची फीस नहीं ली जाती है। मलेरिया, जापानी बुखार और डेंगू के मरीजों से कोई पर्ची फीस नहीं ली जाती है। कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके लिए कोई पर्ची फीस नहीं है। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कोई पर्ची फीस नहीं है, विपक्ष के साथी पता नहीं क्या बात करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 26 जनवरी को यह निर्णय भी लिया है कि स्वतंत्रता सेनानियों को उनके घर जाकर स्वास्थ्य सुविधायें मुहैया कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार उन लोगों को स्वास्थ्य सुविधायें दी जा रही है, जिनकी वजह से आज हम लोग आजाद भारत में आजादी की सांस ले रहे हैं, हमारी सरकार ने उनको क्रेडिट दिया है। 2-3 दिन से विकलांगों के बारे में सदन में विपक्ष द्वारा बातें की जा रही हैं, जिन विकलांगों की ये भाई बात करते हैं उन विकलांगों को भी हमने पर्ची फीस में छूट दी है इसके अलावा सीनियर सिटिजंस को छूट दी है। अनाथों के लिए, साधु संतों के लिए पर्ची फीस में छूट दी है, जो ऐक्सीडेंटल केस आ जाते हैं जिनके बारे में कोई अता पता नहीं होता है कि कौन कहां का है ऐसे में कोई फीस उनसे नहीं ली जाती है व उनका मुफ्त इलाज किया जाता है।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : कैप्टन साहब को पर्ची से कोई सरोकार नहीं है आप ये बताएं कि मैंटल केसिज में छूट दे रहे हैं या नहीं ?

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, यह प्वाइंट भी मैंने रखा हुआ था। पहली बार हरियाणा सरकार ने मैंटल होस्पिटल खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार को दिया है वह बहुत जल्दी ही मंजूर हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बीच में इंट्रप्ट न करें।

11.00 बजे

डॉ० एम०एल० रंगा : इसके साथ साथ मैं सम्मानित सदन के उन साथियों से निवेदन करूंगा जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ रहे थे तब हम बीच में नहीं बोले थे अब वे भी बीच में इंट्रप्ट न करें। मेरा जवाब सुनिए। जो भी सप्लीमैंट्री पूछी जाएगी उसका जवाब दिया जाएगा। जिस प्रकार से विपक्ष के साथियों ने बात की थी कि भर्तियों में फिटनेस के लिए जो फीस रखी हुई है। वह फीस 2001 में लगाई थी और क्लास फोर के इम्प्लाईज के लिए मात्र दस रुपये, क्लास थ्री के लिए 100 रुपये व क्लास-2 और क्लास-वन के लिए दो सौ रुपये फीस रखी हुई है। इसी तरह से ऐम्बुलैंस के लिए हमने 4 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्जेज रखे हुए हैं और उसमें हम बहुत सारी सुविधाएं भी देते हैं जैसे हमारी पैरा मैडीकल स्टाफ जाता है जिसमें एक अटैंडेंट, एक स्टाफ नर्स, एक हैल्पर और एक ड्राईवर जाता है चार आदमी जाते हैं और चार रुपये प्रति किलोमीटर खर्च है इतने स्टाफ के साथ ऐम्बुलैंस जाए तो यह खर्च ज्यादा नहीं है यह सब हमने मरीजों की सुविधा के लिए किया है। यमुनानगर जिले में एम्बुलैंस के लिए एक हजार रुपये का रेट फिक्स किया हुआ है चाहे वह

[डॉ० एम० एल० रंगा]

500 किलोमीटर के लिए जाए या 1000 किलोमीटर के लिए जाये, उसके लिए एक लिमिट रखी हुई है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसमें निजीकरण और व्यवसायीकरण नाम की कोई चीज नहीं है। पिछली बार कैप्टन साहब ने कहा था कि लोगों में आज तनाव है। आज 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत 40 हजार कार्य किए गये हैं इसलिए आज लोगों का तनाव खत्म हो गया है लेकिन विपक्ष को इस बात के लिए तनाव है कि इतने विकास के कार्य क्यों हुए हैं? हमने सभी अस्पतालों में और डिस्पैंसरियों में इक्विपमैंट और दवाइयों की सप्लाई करके सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को प्रदान की हैं, इसलिए आज किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। इसके लिए हमने नारा दिया है 'आपका स्वास्थ्य हमारा कर्त्तव्य' और इसके तहत हमने गरीब से गरीब आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की हैं और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग तत्पर है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि इन्होंने अपने जवाब में यह कहा है कि सरकार कैंसर और हार्ट पेशेन्ट का इलाज अपने आप करवा रही है। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या इसके लिए ट्रीटमैंट देने के लिए सरकार द्वारा डिस्ट्रिक्स लेवल पर कोई कैम्प लगाये जा रहे हैं? दूसरा, मैं यह जानना चाहूँगा कि जो मंत्री जी ने जवाब में बताया कि मेडीकल प्रोफैशन या इंजीनियरिंग प्रोफैशन के कालेजों में एडमिशन के समय जो टैस्ट लिये जाते हैं उनमें गरीब आदमी को एग्जैम्प्ट करने के लिए सरकार इस बिल में कोई एमेंडमैंट करने जा रही है, जिसके माध्यम से गरीब लोगों को कोई रिलीफ दिया जा सके क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनको इस प्रकार की सुविधा प्रदान की है। क्या हमारी सरकार भी इस प्रकार की सुविधा गरीब लोगों को देने जा रही है? मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार हैंडीकैप लोगों को इस प्रकार की सुविधा देने जा रही है।

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, कैंसर के बारे में वैसे तो मैं विस्तार से जानकारी दे चुका हूँ। हमारा मेडीकल कालेज रोहतक इसके लिए अति उपयुक्त है क्योंकि कैंसर का इलाज सस्ता नहीं है इसलिए जब भी हम कैंसर के पेशेन्ट डिटैक्शन के लिए स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करते हैं उस समय हम अच्छे फिजीशिएनंज को चण्डीगढ़ और दिल्ली से बुलाते हैं और स्वास्थ्य मेले के आयोजन के समय ही लोगों को चैक करते हैं और जो भी कैंसर के पेशेन्ट उस समय डिटैक्ट होते हैं उनका इलाज हम मुफ्त करते हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य मेले के आयोजन के समय अगर किसी भी रोगी को ऑपरेशन की जरूरत होती है तो उसका ऑपरेशन भी हम मुफ्त करते हैं किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता। यह इस सरकार की सोच है। आदरणीय चौधरी देवी लाल जी की यह सोच थी उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह 'स्वास्थ्य आपके द्वार' कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत हम स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कर रहे हैं। उस स्वास्थ्य मेले में जितने भी लोगों का चैक-अप किया जाता है उसमें चाहे कोई गरीब हो या अमीर उनका इलाज सरकार द्वारा मुफ्त किया जाता है। अब पिछले दिनों इस प्रकार का स्वास्थ्य मेला झज्जर में लगाया गया और वहां पर काफी लोगों को चैक किया गया, दवाई दी गई और जिनका ऑपरेशन करना था उनका ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर को 500 रुपये सर्जरी के लिए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। बुजुर्गों को फ्री ऐनक देने के लिए हमारी सरकार ने 1.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

श्री शादी लाल बत्रा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वास्थ्य नीतियों के बारे में विस्तार से

बताया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह प्रस्ताव करता हूँ कि यूरोपियन कमीशन के अंदर जो रेट लगाये हैं, क्या उन रेटों में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता? जहां तक मेरा विचार है इन रेटों के लगाने से सरकार को थोड़ा बहुत पैसा मिलता होगा यदि इन रेटस को हटा दिया जाये तो सरकार को वाह-वाही मिलेगी और लोगों को भी लाभ मिलेगा।

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदन के सदस्य को जानकारी देना चाहूँगा कि ये रेट हमने 2001 में लागू किए थे। उसके बाद कोई नया रेट लागू नहीं किया गया और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह निर्णय लिया कि इस तरह से जो भी पैसा आयेगा वह पैसा किसी सरकारी खजाने में जमा नहीं होगा। वह पैसा जिला स्वास्थ्य समितियों के पास रखा जायेगा जो गरीब लोगों की दवाईयों और उपकरणों पर खर्च किया जायेगा। यह राशि चार या पांच करोड़ रुपये के करीब है जो स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च की जायेगी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, शादी लाल बत्तरा जी बहुत ही सीनियर विधायक हैं। मैं इनको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कुछ मूलभूत जरुरयातें होती हैं जिनके लिए पैसा मायना नहीं रखता। हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक का स्वास्थ्य ठीक रहे। उसके लिए सरकार की तरफ से हर गांव में इस प्रकार के मैडीकल कैम्प लगाये जायेंगे जो स्कूली बच्चों का, आम नागरिकों का चैक-अप करेंगे और इन कैम्पों में अच्छे मैडीकल इक्वीपमैंट्स और डॉक्टर भी रहेंगे। सरकार के पास यदि डॉक्टरों की कमी आयेगी तो प्राईवेट डॉक्टरों से प्रार्थना करके उनसे सहायता ली जायेगी। पैसा अर्जित करने के लिए तो दूसरे महकमें भी हैं लेकिन स्वास्थ्य के लिए तो सरकार पैसा खर्च करेगी, इसमें पैसा नहीं कमायेगी। किसी भी देश की संस्कृति की पहचान वहां के लोगों के स्वास्थ्य से होती है। यदि निरोगी काया है तो सब कुछ है। कौन सा देश कितना मजबूत है, वह इसी बात से आंका जाता है कि उस देश के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो। स्वास्थ्य के बारे में हमने जो नीतियां बनाई हैं उनका दूसरे प्रदेशों द्वारा अनुसरण किया जा रहा है।

आई०जी० (रिटायर्ड) श्री शेर सिंह : स्पीकर सर, यह बिल्कुल सही बात है कि स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। सरकार उसकी तरफ ध्यान दे रही है लेकिन आमतौर पर जो लोग गांवों में रहते हैं वहां पर जो हैल्थ सैंटर हैं उनमें डॉक्टरों का अभाव रहता है। मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि जिन डॉक्टरों की पोस्टिंग गांव में है, क्या उनको सरकार की तरफ से कोई इनसैंटिव दिया जाता है? यदि नहीं दिया जाता तो कोई न कोई इनसैंटिव दिया जाना चाहिए ताकि डॉक्टर गांव में रहकर लोगों की सेवा कर सकें। अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आज के दिन हरियाणा में लिंग अनुपात में बहुत अन्तर है। 1000 लड़के के पीछे 861 लड़कियां हैं जिसकी तरफ सबको गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यदि यह अनुपात इसी तरह बढ़ता रहा तो आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि आने वाले समय में क्या हालत हो जायेगी। सरकार ने अल्ट्रासाउंड पर बैन लगा दिया है लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस बारे और कोई सार्थक कार्यवाही कर रही है और कर रही है तो कब तक की जायेगी? वरना आगे सोशल स्ट्रक्चर गड़बड़ा जायेगा। अन्त में मेरा सरकार से यही कहना है कि यदि लड़के और लड़की के अन्तर को दूर करने का प्रयत्न नहीं किया गया तो आगे चल कर यह समस्या एक सोशल इविल का रूप धारण कर लेगी, इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा तुरन्त कदम उठाये जायें ताकि आगे चल कर हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, धन्यवाद।

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मेरे सम्मानित सदस्य ने अच्छे सवाल रखे। इनके मुख्य दो सवाल रहे हैं। एक सवाल यह रहा है कि हमारे यहां पर जितनी भी पी०एच०सीज० या सी० एच०सीज० हैं उनमें डॉक्टर बहुत कम रहते हैं। इस बारे में मैं सदन की जानकारी व सदस्य महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने पहली बार डॉक्टरों की भर्ती करके जितने डाक्टरों के खाली पद थे वे भरे हैं। सरकार द्वारा अब तक 388 डॉक्टर्ज की नियुक्ति की जा चुकी है और 70 डाक्टर्ज लगाये जाने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रकार कुल 458 नये डॉक्टर्ज मौजूदा सरकार द्वारा लगाये जा सकेंगे। इसी प्रकार से ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने 80 आयुर्वेदिक डॉक्टर्ज भर्ती किए हैं और 50 और डॉक्टर्ज की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। अब तक सरकार द्वारा 21 एस०एम० ओज० लगाए जा चुके हैं और 17 एस०एम०ओज० लगाये जाने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक डॉक्टर्ज लगाने जा रही है ताकि लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके। मौजूदा सरकार द्वारा नये डॉक्टर्ज की नियुक्ति में यह पहली बार कन्डीशन लगायी है कि उन्हें कम से कम 3 साल तक गांवों में सेवा करनी अनिवार्य होगी ताकि वे गांव में रहकर लोगों की सेवा कर सकें। दूसरा सवाल मेरे साथी ने लिंग अनुपात का उठाया है। आज के समय में हरियाणा में 1000 लड़कों के पीछे 861 लड़कियां हैं। सरकार ने लिंग अनुपात को दूर करने के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं। इनमें एक योजना 'देवी रुपक' के नाम से शुरू की गई है। सरकार ने योजनाएं शुरू करके यह प्रयास किया है कि यह अनुपात और अधिक न बढ़े इसके लिए देवी रुपक योजना के तहत तीन काम किए जा रहे हैं। एक तो इससे जनसंख्या नियंत्रण को बढाया जा सके, दूसरे भ्रूण हत्या को रोका जा सकेगा और तीसरे लिंग अनुपात को रोकने में यह योजना लाभदायक काम कर रही है। स्पीकर साहब, इस योजना के तहत यदि पहली लड़की होने पर कोई दम्पत्ति परिवार नियोजन को अपनाता है तो उसको हर महीने की पहली तरीख को 20 सालों तक 500 रुपये प्रति मास मिला करेंगे और यदि कोई दम्पत्ति पहला लड़का होने पर परिवार नियोजन को अपनाता है तो उसको भी पहली तारीख को 20 सालों तक 200 रुपये प्रतिमास मिला करेंगे। सरकार की इस योजना से एक तो भ्रूण हत्या को रोकने में मदद मिलेगी दूसरे लड़कियों को बढ़ावा इस 'देवी रुपक' स्कीम से मिलेगा। इसी प्रकार से हमने 5100 रुपये की राशि कन्यादान के नाम से देनी शुरू की हुई है। पहले यह राशि केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ही दी जाती थी, लेकिन अब सरकार इसको अन्य जातियों तक बढ़ाने बारे विचार कर रही है। इसी प्रकार से सरकार लड़कियों को मुफ्त शिक्षा सुविधाएं दे रही है ताकि लड़कियां अधिक से अधिक पढ़-लिख सकें। इसी प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार महिलाओं की हर मामले में 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में जब तक हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वे समाज में जा करके यह प्रचार नहीं करेंगे कि लड़के और लड़की बराबर हैं और दोनों को समान समझना चाहिए, तब तक हम उतने कामयाब नहीं होंगे जितना हम होना चाहते हैं। सरकार तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखेगी लेकिन हमारे जन प्रतिनिधियों जिनमें हम सभी विधायक हैं, या जिला परिषद, ब्लॉक समिति या पंचायत के सदस्य हैं, वे प्रचार नहीं करेंगे कि लड़के और लड़की बराबर हैं तब तक हम इस मामले में ठोस प्रगति नहीं कर पाएंगे। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि सरकार ने भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। हमारी सरकार ने 758 अल्ट्रासाउंड मशीनों को रजिस्टर किया है। बिना रजिस्ट्र हुए अल्ट्रासाउंड मशीन वालों के खिलाफ हमनें 21 केस दर्ज किए हैं। इस बारे में आज तक हरियाणा प्रदेश के अलावा देश के किसी भी अन्य प्रदेश में ऐसा केस कोर्ट में किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं किया गया है। जो अबोर्शन करवाता है वह नहीं बताएगा

और न ही करने वाला बतायेगा। जो व्यक्ति साथ जाता है वह भी नहीं बताएगा कि फलां से हमने अबोर्शन करवाया है। इस बारे में तो हमारे समाज के सभी व्यक्तियों की बराबर की जिम्मेदारी बनती है कि जिस किसी व्यक्ति को भी इस बारे में पता चलता है तो वह हमारे नोटिस में यह बात लाये ताकि उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। अब हम इस मामले में यह भी करने जा रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में पता लगता है तो उसकी सूचना वह संबंधित सिविल सर्जन को देगा तो उसका नाम गुप्त रखा जायेगा और उस व्यक्ति को ईनाम भी दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि भ्रूण हत्या जैसे पाप को रोका जा सके। हमारी सरकार समझती है कि लड़कियों को मारना सबसे ज्यादा पाप है। इसलिए मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि सभी साथी और समाज के मान्य व्यक्ति इस 'देवी रुपक' योजना में बराबर का अपना सहयोग दें ताकि लिंग अनुपात को ठीक किया जा सके।

———

सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to lay on the Table—

The Audit Report on the accounts of the Haryana Prathmik Shiksha Pariyojna Parishad for the year 2000-2001, as required under rule 9.9 of D.P.E.P. Manual of Administration.

The Annual Report of the Haryana Electricity Regulatory Commission for the year 2001-2002, as required under sub-para (5) of para II of the Schedule appended with the Haryana Electricity Reform Act, 1998 and section 105 (2) of the Electricity Act, 2003.

The 36th Annual Report & Accounts of the Haryana Agro Industries Corporation Limited for the year 2002-2003, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of the Haryana State Pollution Control Board for the year 2001-2002, as required under section 39 (2) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2003 (Commercial) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Finance Accounts of the Government of Haryana for the year 2002-2003 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Appropriation Accounts of the Government of Haryana for the year 2002-2003 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March 2003 (Civil) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

[Prof. Sampat Singh]

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2003 (Revenue Receipts) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

वर्ष 2004-05 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now general discussion on the Budget Estimates for the year 2004-05, will take place. माननीय सदस्यगण, लीडर ऑफ दि ओपोजीशन की तरफ से बजट पर बोलने के लिए कुछ नाम आए हैं। आज पूरा दिन बजट पर बहस होगी और हर माननीय सदस्य को लगभग 5 मिनट का समय बोलने के लिए आता है। माननीय सदस्यों से विनती है कि अपनी-अपनी पार्टी स्ट्रैंथ के अनुसार वे बोल सकते हैं। दूसरी बात, यह है कि दिनांक 16.02.2004 को माननीय वित्त मंत्री जी का रिप्लाई होगा। अतः सभी सदस्यगण विशेषकर कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो बोलना चाहते हैं वे आज ही बोल लें ताकि ऐसी स्थिति पैदा न हो जैसे कि महामहिम राज्यपाल महोदय के रिप्लाई के समय पर हुई थी। इस स्थिति को क्लीयर करते हुए मैं फिर यह विनती करता हूँ कि सभी माननीय सदस्य जो बोलना चाहते हैं वे आज ही बोल लें और सदन चलता रहेगा (विघ्न) मैं अब श्री भूपेन्द्र सिंह जी को बजट पर बहस के लिए आमन्त्रित करता हूँ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बी०ए०सी० की बैठक में बजट पर बहस के लिए दो दिन रखे गए थे इसलिए मैं यह निवेदन करता हूँ कि हमारे जो साथी बोलने से रह जाएंगे वे 16 तारीख को बोल सकते हैं और डिस्कशन कान्टीन्यू कर सकते हैं उसके बाद 16 तारीख को ही वित्त मंत्री जी का जवाब भी आ जाएगा।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : हुड्डा साहब, आज का दिन आप जितनी देर चाहें बोलें अगर जरूरत हुई तो रात के दस बजे तक भी हाउस चलाया जा सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : आप बी०ए०सी० की प्रोसीडिंगज़ निकलवा कर देख लें। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : प्रोसीडिंग्ज़ तो यहीं पर है । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : बी०ए०सी० में जो कुछ फैसला होता है उसके अनुसार ही तो हाउस की कार्यवाही चलती है।

प्रो० सम्पत सिंह : जब गवर्नर ऐड्रैस शुरू हुआ था तो आखिर में आप यह कह कर चले गए थे कि हम नहीं बोलेंगे। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : बजट पर डिस्कशन शुरू हो रही है और वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि जिसने बोलना है वह आज ही बोल लें। 16 तारीख को भी हाउस चलेगा और जो लोग आज नहीं बोल पाएंगे वे 16 तारीख को बोल सकते हैं (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : 16 तारीख को तो वित्त मंत्री जी जवाब देंगे।

चौधरी भजन लाल : क्या वित्त मंत्री जी अकेले ही बोलेंगे?

श्री अध्यक्ष : मंत्री तो अकेले ही बोलते हैं, क्या दो-दो मंत्री इकट्ठे बोलेंगे? (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : हमारे कुछ माननीय सदस्य आज बोलेंगे और जो रह जाएंगे वे 16 तारीख को बोल लेंगे। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : चौधरी भजन लाल जी, अध्यक्ष महोदय, ने बड़ी फ्राखदिली दिखा कर यह कहा है कि आप इस बजट पर जितनी भी चर्चा करना चाहते हैं खुल कर करें लेकिन 16 तारीख को रिप्लाई आना है और आज का दिन बोलने के लिए काफी है। आप चाहे कितना भी बोलें, छिक कर बोलें। आपको यहां तक छूट है कि ट्रेजरी बैंचिज़ की तरफ से कोई नहीं बोलेगा। विपक्ष के नेता बोलेंगे और मैं अपने सभी सम्मानित सदस्यों से कहूँगा कि वे कोई टोकाटाकी न करें। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : (किलोई) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने वर्ष 2004-05 का और अपनी सरकार का पांचवा बजट पेश किया है मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि यह बजट बड़ा डिसएप्वायंटिंग, नीरस, निराशाजनक और क्लरलैस है। हमारे वित्त मंत्री साहब बहुत काबिल मंत्री हैं और पहले भी चार बजट प्रस्तुत कर चुके हैं। मैंने इनकी हर बजट स्पीच सुनी है, इनको आंकड़ों की काफी अच्छी जादूगरी आती है। इस बजट में लिपसर्विस की कोशिश भी पूरी तरह से नहीं कर सके। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)** इसका निष्कर्ष यह है कि काम करो या काम न करो, काम न करो तो चिन्ता करो, अगर चिन्ता नहीं करो तो चर्चा करो। अब की बार तो चिन्ता भी नहीं हुई और न ही चर्चा हुई। अब की बार जो बजट है, इसमें किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और कर्मचारियों के हित की कोई भी स्कीम नहीं है। इस बजट को आंकने के बाद मैं सबसे पहले फाईनैंशियल स्थिति क्या है उसके बारे में यहां पर चर्चा करना चाहूँगा कि हम किस ओर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं, आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है और किस प्रकार से आज हम कर्जे में डूबे जा रहे हैं। अगर इस प्रकार के बजट आते रहे तो प्रो० सम्पत सिंह जी आने वाले दो तीन सालों के बाद बजट प्रस्तुत करने की जरूरत ही नहीं रहेगी क्योंकि इसके अन्दर कोई प्लान ही नहीं रहे हैं। आज कर्जे में और उसके ब्याज के भुगतान में और सरकारी तनख्वाह में खजाना खाली होता जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, 2000-2001 का प्लॉन आउटले 1718 करोड़ रुपए का था जो कि 23 प्रतिशत बनता है और नॉन-प्लॉन का आउटले 76.06 करोड़ रुपए का था। इसके बाद जो हम 2003-04 तक पहुंचे तो उसमें नॉन प्लॉन 87.57 करोड़ रुपए का हो गया और प्लॉन 16.43 करोड़ का हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्लान बजट 2175 करोड़ रुपए का रखा गया है, जब से यह सरकार आई है, तब से इन्फलेशन लगाएं तो यह असल भाषमे में प्लान्ड बजट घटकर 1300 करोड़ रुपए ही गया है। उपाध्यक्ष महोदय, हर प्लान्ड बजट में कमी आ रही है और जबकि हमारी देनदारियां बढ़ रही है। आज पूरा प्रदेश 33,000 करोड़ रुपए के कर्जे में डूबा हुआ है और इसमें डैट तथा गारन्टीज की ग्रान्ट हैं। आज हरियाणा प्रदेश को 9 करोड़ 52 लाख रुपया प्रति दिन कर्जा लेना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश का हर व्यक्ति जो पैदा होता है तो वह 12-15 हजार रुपए का कर्जा लेकर पैदा होता है। आज हर व्यक्ति पर 4.51 रुपए रोज कर्जा बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही कर्जा बढ़ता रहा तो हमारा क्या होगा? यह आप समझ सकते हैं, प्रदेश में रेशो ऑफ लॉयब्लिटी टू

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

जी०डी०पी० 50 प्रतिशत है और डैट सर्विस रेशो 45 प्रतिशत है। उपाध्यक्ष महोदय, 1999-2000 में रिपेमैन्ट 997 करोड़ रुपए की गई थी, जबकि यह 2004-05 में 2488 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। उस समय इन्ट्रस्ट रेट 11 प्रतिशत था, आज यह घटकर 6 प्रतिशत हो गया है और इसी हिसाब से इनको पैसा मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि ब्याज का भुगतान 2488 करोड़ रुपए प्रस्तावित है और विकास का खर्च बजट प्लान में 2175 करोड़ रुपए का है। हम जो ब्याज दे रहे हैं वह प्लान से ज्यादा दे रहे हैं। ऐसे में हम आज प्रदेश को कहां पर ले जा रहें हैं? उपाध्यक्ष महोदय, हमारी मुख्य समस्या बेरोजगारी की है, अब मैं बेरोजगारी के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। 1998 में कर्मचारियों की संख्या 4 लाख 24 हजार 918 थी और 2002 में घटकर 4,10,011 हो गयी है, यह इकोनोमिक सर्वे आफ इण्डिया में अंकित किया हुआ है। यानि की लगभग 15000 नौकरियां 2002 तक घटा दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, अब पब्लिक अंडरटेकिंग्ज और गवर्नमैंट सैक्टर्ज में से भी 30 हजार कर्मचारियों को हटा दिया गया है। यह फिगर तो मैंने सरकारी बताए हैं। इसके अलावा इन्ट्रस्ट्रीज का रैवेन्यू भी घटा है और इन्डस्ट्रीज में भी नौकरियां नहीं मिलती हैं। उसमें भी बेरोजगारी बढ़ी है यह ठीक है कि सभी बच्चों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती हैं। हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान देश है। मैं यहां पर रोजगार से सम्बन्धित बात कहना चाहता हूँ, जिस बारे में वे सदन में बार-बार कहते हैं, इम्पलायमैंट जनरेशन की बात कहते हैं। यहां पर ये कहते हैं कि 1997-98 में हरियाणा में 78847 उद्योग काम कर रहे थे। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि 2003 में इन उद्योगों की संख्या घटकर 64314 रह गयी है इसका मतलब 14533 उद्योग हमारे कम हुए हैं और यदि हर उद्योग में 15-20 व्यक्ति भी नौकरी करते हों तो इसका मतलब 1997-98 में जो काम करते थे उनमें से आज तक कम से कम दो लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। यह सरकार आने के बाद अढ़ाई लाख व्यक्ति को बेरोजगार कर चुकी है उनको रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। दिसम्बर, 2000 में रोजगार दफ्तरों में 6,63,775 बेरोजगार लोगों के नाम इंगित कर रखे थे जो दिसम्बर 2002, में बढ़कर 8,02,581 हो गये। उपाध्यक्ष जी, इनके अलावा भी कितने और ऐसे बेरोजगार लोग हैं जो रोजगार दफ्तरों में अपना नाम नहीं दर्ज करवा पाते हैं। इस तरह से आज जो बेरोजगारी बढ़ रही है यह आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रही है। इनके चार बजट मैंने भी पढ़े हैं, लेकिन पहली बार हमने यह देखा है कि इकोनोमिक सर्वे में अनएम्पलायमैंट का चैप्टर ही अंकित नहीं किया गया है। जहां तक बिजली की बात है। बिजली के बड़े गुणगान हो रहे हैं। प्रयास भी सरकार ने किए होंगे और हो सकता है कि बिजली की जैनरेशन भी बढ़ी हो लेकिन आप किसी भी गांव में जाओ वहां पर आपको पता लगेगा कि कितने दिन का कट है, कितने दिन बिजली प्राप्त होती है। यहां पर सभी साथियों ने इस बारे में चर्चा भी की। आज हमारे पड़ोसी प्रदेश पंजाब के ट्रांसमिशन लौसिज 17 परसेंट है और हमारे ट्रांसमिशन लौसिज चालीस परसेंट से ज्यादा हैं इसका मतलब 3574 करोड़ रुपया हमें वहां ज्यादा पड़ रहा है और वह सरकार को वहन करना पड़ रहा है। इस तरह से यह तो बिजली की स्थिति है। 1998-99 में ट्रांसमिशन लौसिज 32.56 परसेंट थे और आज वे चालीस के करीब टच कर गये हैं जबकि नोर्मज 15 परसैंट है। इसी तरह से ट्यूबवैल्ज के कनैक्शंज देने की बात कही गयी। ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन देने के बारे में मुख्यमंत्री जी ने भी, वित्त मंत्री जी ने भी और सरकार के दूसरे मंत्रियों ने भी बड़े जोर-शोर से कहा कि हमारी सरकार आने के बाद 36 हजार ट्यूबवैल्ज के नये कनैक्शंज दिये गये हैं। उपाध्यक्ष जी, कितने गुमराह करने वाले आकंड़े हमारे वित्त मंत्री जी दे रहे हैं। 2003-2004 के इकोनोमिक सर्वे के पेज पर आप देखेंगे कि प्रदेश में केवल 3,61,454 ट्यूबवैल्ज सिंचाई कर रहे

थे और 31 मार्च, 2003 तक ट्यूबवैल्ज की संख्या 3,89,099 है इसका मतलब हुआ कि गत चार वर्षों में केवल मात्र 17,645 ट्यूबवैल्ज के कनैक्शंज इन्होंने दिए हैं। अब इसमें एक बात है या तो सरकार ने 18,355 कनैक्शंज कटवाकर दोबारा से दिये हैं या फिर 36 हजार के आंकड़े गुमराह करने के लिए दिए हैं। यह आंकड़े हमारे वित्त मंत्री जी ने बड़े जोर शोर से बताएं हैं। इसी तरह से सड़कों की भी यहां पर बड़ी चर्चा हुई है। सत्ता पक्ष का हर व्यक्ति सड़कों की बड़ी चर्चा करता है, यह बात ठीक है कि कई जगहों पर सड़कें बनी हुई हैं लेकिन बहुत सारी जगहों पर टूटी भी पड़ी हैं। सरकार के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की वजह से सरकार को काफी नुकसान वहन करना पड़ा है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से 690 करोड़ रुपये ऋण देना प्रस्तावित है जिसमें 295 करोड़ रुपये केन्द्र से ग्रांट के तौर पर मिलने थे और इसके लिए दस करोड़ रुपये कंसलटैन्सी चार्जिज भी गवर्नमैंट ऑफ हरियाणा ने दे दिए थे। यह ऋण 5.5 परसेंट इंट्रस्ट पर मिल रहा था और 20 साल में वापस करना था लेकिन अगस्त 2000 में इस अहम् प्रोजैक्ट को बंद कर दिया गया क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा सकी और उसका नतीजा क्या हुआ कि दस करोड़ जो कंस्लटैंसी के होते थे वह तो गए और जो इन्होंने हुडको से 137.25 करोड़ का लोन लिया वह 13.5 परसेंट इंट्रस्ट पर लिया कहां 5.5 पर मिल रहा था और शर्त यह भी है कि 10 साल में पैसा वापस करना पड़ेगा इससे प्रदेश को कितना नुकसान वहन करना पड़ेगा इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में कहना चाहूँगा। यह बात ठीक है कि आप नयी बसें लाए हैं जनसुविधा चाहिए लेकिन पंजाब के साथ ट्रांसपोर्ट महकमें का जो रोड का ऐग्रीमैंट है वह 10.50 लाख रुपये का टैक्स दिया है और इस विषय में किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 9.13 लाख देना बनता था, इससे लगभग डेढ़ करोड़ रुपये का प्रदेश के ट्रांसपोर्ट को नुकसान हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डीज़ल की खपत के बारे में कहना चाहूँगा। डीजल की खपत 2 परसेंट होनी चाहिए जबकि 8-9 डिपोज़ में यह 2.26 परसेंट से लेकर 4.39 तक है इससे भी ट्रांसपोर्ट विभाग को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। वैट के बारे में हमारी पार्टी ने बड़े जोर-शोर से कहा था कि यह प्रदेश के हित में नहीं। अकेले हरियाणा प्रदेश में यह टैक्स न लगाया जाए तो वित्त मंत्री ने इसकी बड़ी भारी वकालत की थी। वह वैल्यू ऐडेड टैक्स न होकर वैरी ऐडेड ट्रबल है। यह जो कहा गया है कि वैट से 318 करोड़ रुपये अतिरिक्त खजाने में आए हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पहले सेल्स टैक्स की आमदनी में हर साल पन्द्रह प्रतिशत का इजाफा होता था इस बार भी इजाफा उतना ही है। इस प्रदेश का किसान जो केवल धान पैदा करता है, उसको कितना नुकसान हुआ है, 37 लाख मीट्रिक टन प्रदेश में कुल धान पैदा हुआ है। उसमें से 9 लाख मीट्रिक टन बासमती निकली है। आज आप पंजाब में जाकर पता करें पंजाब के किसान को 1300 रुपये प्रति क्विंटल धान का रेट मिला है और हरियाणा के किसान को 1100 रुपये प्रति क्विंटल धान का रेट मिला है इसका मतलब हरियाणा के किसान को 1800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और जो शैलर वाले थे, जो चावल बनाते थे। दिल्ली के नजदीक होने के कारण हमारे शैलर वालों को हमेशा पंजाब से फालतू पैसा मिलता था लेकिन इस बार कम पैसा मिला है लगभग 700 करोड़ रुपये का शैलर वालों को नुकसान हुआ है और व्यापारियों को भी अलग से नुकसान हुआ है। टैक्स कलैक्शन की बात मैंने कही। 2001-02 में 371 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी और 2002-03 में 356 करोड़ की वृद्धि हुई। इसी प्रकार से वर्ष 2003-04 में 358 करोड़ रुपये की वृद्धि आपने वैट से की है। यह वृद्धि तो वैसे भी होनी थी। वैट लगाने की बात से मैं सहमत नहीं हूँ और मेरा सरकार से निवेदन है कि अब भी समय है जब तक इसका आईसोलेशन नहीं होता तब तक वैट को न लगाया जाए क्योंकि इससे किसानों को, व्यापारियों को बड़ा भारी नुकसान है और सरकार को भी इससे

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

ज्यादा लाभ नहीं है। अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूँगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में काफी जोर-शोर से बात कही और आज सवेरे भी इस बात की चर्चा थी। लेकिन अगर आप विद्यालयों और स्कूलों के रखरखाव को पूरे हरियाणा में देखें तो बजट में इसके लिए प्रावधान किया है 1 करोड़ 60 लाख रुपये का इस प्रकार एक भवन की मरम्मत के लिए 1266 रुपये रखा है आज 1266 रुपये में एक भवन की सफेदी भी नहीं हो सकती है, मरम्मत कहाँ से होगी और किस तरह से आप विद्यार्थियों को शिक्षा मुहैया करा सकेंगे? रंगा साहब ने मैडीकल हैल्थ की बात कही। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश भर में 50 अस्पताल, 64 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 404 पी०एच०सीज०, 2299 हैल्थ सब-सैंटर, 22 टी०बी० और 55 डिसपैंसरियां हैं, जो लोगों का स्वास्थ्य चैक करती हैं। इन सभी में जहां तक दवाई देने का प्रावधान है उसके लिए 2003-2004 के बजट में 4 करोड़ 70 लाख रुपये खर्च किए गये हैं। इससे क्या पता चला, इससे यह अंदाजा लगता है कि प्रति व्यक्ति केवल दो रुपये वार्षिक खर्च हुआ और इसका मतलब यह हुआ कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एक पैसा भी हिस्सा नहीं आता तो आप किस प्रकार से स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं? मुख्य मंत्री महोदय ने भी कहा कि हम चश्में मुफ्त देंगे लेकिन एक पैसा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हिस्से में आता हो तो क्या स्वास्थ्य सुविधा आप उपलब्ध करा सकते हैं? यह बात आप ही समझ सकते हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय डॉक्टर रंगा साहब ने कहा कि हम और डॉक्टर लगा रहे हैं जिनकी कुल संख्या 17070 है उनकी संख्या और प्रदेश की जनसंख्या का हिसाब लगायें तो 12 हजार व्यक्तियों के हिस्से में एक डॉक्टर आता है तो मैं समझता हूँ कि एक डॉक्टर 12 हजार व्यक्तियों का स्वास्थ्य कैसे चैक करेगा और जनता को इसका लाभ कैसे मिलेगा यह आप खुद अन्दाजा लगा सकते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, 2000-2001 में जो अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पी०एच०सीज०, टी बी० सैंटर और डिसपैंसरीज की संख्या 2905 थी और अब इनकी संख्या में 21 की घटत हुई है (विघ्न) No one is perfect here, Neither you nor I. इस बारे में कृपया वित्त मंत्री जी अपने जवाब में बतायें। अब सवाल आता है एस०वाई०एल० का जोकि अहम है। इस बात की मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की है लेकिन अगर बजट में इसका प्रावधान देखा जाए तो पिछली बार बजट में एक करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी और अब की बार बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। क्या एस०वाई०एल० पूरी हो चुकी है कि इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय,एस०वाई०एल० इस प्रदेश की जीवन रेखा है। सब चीजें तो छोड़ी जा सकती हैं लेकिन एस०वाई०एल० को प्राथमिकता देनी नहीं छोड़नी चाहिए। हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि के बारे में सबको बहुत चिन्ता रहती है। यह सरकार तो किसानों के नाम से वोट लेकर सत्ता में आई है और अपने को किसान हितैषी सरकार कहती है। लेकिन इन्होंने कृषि के लिए बजट में 1.25 करोड़ रुपये का ही प्रावधान किया है जो कि टोटल प्लान का 5.76 प्रतिशत है और टोटल बजट का देखें तो एक प्रतिशत ही बनता है। वित्तमंत्री जी ने कृषि के बारे में बड़े जोर-शोर से कहा कि क्रोप इन्श्योरैंस इस साल से लागू की जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में गेहूँ, धान और गन्ना ये तीन फसलें मुख्यत:बोई जाती हैं और इन तीनों फसलों को ही क्रोप इन्श्योरैंस में कवर नहीं किया गया लेकिन जिन फसलों को इन्होंने कवर किया है उनके लिए 50 प्रतिशत पैसा सरकार की तरफ से दिया जाना है लेकिन उसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये इन्श्योरैंस का पैसा कहां से देंगे? यह हमारी समझ में तो नहीं आता है, शायद चुनाव देखकर इन्होंने यह घोषणा कर दी है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि गेहूँ, धान और शूगरकेन को भी इसमें शमिल किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने शूगरकेन के बारे में भी बड़ी चर्चा की कि ये हिन्दुस्तान में शूगरकेन का

सबसे ज्यादा भाव दे रहे हैं। सभी साथी जानते हैं कि मण्डी में अगर लेन-देन में तीन दिन से ज्यादा पेमैंट में ढिलाई हो तो खरीददार ढिलाई पर ब्याज देता है लेकिन हमारे यहां गन्ने के कृषक को ढिलाई पर ब्याज नहीं मिलता और पेमैंट भी उचित समय पर नहीं दी जाती। इसके अतिरिक्त प्रदेश में डिस्क्रीमीनेसन भी बहुत है। एक जगह किसान को भाव कुछ मिलता है और दूसरी जगह कुछ मिलता है। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के किसानों को एक भाव मिलना चाहिए, चाहे कोई यमुनानगर का किसान हो, चाहे रोहतक का किसान हो, चाहे पलवल का किसान हो और चाहे सिरसा का किसान हो, इसके लिए बजट में भी कोई प्रावधान नहीं रखा कि जिन किसानों का गन्ना सस्ते भाव में बिका है उन्हें मुआवजा दिया जायेगा। इनके इलैक्शन मेनीफैस्टों में भी था कि यह भाव दिया जायेगा लेकिन वह भाव सबको नहीं मिला। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने इण्डस्ट्री के बारे में और इण्डस्ट्रियल रोजगार के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कही हैं लेकिन बजट में इण्डस्ट्री के लिए केवल 11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । हमारी जो फाईनैंशियल कार्पोरेशन है, उसने वर्ष 2003-2004 में 19.27 करोड़ रुपये ऋण के रूप में वितरित किए। इतने कम पैसे से हम कितने आगे बढ़ पायेंगे ये लोग स्वयं हिसाब लगा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, फारेन इन्वैस्टमैंट के बारे में मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी तकरीबन पूरा सत्ता पक्ष चर्चाएं करता है कि 3132 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हुआ है। लेकिन 22-8-2003 को लोक सभा में एक प्रश्न आया था जिसका जवाब वाणिज्य मंत्री श्री अरुण जेटली ने दिया था और उन्होंने अपने जवाब में कहा था कि हरियाणा में पिछले चार वर्ष में कोई विदेशी निवेश नहीं हुआ है। एक बार मैंने पढ़ा भी था कि अरुण जेटली जी ने सही जवाब नहीं दिया। केन्द्र में सत्ता पक्ष के पांच सांसद भी हैं यदि गलत जवाब दिया गया था तो ये पूछ सकते थे। वह जवाब रिकार्ड में है और मेरे पास भी है। डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात के लिए तो मैं मुख्यमंत्री जी को एप्रीशिएट करता हूँ कि ये एक-एक दिन में कई-कई गांवों में जाते हैं। इतना तो मैं भी और शायद और कोई भी न जा पाये जितना ये जा पाते हैं। ये सुबह निकलते हैं और रोजाना 10-20 गांवों में हो आते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा कि 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत जो प्रोग्राम है और जिसका प्रचार बड़े जोर-शोर से सरकार कर रही है मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने कितने पैसे का प्रावधान इस प्रोग्राम के लिए इस बजट में किया है? मुझे तो इस बजट में इस कार्यक्रम के तहत कोई पैसा नजर नहीं आता। सरकार के रूरल डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट और मार्किटिंग बोर्ड की चर्चा मुख्य रही है जिसके लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले वर्ष 60 करोड़ या कभी-कभी 100 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया था। सरकार ने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत 1891 करोड़ रुपये लगाये हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो पैसा इस कार्यक्रम के तहत खर्च हुआ है वह कौन से विभाग का है? आया यह पैसा पंचायत डिपार्टमैंट को, जो सैन्ट्रल गवर्नमैंट से आया था वह है या किसी और स्कीम का जो पंचायतों ने या सरपंचों ने खर्च करना था वह है या किसी और मद में से यह पैसा खर्च किया गया है? कृपया जवाब देते समय वित्त मंत्री जी बताएं कि 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत जो पैसा खर्च किया गया है? वह कहां से किया गया है और क्या उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान भी किया गया है या नहीं? वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं दूसरी बार टैक्स फ्री बजट पेश कर रहा हूँ। लेकिन मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद लोगों पर किस-किस चीज पर कर के रूप में एडीशनल बर्डन जनता पर डाला है उसकी डिटेल में तो मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि सरकार ने हाउस टैक्स बढ़ाया, इलैक्ट्रीसिटी चार्जिज बढ़ाए, ट्रैक्टर्ज-ट्राली पर टैक्स लगाया, वाटर चार्जिज बढ़ाए। इसी प्रकार से लोकल एरिया डिवैल्पमैंट टैक्स बढ़ाया गया, कमर्शियलाइजेशन ऑफ

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

एजुकेशन पर टैक्स बढ़ाया है। सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी की फीस पहले से घटा कर 8 प्रतिशत कर दी है लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि पंजाब में अब भी यह 5 परसेंट है। गुड्ज पैसेंजर टैक्स, टोल टैक्स एण्ड स्टेट हाईवेज का बोझ जनता पर डाला। नैशनल हाई-वे तो आपके अधीन आते नहीं। इसी प्रकार से ट्रैक्टरों की रजिस्ट्रेशन पर भी फीस बढ़ाई गई, ड्राईविंग लाईसेंस की भी फीस बढ़ा दी गई है। जो बेरोजगार लोग मैक्सी कैब चला रहे हैं उन पर भी टैक्स का भार लाद दिया गया है, यह भी आपको मालूम है। कई चीजों पर टैक्स लगाया गया जिससे सरकार की आमदनी बढ़ी। पहले हुडा के प्लाट्स पर ट्रांस्फर फीस नहीं होती थी, वह भी आप लोगों ने लगा दी। इसमें कोई दो राय नहीं सरकार की आमदनी बढ़ी लेकिन प्लान बजट घटा है। जब आपका प्लान बजट घटा है तो फिर आप कहां से विकास का काम करेंगे? डिप्टी स्पीकर साहब, मेन-मेन बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। इन बातों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि यह बजट बिल्कुल फीका, खोखला और सिर्फ खाना-पूर्ति करने वाला है। यह आपका आखिरी बजट है। यदि आप इसी तरह का बजट पेश करते रहे तो बजट पेश करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। (विघ्न) आपका यही ट्रैण्ड चलता रहा तो आपको अगला बजट पेश करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का कड़ा विरोध करता हूँ। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बोलें।

चौधरी भजन लाल : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आज नहीं, सोमवार को बोलूंगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : भजन लाल जी, स्पीकर साहब ने क्लीयर कह दिया था कि आप के मैम्बरों ने जितना आज बोलना है बोल लें, पूरी खुली छुट्टी, समय की कोई पाबन्दी नहीं है। इसलिए आप आज ही बोल लें, सोमवार को बोलने का समय नहीं मिलेगा क्योंकि उस दिन वित्त मंत्री जी ने जवाब देना है।

श्री उपाध्यक्ष : भजन लाल जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, इसलिए मैंने आपको बोलने के लिए कहा है कि यदि आज आप बजट पर बोलना चाहते हैं तो बोल लें।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : डिप्टी स्पीकर सर, कई सालों के बाद सुबह के समय बजट पेश हुआ है और इन लोगों के पास तैयारी के लिए काफी समय था वरना तो बजट शाम को प्रस्तुत होता रहा है और शाम के 6.30 या 7.00 बज जाया करते थे। सुबह आते ही बजट पर बोलना पड़ता था और तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता था लेकिन इस बार तैयारी के लिए काफी समय था। उस समय में ये दूसरी एक्टीविटीज में व्यस्त रहे, अंदरवाईज अगर ये तैयारी करते तो इनके पास दिन के साथ ही साथ रात को भी काफी टाईम था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हमारे वित्त मंत्री जी को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि ये लोग रात के समय बजट की तैयारी करने वाले लोग नहीं हैं, इनकी तो रात रंगीन होती है। (हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, अगर आप बजट पर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज बजट पर नहीं बोलूंगा मैं सोमवार को बजट पर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, सोमवार को तो वित्त मंत्री जी का जवाब आएगा। (विघ्न) ऐसा है, चौधरी भजन लाल जी, पिछली बार भी मैंने आपको बोलने के लिए समय दिया था और आप पीछे हट गए थे और आज भी मैं आपको बोलने के लिए टाईम दे रहा हूँ लेकिन आप आज

भी बैकआउट कर रहे हैं (विघ्न) मैंने तो अपने पड़ोसी होने का फर्ज निभाया है। (हंसी)

चौधरी भजन लाल : डिप्टी स्पीकर साहब, अगर मैं और हुड्डा साहब ही बोलते रहेंगे तो हमारे बाकी के साथी कहां जाएंगे, आप हमारे दूसरे साथियों को आज मौका दीजिए हम तो सोमवार को बात करेंगे। (विघ्न)

राव इन्द्रजीत सिंह (जादूसाना) : डिप्टी स्पीकर महोदय, आपका शुक्रिया। उपाध्यक्ष महोदय, लोकदल की सरकार ने अपना 5वां बजट सदन के सामने रखा है और जब ये लोग पहली बार सत्ता में आए थे तो 1998-99 का जो बजट था वह इन्होंने पेश नहीं किया था लेकिन उस साल यह सरकार शासित हो गई थी, उस समय के कुछ आंकड़े मैं यहां पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

प्रो० सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऑन रिकार्ड राव साहब को ठीक करना चाहता हूँ। मैं इन्टरप्शन की मन्शा से खड़ा नहीं हुआ हूँ। इन्होंने कहा है कि 1998-99 के दौरान यह सरकार सत्ता में आ गई थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वर्ष 1999-2000 के दौरान यह सरकार स्थापित हुई और 1998-99 का वित्तवर्ष 31 मार्च, 1999 को समाप्त हो जाता है और यह सरकार 24 जुलाई, 1999 को सत्ता में आई थी इसलिए मैं इनको करैक्ट करना चाहता था।

राव इन्द्रजीत सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, वर्ष 1999-2000 की इनकी बात मैं मान लेता हूँ और इनका धन्यवाद करता हूँ। वर्ष 1999-2000 की बात चलती है तो लायबिलिटी और स्टेट डैट गारन्टी जो आउटस्टैंडिंग थी उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। फाईनैंस मिनिस्टर साहब, उस समय आउटस्टैंडिंग स्टेट गारन्टी वर्ष 1999-2000 के अन्दर 4315 करोड़ थी और डैट लायबिलिटी उस समय के दौरान 12,044 करोड़ थी। यह जो मौजूदा साल चल रहा है इसके दौरान हम देखते हैं कि कितनी डैट लायबिलिटी और आऊटस्टैंडिंग स्टेट गारन्टी बढ़ गई है। अगर उसका मुकाबला हम करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि पिछले चार सालों में जो बजट पेश किया है उसके माध्यम से ये हमारी स्टेट को अंधेरे में ले जा रहे हैं। मैं वर्ष 2002-03 का जिक्र कर रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, जो एक्चुअल स्टेट गारन्टी है वह 4315 से बढ़कर 7684 करोड़ रुपए की हो गई है। जो कि 1999 में 12,044 करोड़ रुपए की डैट लायबिलिटी थी और यह 2002-03 में 18187 करोड़ रुपए हो गई यानी कि डयोढ़ी से ज्यादा हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार जो अनुमान 2002, 2003 और 2004 के लिख रही है, इसके मुताबिक डैट लायबिलिटी 9900 से बढ़कर 2004 तक 21649 करोड़ रुपए हो जाएगी, 2005 में यह बढ़कर 23679 करोड़ रुपए हो जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, डैट लायबिलिटी अब 9000 से लेकर 23000 करोड़ रुपए हो गई है। यानी कि आलमोस्ट टू एण्ड हाफ टाईम हमारी डैट लायबिलिटी पिछले 5 सालों में बढ़ गई है। उपाध्यक्ष महोदय, जब वित्त मंत्री जी बजट पढ़ रहे थे तो उस समय मैं सदन में नहीं था। लेकिन मैंने इसको पढ़ा है तो इनकी स्टेटमैंट के मुताबिक हमारी भारत सरकार की तरफ से जो 11वां फाईनांस कमिशन है जोकि 2000 से लेकर 2005 तक गठित हुआ था, उसके तहत जो हरियाणा का शेयर सैन्ट्रल टैक्सिज में मिला करता था, वह उन्होंने घटा दिया है। पहले हरियाणा का सैन्ट्रल टैक्स में शेयर 1.238 प्रतिशत मिलता था, 11वें फाईनांस कमिशन के दौरान वह घटकर .944 प्रतिशत रह गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह भी कहा है कि 12वां फाईनांस कमिशन हमारा सैन्ट्रल शेयर इसलिए रिड्यूस कर रहा है क्योंकि हरियाणा बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है। इन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने हमें इस लिए यह हर्जाना लगाया है क्योंकि हम खुद ब खुद अपने साधनों से इस कमी को पूरा कर लेंगे। डिप्टी स्पीकर सर, मेरा मानना यह है कि वास्तव में उन्होंने हमारा पैसा इसलिए नहीं काटा है कि हम अपने साधनों से इस कमी को पूरा कर लेंगे। उन्होंने यह पैसा इसलिए काटा है क्योंकि केन्द्र सरकार और फाईनांस कमिशन

[राव इन्द्रजीत सिंह]

ने कुछ रूल्ज निर्धारित किए हुए हैं, जिसके अनुसार स्टेट द्वारा वह पैसा खर्च होना चाहिए जोकि इस सरकार ने नहीं किया। डिप्टी स्पीकर सर, इसी वजह से यह कट लगा है। डिप्टी स्पीकर सर, उदाहरण के तौर पर मैं एनुअल प्लान के बारे में कहना चाहता हूँ। बजट में एनुअल प्लॉन के अन्दर एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डवैल्पमैंट सैक्टर होता है जिसके तहत पिछले साल डवैल्पमैंट आफ इकनोमिक सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 9011 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस बार फाईनांस मिनिस्टर साहब ने 9011 करोड़ रुपये के अमाउन्ट को बढ़ाकर 9041.36 करोड़ रुपए कर दिया है यानी कि 30-35 करोड़ रुपए का इज़ाफा इसमें दिखाया है। अगर हम इस अमाउन्ट को इन-परसेंटेज टर्म्ज के अन्दर कम्पेयर करेंगे तो पिछले साल की परसैंटेज 43.4 बनती थी और इस साल जो अमाउन्ट इन्होंने दर्शाया है उसमें इज़ाफा होने की बजाए यह परसैंटेज 43.3 ही रह गई है। यानी कि पिछले साल की टर्म्ज के हिसाब से जो हमारा पैसा था उसकी परसैंटेज घटी है। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी जितनी तवज्जोह हमारी सरकार को देनी चाहिए थी उतनी तवज्जोह नहीं दी गयी। आज इंफलेशन किस तेजी से बढ़ी है। फाईनैंस कमीशन ने पिछले दिनों में हमारा जो पैसा कम किया है वह कुल मिलाकर कितना पैसा कम किया है यह मैं बताना चाहूँगा। फाईनैंस मिनिस्टर के हिसाब से ही यह तकरीबन 1100 करोड़ रुपये कम हुआ है यह कम इसलिए हुआ है क्योंकि सैंट्रल स्कीम्ज से कम पैसा प्रदेश को मिला है। हम सरकार से यह जानना चाहेंगे कि ये 1100 करोड़ रुपया हमें फाईनैंस कमीशन से क्यों कम मिला है, क्यों हमें इससे वंचित रखा गया है? इसी तरह से अब मैं सौशल सैक्टर का जिक्र करना चाहूँगा। सोशल सैक्टर सर्विसेज जो हैं पिछले साल बजट के दौरान इनका आउट ले था 890.23 करोड़ रुपये और यह कुल मिलाकर बनता था 42.4 प्रतिशत of the annual plan. इसको अब 890.23 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 919.87 करोड़ रुपये बना दिया गया है जोकि बनता है 42.3 परसेंट of the annual plan यानी सोशल सैक्टर सर्विसेज एनुअल प्लॉन का साईज इस साल कम किया गया है। आज हमारे एक साथी ने एक कालिंग अटैंशन मोशन के माध्यम से जब स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानना चाहा था तो उसके जवाब में रंगा साहब ने भी जवाब दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि हैल्थ सर्विसेज ऐसा सैक्टर है जिसके अंदर पैसे की पांबदी सरकार नहीं रखना चाहती क्योंकि अगर हमारा आदमी स्वस्थ होगा तो वह सारे देश के अंदर अलग ही नजर आएगा। लेकिन वास्तविकता में क्या हो रहा है कि हमारे हैल्थ सैक्टर के अलावा सोशल सैक्टर में जो स्कीम्ज आती हैं उसमें तीन बेसिक सर्विसेज हैं जिसके अंदर जनरल ऐजुकेशन, हैल्थ केयर और ड्रिंकिंग वाटर फैसेलिटीज। इनको सरकार प्राथमिकता भी देना चाहती है लेकिन इनका भी खर्चा इस बजट में पिछले साल की बनिस्पत कम किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से जो सरकार के और मुख्यमंत्री जी के क्लेम हैं कि हम इस तरफ ज्यादा तवज्जोह दे रहे हैं, ये खोखले हैं। जब हमारी तरफ से बजट पर या गवर्नर के अभिभाषण पर कुछ कहा जाता है तो आमतौर पर उधर की तरफ से यही समझा जाता है कि ये तो विपक्ष में बैठे हैं इसलिए इन्होंने तो विरोध ही करना है। इस तरह से जो उधर बैठे हैं उनको तो मखौल उठाने का अधिकार मिला हुआ है यानी इस तरह का वातावरण यहां पर बना दिया गया है। मैं एक बात के लिए तो सरकार की सराहना करना चाहता हूँ कि पानी के वितरण के बारे में बार-बार चर्चा हुई कि जितना पानी किसान के खेत के लिए चाहिए, वह उपलब्ध नहीं है, जितना पानी आम जनता को पीने के लिए चाहिए, उसमें भी कमी है और हम उतना पानी लोगों को प्रोवाईड नहीं करवा पा रहे हैं। इस चीज को देखते हुए पिछले दिनों के अंदर मुख्यमंत्री जी ने भी जिक्र किया था। चुंकि हमारे पास सिंचाई का पानी कम है इसलिए हमको क्रोपिंग पैटर्न

12.00 बजे

एडाप्ट करना पड़ेगा। इस बारे में कुछ सुझाव उधर से भी आए और सरकार की भी यही सोच थी। क्रोपिंग पैटर्न के बारे में फाईनैंस मिनिस्टर ने भी पहली बार अपने बजट में जिक्र किया है कि हम 900 करोड़ रुपये भारत सरकार से क्रॉप डायवर्सीफिकेशन के वास्ते लेना चाहते हैं इनका अन्दाजा यह है और हम भी समझते हैं कि जब तक क्रॉप डायवर्सीफिकेशन को अगर हमने सही ढंग से उतारना है तो उसको कम से कम उतना पैसा तो मिले जितना खर्च उसके अंदर करेंगे। उसको पूरा करने के लिए, किसान को पूरा पैसा प्रदान करने के लिए 900 करोड़ रुपया इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार ने केन्द्र सरकार से मांगा है। इसकी मैं सराहना करता हूँ, साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह चर्चा चार साल से हो रही है और हम बार-बार कह रहे हैं कि रावी ब्यास का पानी उपलब्ध नहीं है, जितना पानी मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है जब तक हम डायवर्सीफाई करेंगे तब तक हमारा कहीं पानी के ऊपर लट्ठ न बज जाए। चार साल से चर्चा चल रही थी और 900 करोड़ रुपया क्या इन्होंने तभी मांगना था जब तालमेल टूट जाए। आज से चार साल पहले यह पैसा मांगा होता तो यह नीति सिरे चढ़ जाती। आज ओम प्रकाश चौटाला जी अलग रास्ते पर चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अलग रास्ते पर जा रही है। अगली सरकार जो बनेगी उसके लिए ये छोड़ना चाहते हैं। यह लिप सर्विस है, ऐक्चुअल इनपुट ज्यादा होना चाहिए यदि इंटेग्रिटी इंटैक रखनी है तो। तीसरा मैं वाटर रिसोर्सिज के बारे में चर्चा कर रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : आप समय का ध्यान रखें। आप ऐलैबोरेट करना चाहते हैं।

राव इन्द्रजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जिक्र कर रहा था। आमतौर पर इस साइड से इक्विटेबल वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हरियाणा में नहीं हो रहा है। इस विषय में बार-बार चर्चाएं हुई। मैं समझता हूँ कि मेरे सत्ता पक्ष के साथियों को भी पता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है लेकिन ये चुप्पी साधे हुए हैं। जो हमारे को पानी उपलब्ध है वह तीन स्रोतों से है, सतलुज से हमें 4.4 एम०ए०एफ० मिलता है, यमुना से 4.5 एम०ए०एफ० मिलता है और रावी ब्यास जिसका जिक्र हम करते हैं तो कहा जाता है कि यह मामला सब-ज्यूडिस है इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। रावी ब्यास से हमें उम्मीद है कि 3.83 एम०ए०एफ० पानी मिलेगा, यह पानी हमारे को कुछ भाखड़ा सिस्टम से व कुछ नरवाना सिस्टम से मिल सकता है। सवाल इस बात का है कि इस 3.83 एम०ए०एफ० पानी का कुछ हिस्सा हरियाणा को मिल रहा है और यह आज से नहीं 1978 से मिल रहा है और जब से यह पानी मिल रहा है तब से यह उन्हीं जिलों में जा रहा है, जहां पर सतलुज का पानी पहले जा रहा था। जिन लोगों को आज के दिन पीने के पानी के लाले पड़ रहे हैं, मैं पैप्सू एरिया का जिक्र करना चाहता हूँ, जो पंजाब का इलाका था उसमें 1955 के अंदर इंटर स्टेट ट्रीटी एक बार तय हुई थी, जबकि रिआर्गेनाईजेशन स्टेट का नहीं हो पाया था, तब पैप्सू को इस पानी के शेयर का हिस्सा मिला था और पंजाब, पैप्सू व राजस्थान सरकार ने इस पर दस्तखत किए थे। संपत सिंह जी को इस बारे में अच्छी तरह से ज्ञान होगा। हमारा उस पानी का अधिकार था। पंजाब कहता है कि पानी नहीं देते और पंजाब के हम पीछे पड़े रहते हैं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : आप बजट पर आएं। आप ज्यादा ऐलैबोरेट कर रहे हैं। यह बात आप गवर्नर एड्रैस पर बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता।

राव इन्द्रजीत सिंह : इरीगेशन में एनुअल बजट में इन्होंने 4.33 प्रतिशत बजट रखा है मेरे लिहाज से इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए थी लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई बढ़ोतरी हुई हो। रावी ब्यास का जो पानी मिल रहा है उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिये जो कि पैप्सू के समय होता था क्योंकि कई क्षेत्रों में तो पानी के लाले पड़े हुए हैं इसलिए सभी क्षेत्रों में बराबर का हिस्सा पानी का होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्लीज वाईंड-अप कीजिए।

राव इन्द्रजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। यह फैसला हमारी सरकार ने खुद करना है। अगर हमारी सरकार यह फैसला करना चाहे तो कर सकती है क्योंकि हर पार्टी अपने चुनाव मैनीफैस्टो में तो कई बातें कहती हैं लेकिन जिस पार्टी को लोग सत्ता पर बिठाते हैं तब उस पार्टी का फर्ज बन जाता है कि वह बराबर का हिस्सा लोगों को दे। जैसे चौधरी भजनलाल जी कह रहे थे कि सभी क्षेत्रों को एक निगाह से देखना चाहिए, लेकिन आज एक निगाह से नहीं देखा जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी भजनलाल जी आपकी बात सुन ही नहीं रहे।

राव इन्द्रजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि पानी का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें। हम सोच रहे थे कि हमारे लीडर ऑफ दि हाउस और लीडर ऑफ दि अपोजीशन आपस में बैठकर वर्तमान ऐसैम्बली को भंग करके विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ करा देंगे लेकिन वह प्रस्ताव सरकार द्वारा मंजूर नहीं किया गया (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : राव साहब आप वाईंड-अप कीजिए।

राव इन्द्रजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इतना कहते हुए मैं इस बजट का विरोध करता हूँ।

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रो० सम्पत सिंह जी बहुत विद्वान सदस्य हैं उन्होंने जो बजट पेश किया है, मैं समझता हूँ कि यह बजट दिशाहीन है और किसी तरह से भी इस बजट को प्रगतिशील बजट नहीं कहा जा सकता। इस बजट में नया कुछ नहीं है सिर्फ आंकड़ों की हेराफेरी की गई हैं। खासतौर पर इसमें रोजगार के बारे में कोई खास बात नहीं कही गई है। इन्होंने यह भी कहा कि टैक्स फ्री बजट है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी इन्होंने बजट पेश किया था तो यह कहा था कि यह टैक्स फ्री बजट है लेकिन बाद में वाटर चार्जिज, सीवरेज चार्जिज हुड्डा ने और म्यूनिस्पिल कमेटियों ने बढ़ा दिये। हैल्थ सरचार्ज भी बढ़ा दिये। इन सब बातों को देखें तो मैं समझता हूँ कि हमारा स्टेट डैट की तरफ जा रहा है और हमारा जो लोन है वह 23672 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले साल का अगर देखा जाए तो 2003 के अन्दर स्टेट की गारन्टी 12461 करोड़ रुपये थी इसमें अगर लोन ऐड कर दिया जाये तो 2005 के अन्दर 40,000 करोड़ रुपये की गारन्टी बॉंड लोन के हो जावेंगे। दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा जो आपका इन्ट्रस्ट है वह 2003-2004 के अन्दर 26 प्रतिशत जो लोन पेमैंट का था और अब यह बढ़कर 29.58 हो गया है और जो इन्ट्रस्ट है वह तकरीबन 15 प्रतिशत है जो कि दोनों को मिलायें तो यह 36-37 प्रतिशत हो जाता है। इस प्रकार की हालत प्रदेश की है। उपाध्यक्ष महोदय, 1999-2000 के बजट में इन्होंने 2300 करोड़ रुपये प्लान बजट में रखा था उसे संशोधन करके इन्होंने 1785 करोड़ रुपये कर दिया था लेकिन actual expenditure हुआ 1675.42 करोड़ रुपये का। इसी तरह से 2000-01 में actual expenditure हुआ 1718.31 करोड़ रुपये का और इन्होंने प्लान किया था 1950 करोड़ रुपये का। 2001-02 में actual expenditure हुआ 1766.87 करोड़ रुपये का और इसी तरह से 2002-03 में 1776.19 करोड़ रुपये का actual expenditure हुआ । उपाध्यक्ष महोदय, पिछले चार पांच साल से हम देख रहे हैं कि हमारी जो कन्ज्यूमर प्राईस इन्डैक्स है अगर उसका बेस 1982 से माने तो 100 अंक था और 1998-99 में हमारा कंज्यूमर प्राईस इन्डैक्स 376 अंक था और अब यह बढ़कर नवम्बर 2003 में 444 अंक हो गया है।

हमारा कंज्यूमर प्राईस इन्डैक्स बढ़ रहा है और बजट का actual expenditure उतने का उतना ही है तो कहां से हमारा प्रदेश प्रगतिशील माना जायेगा। पिछले चार साल से यह वहीं का वहीं टिका हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से हमारे प्रदेश का जो घाटा है वह टोटली अनमैनेजेबल है, उसके बारे में मैं बतलाना चाहूँगा कि आज जो सी०ए०जी० की रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें दिखाया गया है कि मार्च, 2003 के अंत में जो एरियर्ज रैवेन्यू के हैं उनमें मेजर डिपार्टमैंट्स के 1576.98 करोड़ रुपये के ड्यू हैं। इसी प्रकार Total loss of revenue etc. amounting to Rs. 439.39 crore in 156286 केसिज यानी सेल डीड़ के अंदर इस प्रकर के एरियर्ज हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो उत्तरी बिजली वितरण निगम है उसमें मीटर परचेज के अंदर लोएस्ट टैंडर को इग्नौर किया गया, जिसकी वजह से 10.92 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। यह मैं नहीं कह रहा यह सी०ए०जी० की रिपोर्ट में दिया हुआ है। इसी प्रकार से Precurement of one lakh meter cupboards on single tender basis at unjustified rates resulted in extra expenditure of Rs. 433 crores. यह सी०ए०जी० की रिपोर्ट में दिया हुआ है। इसी प्रकार से Non replacement of defective meters ranging between 6.3 and 8.2 per cent of metered connections during three years up to 2002-2003 resulted in loss of revenue of Rs. 71.86 crore as the consumers were billed on average basis. उपाध्यक्ष महोदय, यदि इसी प्रकार से अनमैनेजेबल तरीके से हम अपना काम चलायेंगे तो घाटा तो बढ़ेगा ही। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, Non-recovery of interest of Rs. 16.80 crore on a loan of Rs. 44.21 crore granted to Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited and Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited resulted in loss of revenue to Market Committees. तो मैं यह कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से लोसिज हो रहे हैं उसका कारण यह है कि ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। पिछली बार इन्होंने C.R.P.F. की बात की थी कि ये लोग जो लोन ले रहे हैं उससे सारा घाटा पूरा करेंगे, इस बारे में इन्होंने क्या किया है ? उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह कहना चाहूँगा कि बजट का जो deficit है, वह इनका 2003-04 में 226 करोड़ रुपये से शुरू हुआ था और 339.38 करोड़ रुपये पर खत्म हुआ। इस साल इन्होंने कहा है कि यह 438.97 करोड़ रुपये पर खत्म होगा। इस बारे में मैं कहूँगा कि यह जो घाटा है, यह सिर्फ आंकड़ों का फेर है इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है और मेरे हिसाब से तकरीबन 1300 करोड़ रुपये घाटे का बजट है, यदि इसका सही तरीके से हिसाब लगाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से हमारे expenditure दिन ब दिन बढ़ रहे हैं इससे साबित होता है कि मौजूदा सरकार रैवेन्यू एक्सपैंडीचर पर कंट्रोल करने में नाकाम रही है। रैवेन्यू एक्सपैंडीचर 2003-04 में 10673.51 करोड़ था वह बढ़कर 11684.02 करोड़ रुपये 2004-05 में हो गया। जो यह राज्य की टोटल सैलरी और इन्टरस्ट की पेमैंट की बात है, इन्होंने लिखा है it is due to interest payment और अगर आप देखेंगे कि इन्होंने रूरल डिवैल्पमैंट के लिए 2002-03 के लिए 5 प्रतिशत पैसा खर्च करना था और इस वर्ष केवल कर रहे हैं 3.56 प्रतिशत। इसी प्रकार से एजुकेशन के अन्दर इनका खर्चा 12 परसैंट से घटकर 11.42 परसैंट रह गया है। हैल्थ के बारे में हैल्थ मिनिस्टर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। वर्ष 2002-03 का हैल्थ का बजट 3 परसेंट था वह भी इन्होंने घटाकर इस बजट में 2.04 परसैंट कर दिया है। इसी प्रकार से जो लोन लिया हुआ है उसकी रिपेमैंट का भी काफी ब्याज बन गया है। जो लोन लिया हुआ है, उसकी रिपेमैंट और इन्टरस्ट जो है वह 2488 करोड़ रुपये है। इन्होंने स्टेट गारन्टी का इस बजट में कोई जिक्र नहीं किया लेकिन सी०ए०जी० की रिपोर्ट में यह दे रखा है कि सरकार ने कार्पोरेशन्ज को होल दी ईयर ऑफ 2003 तक, 12,461 करोड़ रुपये की बैंक गारन्टी दे रखी है। इस प्रकार से मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ कि यह घाटा इसलिए बढ़ रहा है सरकार फारेन टूर किए जा रही है। यह सरकार दुनिया भर का खर्च बढ़ा

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

रही है जैसे लग्जरी कार पर खर्च करके सोनाटा आदि गाड़ियां खरीद कर फिजूलखर्ची सरकार कर रही है। मैं समझता हूँ कि इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। (विघ्न) हमारे पास तो अम्बैस्डर कार थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहूँगा कि अगर आप हरियाणा की सड़कों पर निकलते हैं तो वहां पर आपको बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा मिलता है 'नेक इरादे निभाये हमने वायदे।' मुझे तो इनके कोई नेक इरादे नजर नहीं आते जो इन्होंने निभाये हैं। इसी प्रकार से यह सरकार होर्डिंग के ऊपर जबर्दस्त पैसा खर्च कर रही है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अगर इस पैसे की बचत करके किसी रूरल डिवैल्पमैंट पर लगाया जाये तो अच्छा रहेगा लेकिन होर्डिंग पर यह सरकार अन्धाधुंध पैसा खर्च किए जा रही है। अगर सड़क की बांयें तरफ नजर करें तो देवी लाल जी के स्टैच्यू नजर आते हैं, सीधा देखते हैं तो बड़े-बड़े होर्डिंग और मुख्यमंत्री जी के बोर्ड्ज नजर आते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सरकार फिजूलखर्ची जो कर रही है उस पर कन्ट्रोल करे।

श्री उपाध्यक्ष : आप वाईंड-अप करें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अभी तो मैंने केवल 2-3 बातें ही की हैं।

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : ऑन ए प्वायंट ऑफ ऑर्डर सर, कैप्टन साहब, आप लोगों ने तो सारी दीवारें ही पुतवायी थी। हमने तो उसकी नकल की है कि यह ज्यादा अच्छा होगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : डिप्टी स्पीकर साहब, वैट लगाने से भी हरियाणा को काफी आर्थिक और मानसिक नुकसान हुआ है। वैट लगाये जाने से हमारे किसानों को और व्यापारियों को भी बहुत अधिक नुकसान हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो धान हमारी स्टेट में आया करती थी वह वैट लगाये जाने के कारण दूसरे प्रदेशों में जा कर बिकी, इसका मुख्य कारण हरियाणा में वैट लगाया जाना रहा है जबकि आस-पास के प्रदेशों में वैट नहीं लगाया गया था। वैट लगाये जाने से हमें रेवैन्यू का काफी लोस हुआ है। इसी प्रकार से एच०एस०आई०डी०सी० के जो प्लाट वितरित किए गए हैं वे भी सही तरीके से नहीं किये गये। इन प्लाटों को भी लोगों को केवल एक इन्टरव्यू लेकर सीधे ही अलॉट कर दिए जबकि उन प्लाटों की मार्किट वैल्यू बहुत अधिक थी। ऐसे गलत तरीके से प्लाट अलॉट करने पर भी सरकार को काफी रेवैन्यू का लोस हुआ है। इसी प्रकार से सिकन्दरपुर धोंसी जो गांव है वहां पर एक जनता फ्री स्टेशन 20 साल की लीज पर दे दिया गया। यह स्टेशन केवल थ्रो अवे प्राईस पर दिया गया। मैं समझता हूँ कि इसका जो मार्किट रेट था, वह बहुत ज्यादा था। वहां पर किसी ने स्टे ले लिया और उसके बाद थ्रो अवे प्राईसिज पर फ्री स्टेशन दे दिया गया। इसी प्रकार से सैक्टर 33-34 के अन्दर भी इन्फोटेक इन्फर्मेशन के लिए जो प्लाट काटे गए थे वे भी आपने बकायदा थ्रो अवे प्राईस पर मार्बल मार्किट वालों को दिए और वह भी केवल मात्र 2700 रुपये प्रति स्क्वेयर फीट के हिसाब से जबकि वहां पर मार्किट रेट 15 हजार स्क्वेयर फीट से कम नहीं है।

श्री धीरपाल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, कैप्टन साहब पता नहीं कहां से फिगर्ज ले कर आते हैं और क्या कहते हैं यह अधिकार तो इनका है। जिस बात पर ये चर्चा कर रहे हैं अभी तक तो कोई प्लाट अलॉट नहीं हुआ है। जहां तक भाव की बात है, तो भाव 7000/- रुपये प्रति वर्ग गज तय किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हाईकोर्ट के ऐसे निर्देश हैं। शायद कैप्टन साहब को तकलीफ इस बात की होगी कि जो व्यापारी वहां पर कार्य कर रहे हैं और वहां पर बैठे हुए हैं अगर उनको वहां से

उठा कर स्थान देना है तो केवल उन्हीं का अधिकार वहां पर सुरक्षित है न कि कोई भी आदमी आ जाए और प्लाट के लिए एप्लाई करे तो उसको प्लाट दे दिया जाएगा। जो लोग पहले से ही इस व्यापार से जुड़े हुए हैं और वहां पर बैठे हुए हैं केवल उन्हीं लोगों को प्लाट दिए जाने हैं। ये पता नहीं किस जमाने की बात कर रहे हैं और पता नहीं यह भाव कहां से ले कर आए हैं, कौन सी किताब से इन्होंने यह पढ़ा है। कैप्टन साहब, इस प्रकार की कोई जानकारी हमारे विभाग के पास नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कैप्टन साहब, क्या आप कन्फर्मड हैं कि उनको 2700/- रुपये वर्ग गज के हिसाब से वहां पर प्लाटस दिए गए हैं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : यह बात तो आप कन्फर्म कर लीजिए। मेरे पास रिपोर्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप यह बात हाउस में कह रहे हैं। यह मामला मेरी कांस्टीच्यूएंसी से सम्बन्धित हैं और थोड़ा बहुत यह मामला मेरे नॉलेज में भी है। (विघ्न) यहां पर जो भी बात आप कहें वह जिम्मेदारी के साथ कहें। 2700/- रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से क्या मार्बल का धन्धा करने वालों को प्लाटस दिए गए हैं (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : जी हाँ, प्लाटस दिए गए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तक कोई प्लाट नहीं दिया गया है, अभी तो केवल एप्लीकेशन्ज़ मांगी गई हैं। कैप्टन साहब, आप हाउस में वही बात कहें जिसके सही तथ्य आपके पास हों। आप अपनी इन्फर्मेशन पता नहीं कहां से लेते हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : डिप्टी स्पीकर साहब, वहां पर लोगों ने कब्जे भी ले लिये हैं।

श्री धीरपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कैप्टन साहब फिर गलत बात कह रहे हैं जो कि तथ्यों से परे है। अपनी सरकार के समय में इन्होंने अनियमित कॉलोनियां बसाई और पता नहीं इन्होंने कहां-कहां पर कब्जे करवाए। इन्होंने अजय सिंह के नाम पर और यादव के नाम पर कॉलोनियां कटवाई थी।

कैप्टन अजय सिंह यादव : मैंने कोई कॉलोनी नहीं कटवाई थी। अगर किसी ने यादव नाम लिख दिया तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह कॉलोनी मैंने कटवाई। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठिए। (विघ्न) अपने मन्त्रालय के बारे में स्पष्टीकरण मंत्री महोदय दे रहे हैं। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कैप्टन साहब ने यह बात कही कि वहां पर लोगों ने कब्जे ले लिये हैं। कौन सी भूमि पर कब्जे लिये हैं और कब आप कब्जे वहां पर देख कर आए हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, ये हाउस में एक गैर जिम्मेदाराना बात कह रहे हैं। राव धर्मपाल जी ने भी इस बात का जिक्र किया था तो मैं हाउस की जानकारी के लिए यह बताना चाहूँगा कि सात हजार रुपये प्रति वर्ग गज का भाव वहां पर विभाग ने स्वीकृत किया है और केवल उन्हीं लोगों को वहां पर प्लाटस अलॉट होंगे जो इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए लोग हैं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : कैप्टन साहब, इसके साथ ही एक चीज मैं आपको और बता दूं क्योंकि यह बात मेरे नॉलेज में है। कुछ इण्डस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्हें शहर से बाहर निकालने की बात की गई है जिसमें

[श्री उपाध्यक्ष]

इलैक्ट्रोप्लेटिंग और आरा मशीनें भी हैं। उन लोगों के छोटे-छोटे धन्धे हैं, उनको प्लाटस दिए जा रहें हैं और वे रिजनेबल रेट्स पर दिए जाने चाहिएं, इस बात को तो आप मानेंगे।

श्री धीरपाल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, 200 वर्ग गज से लेकर 600 वर्ग गज तक के प्लाटस हैं और उनमें भी केवल माननीय हाईकोर्ट के आदेशों की पालना की गई है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों के बारे में मैं एक बात खासतौर पर कहना चाहूँगा। हमारी जो ग्रामीण सड़कें हैं उनकी मरम्मत न तो एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड ने करवाई है और न ही पी०डबल्यू०डी० विभाग ने करवाई है। हमारे एरिया में पिछले करीब 8 साल से एक भी लिंक रोड न तो नई बनवाई है और न ही कोई रिपेयर की गई है। मुझे दु:ख इस बात का है कि मेन स्टेट हाईवेज पर 25 से ज्यादा टोल टैक्स केन्द्र स्थापित कर दिए गए हैं और आम पब्लिक से टोल टैक्स वसूला जा रहा है। सरकार यह क्या कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि वह अपने फालतू के खर्चों को कम करके इस काम को करे, टोल टैक्स लगा कर यह सरकार पब्लिक पर क्यों बोझ डाल रही है। इन सड़कों को स्वयं सरकार बनाकर दे। जब ये सैन्टर गवर्नमैंट के साथ थे तब तक तो उनको दोष नहीं दिया, अब ये 11 सौ करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप वाईन्ड-अप करें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में मुख्य मंत्री जी आए और दूसरे मंत्री भी आए थे, उन्होंने कहा था कि वहां पर बाई-पास बनाया जाएगा। डी०ओ०टी० ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। लेकिन वे घोषणाएं, घोषणाएं ही रह जाएंगी।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा०एम०एल० रंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। कैप्टन साहब ने जो बाई-पास का जिक्र किया है तो इस विषय में मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 19 तारीख को रेवाड़ी में दो पुलों का शिलान्यास करने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप एक दो मिनट में ही वाईंड-अप करें।

कैप्टन अजय सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अर्बन डवैल्पमैंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)** अध्यक्ष महोदय, जो स्टेट में कॉलोनिज् हैं, वे कॉलोनिज् हुड्डा का टैक्स, डवैल्पमैंट चार्जिज इत्यादि दे रही हैं। इस बारे में धीरपाल जी ने जिक्र किया था इसलिए मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आपका समय समाप्त हो गया है इसलिए आप सीट पर बैठ जाएं। नैक्स्ट स्पीकर श्री शादी लाल बत्रा जी बोलेंगे।

श्री शादी लाल बत्रा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं इसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, 9 तारीख को राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण सदन में पढ़ा और कल दिनांक 12-2-2004 को प्रो० सम्पत सिंह जी ने बजट पेश किया। उनमें इन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में 70 फीसदी लोग

कृषि पर निर्भर करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं जी०एस०डी०पी० के बारे में कहना चाहूँगा। इसमें कृषि, पशुधन वगैरह आ जाते हैं। आज जी०एस०डी०पी० कम हो रहा है और यह क्यों कम हो रहा है, नैचुरल क्लैमिटी और पशु कम होने की वजह से हो रहा है या चाहे किसी भी कारणों से हो रहा है। हम 50 सालों में जी०एस०डी०पी० कम न हो, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर सके हैं। अध्यक्ष महोदय, ये जो मैनुफैक्चर्र सैक्टर की बात कर रहे हैं कि इसमें 77 प्रतिशत इन्क्रीज है, मैं आपके माध्यम से इस सरकार को यह बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर में जी०एस०डी०पी० कम हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और अगर यह प्रदेश एग्रीकल्चर में पिछड़ गया तो यह बहुत ही चिन्ता का विषय होगा। यहां पर टैक्स की भी बात आई। अध्यक्ष महोदय, यह नहीं कि सारा साल टैक्स नहीं देते हैं। अध्यक्ष महोदय, सदन में सदस्यों को किसी भी विषय में बोलने नहीं दिया जाता है। अगर किसी को बोलने का मौका दिया जाएगा तो ही वह यहां पर अपने विचार रख सकेगा कि टैक्स लगा है कि नहीं लगा है। हमेशा सदस्यों की अनदेखी की गयी है। चाहे विधानसभा के अंदर की बात हो या बाहर की बात हो सदस्यों को मान्यता नहीं दी जा रही है। मैं समझता हूँ कि ऐसा करके प्रजातंत्र के इस मंदिर में कमजोरी लायी जा रही है और इसको खोखला किया जा रहा है। यह कब तक चलेगा, इसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। जब ये टैक्स फ्री बजट की बात करते हैं तो ये उसके बाद साल भर टैक्स क्यों लगाते रहते हैं। बजट के बाद इतने टैक्स लगाए जाते हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। अध्यक्ष महोदय, यह आज की बात नहीं है बल्कि हम यह बात पिछले चार सालों से देख रहे हैं कि बजट तो टैक्स फ्री दो और उसके बाद टैक्स ही टैक्स लगा दो क्योंकि बाद में तो यह चल ही जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, सी०ए०जी० की जो रिपोर्ट आयी है वह बड़ी एलार्मिंग है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि सी०ए०जी० ने हमारी सरकार के बारे में क्या कहा है। Epitome of CAG's Reports on the Government of Haryana for the year ended 31st March, 2003 के पेज 1-2 के हाइलाईटस में जो दर्शाया गया है मैं उसको यहां पर पढ़कर सदन को बताना चाहता हूँ—

"—Fiscal performance of the State was unsatisfactory due to continued revenue deficit and fiscal deficit.

—Indebtedness of the Government increased by 89 per cent during 1998-2003 at an average growth rate of 18.72 per cent. Interest payments increased by 95 per cent during 1998-2003 and constituted 21 per cent of revenue expenditure during 2002-2003

—Arrears in revenue increased by 88 per cent from Rs 307 crore to Rs. 577 crore during 1998-2003 indicating poor tax compliance.

—Returns from investments in Public Sector Undertakings/Co-operative institutions were negligible.

—Excess expenditure of Rs. 1,225.21 crore over budget provisions during 2001-2002 was not regularized in terms of Article 205 of the Constitution of India.

—Ineffective budgetary and expenditure control led to surrender or Rs. 1,284.81 crore on the last day of the financial year against a saving or Rs. 2,136.60 crore.

—Yield per hectare under cotton and Kharif pulses and area sown under

[श्री शादी लाल बंत्रा]

commercial crops declined during 2002-2003 in comparison to 1996-97.

—Maintenance of watersheds was not handed over to Watershed management Committees.

—Certified seeds were not sown in 82 and 96 per cent area under wheat, paddy and gram.

—Shortage of Drug Inspectores led to shortfall in inspection of during selling units.

—Testing facilities for homeopathic, Ayurvedic, Unani Medicines and a large number of Allophathic drugs were not available nor any alternative arrangements for their tests were made.

—There was delay of one and half months to one and half years in testing samples in 74 per cent cases.

—Out of 2.21 lakh disabled persons, only 22 per cent were benefited during 1998-2003. No time bound action plan to cover/rehabilitate disable persons was formulated.

—Negligible number of handicapped persons were provided employment.

—Implementation of National Programme for Rehabilitation of persons with disabilities was slack.

—Against the requirment of 4,268 Fire Stations and 422 Water Tenders in the State, there were only 28 Fire Stations and 105 Water Tenders.

—Only 10 hydrants, 14 underground water tanks and 8 tubewells were working conditions against the requirement of 345, 46 and 21 respectively. There was also acute shortage of manpower.

—Response time to fire calls was more than prescribed time in 33 per cent cases in urban areas and in 72 per cent cases in rural areas.

—Non-exercising of prescribed checks by DDOs resulted in embezzlement of Rs. 8.14 lakh.

—Irregular expenditure of Rs. 2.25 crore was incurred on engagement of daily wage workers.

—Water supply schemes constructed by spending Rs. 1.26 crore, without ascertaining availability of raw water, remained unutilized.

—Staff quarters constructed by spending Rs. 89.97 lakh under Yamuna Action Plan were occupied by private agencies on nominal rent instead of staff.

—Sewrage schemes constructed by spending Rs. 1.27 crore without construction of disposal chamber remained non-functional.

—Haryana Urban Development Authority incurred unfruitful expenditure of Rs. 59.31 lakh on construction of booths without proper survey of demand.

जबकि अध्यक्ष महोदय, आज सरकार यह मानती है कि ये किसान हितैषी है। किसानों के बलबूते पर ही आज ये यहां पर हैं और आज जो सर्टिफाईड सीड्ज हैं वे उनको नहीं दिए जाते हैं। और सी०ए०जी की रिपोर्ट में आगे भी लिखा है कि –

—Due to non-acceptance of highest bid of Rs. 4.41 crore, Haryana Urban Development Authority sustained a loss of Rs. 88 lakh.

—Professional service fees of Rs. 2.01 crore was not recovered by Haryana Urban Development Authority from allottees.

श्री अध्यक्ष : बत्रा साहब अब, आप वाईड-अप करें।

श्री शादी लाल बत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं वही तथ्य ले रहा हूँ जो ऐडमिटिड हैं जो सी०ए०जी० ने दिए हैं। आप सी०ए०जी० की रिपोर्ट देखें तो नजर आता है कि हरियाणा गवर्नमैंट कैसे चल रही है उनकी वर्किंग क्या है। (विघ्न) अगर आप बजट ऐट-ए-ग्लांस देखें तो उसमें यह है कि रुपया कहां से आएगा और कहां जाएगा। हमारे बजट का 44.24 परसेंट कर्जा देने में जा रहा है, Payment of loan and interest कहां से आते हैं जो कर्ज लेते हैं उसका 53 परसेंट अमाउन्ट दोबारा से कर्ज देते हैं। कर्ज लेकर कर्ज देना यह कहां तक चलेगा इसका मतलब तो यह हुआ कि सरकार कोई ऐसी इन्कम या कोई सोर्स जनरेट नहीं कर सकी। जिससे आमदनी बढ़ सके। खर्च बढ़ता जा रहा है और हमें उस तरफ कोई चिंता ही नहीं है। सारा पैसा उल्टा खर्चों में चला जाएगा तो कैसे काम होगा ?

श्री अध्यक्ष : बत्रा जी, आप यह बताएं कि इसका सरकार पर क्या जोर हुआ ?

श्री शादी लाल बत्रा : अध्यक्ष महोदय, बजट का 44.24 परसैंट कर्ज दे रहे हैं और पब्लिक इट्रैस्ट 38.87 और 4.91 करोड़ आ रहा है यह बहुत ही अलारमिंग सिचुएशन है। इस सबके बावजूद फिर भी ये कहते हैं कि डिवैल्पमैंट बहुत कर रहे हैं। सदन में रोड्स की बहुत चर्चा की गई है। मैं आपके नोटिस में ला दूं कि पिछली बार भी मैंने काल अटैंशन मोशन के द्वारा सरकार से अनुरोध किया था कि रोहतक की सड़कें ऐसी हैं कि गाड़ियों पर तो क्या पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है तो मुझे आश्वासन दिया गया था कि वे सड़कें बन जाएंगी आज चार साल हो गए हैं उन सड़कों पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है। वे सड़के हैं:— लेबर चौक से जगदीश कालोनी इस सड़क पर पैदल चलना मुश्किल है चाहे वह सर्कुलर रोड है, गोहाना बस स्टैण्ड से सुखपुरा चौक, लाडौत रोड़ जो गोहाना तक जाती है उस पर भी चलना मुश्किल है। काठ मंडी के सामने वाली सड़क की भी हालत बहुत खराब है।

श्री बलबंत सिंह मायना : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इन्होंने रोहतक की सड़कों की चर्चा की है क्या इन्होंने यह देखा है कि मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के आने से पहले रोहतक शहर की क्या हालत थी। आज रोहतक शहर की वह सारी सड़कें मंजूर हो चुकी हैं जिनकी इन्होंने चर्चा की है। काठ मंडी से लेकर दूसरी जितनी सड़कें हैं या डी-पार्क था या जो सारे चौराहें हैं

[श्री बलवन्त सिंह मायना]

वह कितने सुंदर बना दिए गए हैं। आज रोहतक शहर की दशा में बहुत सुधार हुआ है।

श्री शादी लाल बत्रा : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मंजूर हो चुका है मैंने पेपर तो देखे नहीं हैं कि मंजूर हुआ है या नहीं, इन्होंने पेपर देखे होंगे क्योंकि यह सत्ता पक्ष में बैठते हैं। मैं तो विपक्ष का सदस्य होने के नाते यह कह सकता हूँ कि आज चार साल हो गये लेकिन वहां की सड़कें आज चलने के काबिल नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : बत्रा जी, आप बैठिये।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो चेयरमैन मार्किटिंग बोर्ड ने बता दिया है। लेकिन मुझे भी रोहतक जाने का मौका मिला था तब मैंने देखा कि जो झज्जर रोड है, जो कि मेन रोड से निकलता है वह डेढ़ फुट ऊंची सीमेंट की सड़क बनते हुई मैंने खुद देखी है। इस बात को बत्रा साहब मानते हैं या नहीं यह मैं नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष : अब मांगे राम गुप्ता जी बोलेंगे।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल सकता। अगर आप मुझे बुलवाना चाहें तो सोमवार को मौका दे देना।

श्री अध्यक्ष : मांगेराम गुप्ता जी, सोमवार को तो वित्त मंत्री जी बजट का रिप्लाई देंगे इसलिए उस दिन बजट पर बहस नहीं होगी। बोलना है तो आज ही बोल लें। वर्ना अब धर्मवीर जी बोलेंगे।

श्री धर्मवीर सिंह (तोशाम) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं इस बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। बजट भाषण में ऐसी कोई खास बात नहीं है इसमें तो केवल यह दिखाया गया है कि कर्ज कैसे लेंगे और कैसे देंगे। इसके अलावा कुछ खास नहीं है। प्रो० साहब ने 11वें वित्त आयोग का जिक्र किया कि 11वें वित्त आयोग से हमें 1100 करोड़ रुपये का कम हिस्सा मिला है मुझे तो आशंका है कि हमें 12वें वित्त आयोग में भी कम पैसा मिलेगा। इस प्रावधान के मुताबिक भारत सरकार द्वारा हमारे साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया गया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने हमारा हजारों रुपये का एक्साईज घटा दिया और डीजल के रेट बढ़ा दिये तो मैं चाहूँगा कि यह सदन भारत सरकार के खिलाफ यूनानिमसली एक निन्दा प्रस्ताव पास करे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हर जगह यह कहा है कि केन्द्रीय सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है और पैसा हमें कम मिला है सदन में बैठे सत्ता पक्ष के बहुत से साथियों ने इस बात को दोहराया है। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह तकरीबन 2100 करोड़ रुपये का बजट है और लगभग 439 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। असल में पिछले चार साल से प्लॉन बजट कभी भी 1800 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं गया है। मुख्यमंत्री जी और सत्तापक्ष के साथी बार-बार चर्चाएं करते हैं कि पिछले चार साल में गांवों के विकास पर 18 सौ कुछ करोड़ रुपये खर्च किये हैं। जबकि इस साल रूरल डिवैल्पमैंट फंड सिर्फ 130 करोड़ रुपये है। जहां तक पिछले चार सालों में 40 हजार घोषणाएं पूरी करने की बात है तो उसके हिसाब से चार साल में हर घोषणा पर 450 रुपये से कम खर्च किया गया है। इस तरह से 450 रुपये में तो किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया जा सकता। इस वर्ष 130 करोड़ रुपये का प्रावधान रखकर ये कहते हैं कि हर ब्लॉक में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करते हैं। हमें नहीं पता यह पैसा

कहां से आयेगा। यह तो सिर्फ कागजी बात बनकर रह जायेगी (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने तोशाम सब-डिविजन बनाया, लेकिन ये जाते समय साढ़े चार साल बाद बनवा रहे हैं। चौधरी बंसी लाल जी ने इस डिविजन को 8 साल पहले तोड़ा था जब इनकी सरकार आई तब हमने सोचा था कि आते ही ये तोशाम सब-डिविजन बनायेंगे। लेकिन इन्होंने तोशाम को सब-डिविजन बनाया, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अब ये जो पैसा पानी पर और पक्के खालों पर खर्च करने जा रहे हैं, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने इसके लिए नाबार्ड के पैसे का जो प्रावधान बजट में कर रखा है, यह पैसा ये केवल भाखड़ा कमाण्ड एरिया पर खर्च कर रहे हैं। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे हल्के में बहुत पुराने पक्के खालें बने हुए हैं उनकी रिपेयर के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वहां पर ऊँचे-नीचे टिब्बे हैं इसलिए उन खालों की रिपेयर के लिए बजट में पैसे का प्रावधान किया जाये। अध्यक्ष महोदय, हम कई सालों से पानी के बटवारे की बात करते हैं और अध्यक्ष महोदय, आप भी इसके भुगतभोगी हैं, रोहतक, नारनौल, महेन्द्रगढ़ तथा भिवानी पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ रहा है। मौजूदा सरकार अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने की बात करती है लेकिन हमारे यहां कई माइनर्ज ऐसे हैं जिनके अन्तिम छोर तक पानी पहुंचने की बात तो अलग है, बहुत से वाटर वर्क्स में भी पीने का पानी नहीं पहुंच पाता। इसलिए मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर पानी पहुंचाना बहुत जरूरी है और वहां पानी पहुंचना तभी संभव होगा जब भाखड़ा कैनाल का पानी डब्ल्यू०जे०सी० में डालकर हमारे इलाके में दिया जायेगा। इस बारे में जब हम बार-बार कहते हैं तो यही जवाब मिलता है कि जब एस०वाई०एल० पूरी होगी तभी रावी-ब्यास का पानी मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां बहुत पुराने पम्प हाउसिज हैं यदि उनके लिफ्ट सिस्टम ठीक करवा दिए जायें तो पानी उठाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, बजट में कहा गया है कि नई छिड़काव पद्धति के अनुसार सिंचाई की जायेगी। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे वहां मिराण में 10 करोड़ रुपये के स्प्रिंकलर सैट पड़े हैं, जो बहुत पहले खरीदे गये थे और मुझे पता चला है कि उनको अब बहुत कम दामों पर किसी दूसरी एजैंसी को दिए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वे स्प्रिंकलर सैटस अब अरबों रुपये के हैं और नये के नये हैं उन्हें दोबारा से चालू कराने की कोशिश करें ताकि किसान कम पानी में अच्छी तरह सिंचाई कर सकें और अधिक पैदावार ले सकें।

अध्यक्ष महोदय, सड़कों के बारे में रामपाल माजरा जी ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि लोहाणी से बहल तक की सड़क पर 82 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करके उस सड़क को तैयार करवा दिया गया है। अभी मुख्यमंत्री जी बहल गए थे और वहां पर जाकर उप-तहसील की घोषणा भी करके आये हैं। मुख्यमंत्री जी उसी रास्ते से गए थे। (विघ्न) आपने कहा है कि उस सड़क पर 82 लाख रुपया खर्च हो चुका है। खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह कोई सड़क है। वहां तक जाने में इनको डेढ़ घण्टा लग गया, लुहाणी से बहल और भिवानी से वाया तोशाम तक की सड़क भी बड़ी खराब है, जबकि वहां की खान से सरकार रोजाना 30 लाख रुपये का राजस्व ले रही है। वहां पर लोग पक्के पर चलने की बजाये कच्चे पर चलना ज्यादा पसन्द करते हैं। इसी प्रकार से जूंई से लेकर हांसी वाया कैरो-तोशाम की सड़कें देख लें तो शायद ऐसी किसी सड़क की खराब हालत नहीं होगी जो इनकी है। वहां से जाने वाले जितने भी व्हीकलज वाले हैं वे कोशिश करते हैं कि पक्की सड़क पर चलने की बजाये अगर कच्चे से चला जावे तो वह ज्यादा बेहतर है। जो नई सड़कें बन चुकी हैं जैसे भिवानी से जीन्द हो या भिवानी से तिगड़ाना और मुण्डाल की सड़कें हैं ये सड़के कम्पलीट होने से पहले ही टूट चुकी हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि सरकार इस बारे में एक हाई लैवल की

[श्री धर्मवीर सिंह]

ईक्वायरी करवा कर देखें कि ऐसा घटिया मैटिरियल क्यों लगाया गया और किसने लगाया। जिन-जिन अधिकारियों ने या ठेकेदारों ने घटिया मैटिरियल लगाया हो उनसे वह पैसा रिकवर किया जाये। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपनी नई परिवहन नीति जो लागू की है उससे भी लोग काफी परेशान हैं। इस नीति से खासकर डी०टी०ओ०, ए०डी०टी०ओ० जी०एम० हरियाणा रोड़वेज की और थानेदार को पता नहीं कैसा अधिकार दे रखा है कि जो गरीब बेरोजगार लड़के सूमों और जीप का लाईसैंस लेकर के अपनी गाड़ियां चलाते हैं उनको ये परेशान करते हैं जबकि उन्होंने टैक्स भी भरा हुआ है। ये लोग 5-5- हजार या 10-10- हजार रुपये का जुर्माना इन जीप वालों पर लगा रहे हैं। इस जुर्माने के डर से वे लोग जल्दी में चलते हैं और उन्हें डर होता है कि कहीं तुम्हें पकड़ न लें। इसी भागदौड़ में कई बार ऐक्सीडैन्ट भी हो जाता है। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि सरकार इस प्रकार के गलत चालान करके जो रिकवरी करते हैं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करके ऐसी कुप्रथा को बन्द करें। स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जमीन के नीचे का पानी खारा है और वहां पर नहर का पानी भी नहीं लगता है। मेरे हल्के में खासकर सिवानी सब-डिवीजन का जो इलाका बहल तक का है और बहल से भिवानी का जो इलाका है और वहां से वापस आते समय ढाणी माऊ तक जो एरिया है वह खारे पानी का एरिया है। वहां पर लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। अगर मैं गलत कहता हूँ तो हाउस की एक कमेटी जा करके निरीक्षण कर सकती है। वहां पर लोगों को पीने का पानी मोल लेना पड़ता है। सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हम लोगों को पीने का पानी 70 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से देंगे जबकि मेरे इलाके के लोगों को पीने का पानी मोल लेना पड़ रहा है। पीने का पानी न मिलने के कारण और गन्दा पानी पीने के कारण लोगों में कैंसर की बीमारी यानि हरियाणा प्रदेश में बड़ी भारी मात्रा में फैल रही है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह कोई छूत की बीमारी है।

श्री धर्मवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, छूत की बीमारी तो नहीं हो सकती है, पर यह बीमारी खान-पान और पानी स्वच्छ न मिलने के कारण बढ़ी है। कैंसर की बीमारी का प्रकोप आज ऐसा है कि हर गांव में इसके 2-4 मरीज आपको मिल जाएंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि इस बीमारी के लिए सरकार अलग से एक कोष की स्थापना करे ताकि जो गरीब परिवार के लोग हैं, वे अपनी कैंसर की बीमारी का इलाज करवा सकें। वे लोग अपनी जेब से कैंसर की बीमारी का इलाज नहीं करवा पाते क्योंकि इसकी दवाई बड़ी मंहगी होती है। एक ओर जहां हैल्थ मिनिस्टर की यह जिम्मेदारी है, तो सरकार की भी यह जिम्मेदारी है कि स्वास्थ्य की तरफ विशेष ध्यान दिया जाये। आज की सरकार ने इस बजट में एक व्यक्ति पर सिर्फ 2 रुपये 12 पैसे खर्च करने का प्रावधान किया है जो कि ना के बराबर है।

श्री अध्यक्ष : धर्मवीर जी, आप बैठिये। आपका समय समाप्त हो गया है क्योंकि आप पहले ही 15 मिनट बोल चुके हैं।

श्री धर्मवीर सिंह : स्पीकर सर, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। आज के दिन एक-एक गांव में 4-5 मरीज आपको कैंसर की बीमारी के मिल जाएंगे और इस बीमारी के कारण एक-एक गांव में 5-5- कैजुअल्टी हो चुकी हैं। इन लोगों को अपना इलाज करवाने के लिए अपनी जमीन भी बेचनी पड़े तो भी ये उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते कि इस बीमारी का इलाज करवा सकें।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि देश में दो बीमारियां बड़ी

घातक थी। एक कांग्रेस और दूसरी कैंसर। ये दोनों बीमारियां हरियाणा में भी थीं। अब कांग्रेस को तो खत्म कर दिया गया है यानि कांग्रेस नाम की बीमारी तो खत्म हो गई है। जो यह कैंसर वाली बीमारी रह गई है इसको भी खत्म कर देंगे।

श्री धर्मवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मैं आपके माध्यम से यह प्रार्थना करना चाहूँगा कि जहां जर्मनी से भी 8 करोड़ रुपये की सहायता मिली है और यूरोपियन कण्ट्रीज से भी सहायता मिली है और स्वास्थ्य मन्त्री जी ने भी बताया है कि ऐलोपैथिक दवाईयों के लिए 5 करोड़ 70 लाख रुपये का बजट रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से यह कहना है कि कम से कम ऐसी जो बीमारियां हैं उनके लिए अलग से कुछ बजट का प्रावधान जरूर करे ताकि गरीब बीमार लोगों को मरने से बचाया जा सके और उनका इलाज हो सके। (विघ्न)

13.00 बजे

श्री अध्यक्ष : धर्मबीर जी, अब आप बैठें। (विघ्न)

श्री धर्मवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूँ इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे दो मिनट का समय और देने की कृपा करें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: धर्मवीर जी, आप का समय समाप्त हो चुका है इसलिए अब आप अपनी सीट पर बैठें।

श्री धर्मवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, xxxx xxxx xxxx

श्री अध्यक्ष : धर्मवीर जी, अब आप अपनी सीट पर बैठें। धर्मवीर जी अब जो बोल रहे हैं वह बिना परमिशन के बोल रहे हैं इसलिए अब इनकी कोई भी बात रिकॉर्ड न की जाए।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : (बल्लभगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने के लिए समय दिया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट सदन में पेश किया है यह बजट सारे हरियाणा प्रदेश के हितों को देखते हुए, प्रदेश के सभी वर्गों के उत्थान और कल्याण को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। यह बजट बहुत निष्पक्ष और सारे हरियाणा प्रदेश की जरूरतों के मुताबिक तैयार किया है। जब से हरियाणा बना है तब से लेकर आज तक प्रो० सम्पत सिंह जी वित्त के बारे में सबसे अच्छे प्रोफैशनल एक्सपर्ट हैं और बहुत ही योग्य, ईमानदार, कर्मठ एवं निष्ठावान मंत्री हैं। सारे हरियाणा प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने यह बजट पेश किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे सभी सम्मानित सदस्यों ने अपने–अपने ढंग से अपने विचार सदन में रखे हैं लेकिन मुझे खेद के साथ यह बात कहनी पड़ती है कि किसी भी माननीय साथी ने यह सुझाव नहीं रखा कि किस प्रकार से प्रदेश के लिमिटिड सोर्सिज़ का प्रयोग किया जाए जिससे सरकार के पास ज्यादा पैसा आए और उस पैसे से प्रदेश के विकास के कार्यों को और तेज गति दी जाए। अध्यक्ष महोदय, कई साथियों ने कहा कि बजट खराब है। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि जो इक्नोमिक सर्वे ऑफ हरियाणा 2003–04 यहां पर सदन के पटल पर रखा गया है इसमें मैंशन किया गया है—The Financial Management of State Government has been termed as one of the best in the country by both the Planning Commission and the Eleventh Finance Commission. अध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा प्रदेश के लिए और हमारी हरियाणा सरकार के लिए यह बड़े फख्र और गौरव

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री राजेन्द्र सिंह बिसला]

की बात है। हरियाणा प्रदेश की सरकार को यह एक सर्टिफिकेट और प्रमाण-पत्र दिया गया है हम सभी के लिए यह बड़े ही गर्व की बात है। इसमें आगे यह मैंशन किया गया है। The notable feature of the State Financial Management is that Haryana is the first State in the country which has not availed overdraft facility even for a single day during the current financial year. अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी एजैन्सिज़ हैं जो सारे भारत वर्ष के फाईनांशियल सिस्टम के बारे में अपनी ओपिनियन जाहिर करती हैं। अध्यक्ष महोदय, आज इतनी सुन्दर व्यवस्था है कि किसी भी वर्ग पर एक नया पैसे का टैक्स नहीं लगाया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह सरकार हरियाणा में चहुंमुखी विकास कर रही है और यह प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए वित्त मंत्री जी ने यह बजट पेश किया है। मैं पुन: वित्तमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा और एक बात कहना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन में ऊंचे पद पर सुशोभित हैं और आप दूसरी कंट्रीज में भी टूर पर गए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ दूसरे कई साथियों को भी बाहर की कंट्रीज में जाने का मौका मिला है। यहां पर कई साथी कहते थे कि घूमने-फिरने के लिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आज किस आदमी के पास इतना टाईम है कि अपने बिजी शैडयूल से टाईम निकाल कर घूमने-फिरने के लिए जा सके। हम लोग दूसरी कंट्रीज में स्टडी टूर पर गए थे और वहां के सिस्टम के बारे में अच्छी चीजें सीखने के लिए गए थे। हमारी डैमोक्रेसी बधाई की पात्र है जिसकी वजह से इस प्रदेश के अन्दर अच्छे कार्यक्रम और अच्छी पॉलिसिज़ बनाई हैं, उसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। उन पॉलिसिज को देखकर राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री जी ने दूसरी स्टेट्स को यह राय दी कि आप हरियाणा में जाकर उनकी पॉलिसिज देखें और वहां की सरकार से उन पॉलिसिज के बारे में विचार विमर्श करें। इन सब के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा मैं सदन के दूसरे साथियों को यह सुझाव देना चाहूँगा कि वे सदन में बोलते हुए अच्छे सुझाव दें और आदरणीय मुख्यमंत्री जी अच्छे सुझावों को मानते भी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जहां पर जरूरत हो तो वहां पर टैक्स लगाने भी चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, मुझे भी साउथ अफ्रीका में जोहन्सबर्ग में जाने का मौका मिला था। वहां पर एक सनसिटी शहर है। वहां पर कोई अच्छी जमीन नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है और न ही कोई नैचुरल फाल है, लेकिन उन्होंने वहां पर एक पार्क बनाया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जिस आदमी की पाकेट अलाऊ करती है, वह ही वहां पर जाता है। जिसकी वजह से वहां की सरकार को करोड़ों रुपए का टैक्स मिल रहा है। इसी तरीके से हमारा गुड़गांव दिल्ली के साथ लगता है और दिल्ली में काफी बड़े-बड़े लोग रहते हैं, दिल्ली में एम्बैसीज़ हैं, वहां पर फारेन के लोग इत्यादि आते रहते हैं और वे पैसे भी खर्च कर सकते हैं। गुड़गांव में सुप्रीमकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार माईन्ज का काम भी बंद कर दिया गया है। ऐसी जगहों पर एयर फील्ड बन सकता है और अगर वहां पर एम्यूजमैंट पार्क बनाएं तो वहां पर लोग अपने सोर्स ऑफ इन्कम के हिसाब से पैसा लगा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, डिजनीलैंड के बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी की बहुत पहले प्रपोजल थी। मैं इसको कोरा-कोरा दुर्भाग्य कहूँगा कि फार दि सेक ऑफ अपोजीशन लोगों ने इसका विरोध किया था और समाज को तोड़ दिया था। कुछ लोग मानते हैं कि हमें तो केवल मुखालफत करनी है चाहे 80 प्रतिशत समाज कुएं में गिर जाए। वे यह नहीं सोचते कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, एस०सी० क्लासिज के लोग हैं या बैकवर्ड क्लासिज के लोग है उनका उत्थान हो। काश, उस समय अगर यह डिजनीलैंड बन गया होता तो उससे आज कम से कम 400-500 करोड़ रुपये हमारे स्टेट के खजाने के लिए आते। जिन लोगों ने उस समय झंडा उठाकर

इसकी मुखालफत की थी, उनमें से कुछ वकील आज भी हमें मिलते हैं और हमसे कहते हैं कि बिसला जी, हमने उस समय बिना सोचे समझे इसकी मुखालफत की थी और हम आज अपनी उस बात के लिए पछताते हैं। मैंने उनसे कहा कि आपको समझदारी से काम करने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे हरियाणा प्रदेश के साथ जो राष्ट्रीय राजधानी तीन तरफ से लगी हुई है तो उसको देखते हुए हमें इस प्रकार का ढांचा खड़ा करना चाहिए ताकि पैसे वाले आदमी हरियाणा की तरफ आकर्षित हों और उनसे सरकार के खजाने में पैसा आए तथा लोगों को रोजगार भी मिले। जब पैसा होगा तो जो हमारा कमजोर वर्ग है उसके कल्याण के लिए पैसा खर्च होगा इस तरह से उसका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। आज इस कमजोर वर्ग के कल्याण पर ज्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। आज सारे हरियाणा में जो टोटल महिलाएं हैं उनमें से 25 फीसदी महिलाएं अनपढ़ हैं। अध्यक्ष महोदय, पचास साल देश को आजाद हुए हो गये और धीरे-धीरे हरियाणा पहले से ज्यादा मोस्ट एडवांस और प्रोग्रेसिव स्टेट कहलाने लग गया है। हम भी यह बात मानते हैं लेकिन यह बात भी सही है कि आज भी हमारे समाज में पचास फीसदी महिलाएं अनपढ़ हैं। इसी तरह से जो हमारा लिंग अनुपात है वह भी काफी चिंतित करने वाला है। एक हजार पुरुषों के पीछे 861 महिलाएं हैं यानि बहुत ही गंभीरता वाली यह बात है लेकिन मैं अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने पहली बार ऐसे इशु को उठाया है और अब लोग धीरे-धीरे जागृत हो रहे हैं। अगर इस तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया गया तो समाज में डिसपैरिटी पैदा हो जाएगी और बड़ी भारी लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रौब्लम हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि आप कहने वाले हैं कि आपका समय समाप्त हो गया है इसलिए आप बैठिए लेकिन मैं जल्दी ही अपनी बात कहकर समाप्त करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, जो इकोनोमिक सर्वे है इसमें चैप्टर 6 है इसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसमें दिया हुआ है कि Housing sites allotted इसमें 2500 थे यानी इसका जो टारगेट है वह अभी तक 86 फीसदी फुलफिल हुआ है, इसी तरह से Construction of residences का टारगेट भी पूरा नहीं हुआ है। इसी प्रकार से इंदिरा आवास योजना है। आज भी समाज का जो गरीब वर्ग है जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है वह अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के पास आकर कहता है कि मुझे भी ऐसा मकान दिलवा दो जिसके ऊपर पक्की छत हो। इस तरह से ये काफी टारगेटस हैं जोकि काफी शोर्ट हैं। इसी तरह से एल०आई०जी० हाउसिज की बात है और इसी तरह से और दूसरे भी हैं। मेरा आपके माध्यम से सम्पत सिंह जी से निवेदन है कि हमारे विकास कार्यों की गति रुकनी नहीं चाहिए, वह तेज होनी चाहिए। प्रदेश के विकास के लिए जो हमारी जरूरतें हैं वहां पर हमें ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए और समाज का जो सर्वांगीण विकास है वह किया जाना चाहिए क्योंकि अगर समाज में बहुत ज्यादा डिसपैरिटी होगी, अगर एक आदमी में दूसरे आदमी के मुकाबले बहुत ज्यादा डिसपैरिटी होगी तो इससे हमारे देश में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। आजादी के पचास साल बाद भी अगर एक आदमी के मुकाबले दूसरे आदमी में ज्यादा फर्क है तो इसको हमें बहुत चुनौती के रूप में मानना चाहिए। हम सभी नेताओं को और सारे हमारे अधिकारियों को यह जो एक बहुत ज्यादा फर्क है इसको हमें दूर करना चाहिए। सम्पत सिंह जी का एक लम्बा राजनीतिक जीवन है, सम्पत सिंह जी भाग्यशाली हैं कि इन्हें राजनीतिक ट्रेनिंग श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी के चरणों में बैठकर मिली है इन्होंने उनसे अच्छे संस्कार लिए हैं जिसको अपनी स्टूडैंट लाइफ में एक अग्रिम पंक्ति के फ्रीडम फाइटर से प्रेरणा मिली है, जिन्होंने देश को आजाद कराया उसमें चौ० देवी लाल जी अग्रिम पंक्ति के योद्धा थे। वे हरियाणा व पंजाब के बच्चों से मिलते थे। सम्पत सिंह जी ने ऐसी राष्ट्र धरोहर के साथ बैठकर संस्कार लिए और इनकी वही सोच इस बजट में

[श्री राजेन्द्र सिंह बिसला]

झलक रही है। इन शब्दों के साथ हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है इसकी दोबारा से प्रशंसा करते हुए मैं इनको और सरकार को बधाई देता हूँ कि एक बहुत अच्छा बजट पेश किया।

श्री अध्यक्ष : कांग्रेस की तरफ से एक सप्लीमैंट्री लिस्ट आई है उसमें राव धर्मपाल का नाम है, अनीता यादव का नाम है। ये दोनों सदस्य बैठे नहीं हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, वे आपकी आज्ञा से लंच के लिए गए हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है अब डॉ० रघुबीर सिंह कादियान बोलेंगे।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान (बेरी) : अध्यक्ष महोदय, जिस समय वित्त मंत्री जी ने इस सदन में बजट पेश किया उस समय दुर्भाग्य से मैं सदन में हाजिर नहीं था क्योंकि आपने मुझे किसी बात के लिए नेम कर दिया था। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने फैसले को रिकंसीडर करके मुझे वापस बुलाया। स्पीकर साहब, बजट ऐट-ए-ग्लांस देखने के बाद और यह किताबें देखने के बाद मैं वित्त विभाग के अधिकारियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी बोल्डली सारी बातें दी हैं चाहे कुछ खामियां थीं या अच्छाइयां थीं, सब कुछ उसमें ठीक ढंग से दर्शाया गया है। जब हम एक नजर बजट पर डालते हैं, वैसे कोई महारत तो हमें नहीं है, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बहुत देखने से जब एक झलक बजट पर पड़ती है तो उसमें सारा का सारा जो प्लान है, उसको कर्जों से पूरा करने की नीयत साफ झलकती है। पांच बजट चौधरी सम्पत सिंह जी ने विधान सभा में पेश किए हैं। जब 2000-2001 का बजट पेश किया था तो उस समय एनुअल प्लान का आकार 2530 करोड़ रुपये दिया था और 39-40 प्रतिशत इन्क्रीज दिखाई गई थी और सत्तापक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गई थीं और वह एनुअल प्लान आगे जाकर औंधे मुंह गिर कर रिवाईज्ड एस्टिमेट में 1815 करोड़ रुपये पर पहुंच गई थी। स्पीकर सर, इसी तरह से उसमें जो डाउन फाल तकरीबन 700 करोड़ रुपए का हुआ था। इस छोटे से प्रदेश की इतनी हैसियत नहीं थी कि उसकी एनुअल प्लान इतनी कम हो। उसके बाद वर्ष 2001-2002 में जो एनुअल प्लान रखी उसमें 2150 करोड़ रुपये की रखी गई थी और उसका रिवाईज्ड एस्टिमेट 1832 करोड़ रुपये पंहुच गया। तीसरी प्लान 2002-2003 की 1922 करोड़ रुपए की थी, जो रिवाईज्ड एस्टिमेट में 1800 करोड़ पर पहुंच गई और 2003-2004 में जो एनुअल प्लान 2120 करोड़ रुपये की थी, वह रिवाईज्ड एस्टिमेट में 1850 करोड़ रुपये रह गई। इसलिए जो प्लान अब रखी गई है वह 2004-2005 की उस 2175 करोड़ रुपये रखी गई है और पिछले ट्रैंड के हिसाब से फाईनैंशियल मैनेजमैंट नाम की कोई चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। जिस ढंग से एनुअल प्लान का आकार घट रहा है और डाऊन फाल होकर 1800 करोड़ रुपये पर आ गई है तो लगता है कि रिवाईज्ड एस्टिमेट 1800 करोड़ रुपये से भी कम हो जायेगा। अगर आप इसकी एक्चुअल वैल्यू लगाओगे तो 5-6 प्रतिशत इसमें इन्फलेशन भी होगी। इसके मुकाबले में जो इस सरकार ने बजट पेश किया है उसके बाद तो उस समय 1815 करोड़ रुपये की एनुअल प्लान आई थी उसकी एक्चुअल वैल्यू 1200-1300 करोड़ रुपये रह गई है। इन्फलेनेशन की साफ बात इसमें नजर आती है। चौधरी सम्पत सिंह एक काबिल मैन हैं, पढ़े लिखे हैं और इन्होंने लगातार पांचवा बजट पेश किया है। लेकिन जब बजट पेश किया जाता है तो उसका कवर नोट एक तरह का होता है जिस पर लिखा होता है कि हरियाणा का बजट प्रजैंटिड बाई प्रो० सम्पत सिंह लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशन इस बजट में साफ नजर आती हैं। शायद लिमिटेशन रही होंगी क्योंकि फाईनैंशियल मैनेजमेंट के कारण कई बार कुछ निर्णय लेने होते हैं। जिस तरह से बिसला साहब ने फाईनैंशियल ऐड की भारत सरकार

की बात कही। उसमें क्या रखा है। भारत सरकार का प्लानिंग कमीशन आता है और राज्य सरकार अपनी प्लान उसके सामने रखती है और प्लानिंग कमीशन उस प्लान में से कट कर देता है क्योंकि प्लानिंग में टैक्स की कम्प्लायंस नजर नहीं आ रही थी। प्लानिंग कमीशन के सामने जो प्लान सरकार ने रखी थी उसको कट कर दिया है दुर्भाग्य इस बात का है कि 2004-2005 की प्लान अभी तक पास ही नहीं हुई है और सरकार ने बजट पेश कर दिया है जबकि दूसरे राज्यों ने इस वर्ष की अपनी प्लान पास करवा ली है। यह एक सीरियस मैटर है। सैंट्रल फायनैंस कमीशन जो ऐड देता है वह भी सरकार को नहीं मिल रही है जबकि सरकार के पास कर्ज लेने के सिवाए कोई चारा नहीं है क्योंकि खुद सरकार इस बात को मान रही है कि वित्त कमीशन को केन्द्र सरकार की तरफ से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है। धर्मवीर सिंह जी ने ठीक फरमाया इसके लिए सरकार को चाहिये कि एक निन्दा प्रस्ताव इस सदन में पारित करके भारत सरकार को भेजा जाये कि हमारे साथ यह भेदभाव क्यों हो रहा है केन्द्रीय एजैन्सी से हमें हमारी सहायता नहीं मिल रही है। मैं भी, जो धर्मवीर सिंह जी ने निन्दा प्रस्ताव के बारे सुझाव दिया है उसको सैकेण्ड करता हूँ। इसके साथ-साथ स्पीकर सर, अब मैं बजट-एट-ए-ग्लांस के बारे में कहना चाहूँगा। प्रो० सम्पत सिंह जी ने जो बजट 2001 में रखा था उसमें नॉन प्लान एक्सपैंडीचर टोटल बजट का 75 प्रतिशत था, 2001-02 में नॉन प्लान एक्सपैंडीचर टोटल बजट का 78 प्रतिशत था, 2002-03 में 80 प्रतिशत था और उसके बाद 2003-04 में नॉन प्लान एक्सपैंडीचर टोटल बजट का 83 प्रतिशत हो गया। जो यह बजट रखा है इसमें इन्होंने टोटल रिसीप्टस 12,390 करोड़ रुपये की दिखाई हैं और नॉन प्लान एक्सपैंडीचर 10,028 करोड़ रुपये के दिखाएं हैं इससे साफ झलकता है कि नॉन प्लान एक्सपैंडीचर 85 प्रतिशत तक चला गया है। अध्यक्ष महोदय, यह लगातार बढ़ रहा है, fiscal deficit इनके कंट्रोल से बाहर चला गया है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2004-2005 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा
(पुनरारम्भ)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, क्रोस डोमैस्टिक प्रोडैक्ट के बारे में वित्त मंत्री जी ने बजट में माना है कि यह नीचे चला गया है, however, मार्जनली चला गया लेकिन Economic Survey of Haryana 2003-2004 के पेज संख्या 2 पर लिखा है कि Structural composition of the State's economy revealed that Primary Sector in Gross Product decreased marginally by 0.8 per cent. "Contribution of Secondary Sector" यह अलग बात है। ग्रोस डोमैस्टिक प्रोडैक्ट घट रहा है और ये कह रहे हैं कि वैल्यू पर कैपिटा बढ़ रही है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि वैल्यू पर कैपिटा कितनी बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी ही सीरियस बात है कि प्रदेश ऐसी हालत से गुजर रहा है, जहां पहले इस प्रदेश को दुनिया में जाना जाता

[डॉ० रघुबीर सिंह कादियान]

था कि प्रदेशों में प्रदेश हरियाणा, जहां दूध दही का खाणा। जिस धरती पर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था उस धरती पर वित्तीय मैनेजमैंट अच्छी नहीं है। यह सब किस कारण हुआ इसके कारण साफ नजर आते हैं। यह सब चाहे टैक्सिज चोरी के कारण हुआ हो, चाहे क्रप्शन के कारण हुआ हो।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आप वाईंड-अप करें।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, क्रप्शन का मामला है। हरियाणा में हर महीने 600 करोड़ रुपये की क्रप्शन हो रही है। वह पोलिटीकल लोगों के हाथों से हो रही है। अफसरों के हाथों से हो रही है। चाहे ठेकों और माईन्ज की ऑक्शन की बात हो, हर जगह क्रप्शन हो रही है। रजिस्ट्रीज कम कीमतों पर की जा रही हैं। हरियाणा प्रदेश दिल्ली के तीन तरफ लगता है और हजारों करोड़ रुपये का सामान इधर-उधर से आता है, बिकता है लेकिन उसके टैक्स की चोरी होती है। इस टैक्स चोरी को रोकने के लिए पोलिटीकल विल की बात है, पोलिटीकल मजबूती की बात है। अध्यक्ष महोदय, यह मैं मानता हूँ कि प्रोफेसर साहब बड़े ही काबिल वित्त मंत्री हैं। कई बजट इन्होंने प्रस्तुत किए हैं और बहस की है तथा बड़ी ही टैक्नीकली, प्रैक्टीकल बहस की है और बड़े ही अच्छे सुझाव भी दिए हैं लेकिन अब इनकी बस की बात नहीं लग रही क्योंकि बजट बनाने वाले से बजट इम्पलीमैंट करने वाले की बात अधिक चलती है। स्पीकर साहब, अब जगह-जगह घोषणाएं होती हैं। मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर तो कोई स्पीड ब्रेकर है नहीं। जहां गए वहां हालात देखे और लोग इकट्ठा हो गए तो वहां पर ही घोषणाएं हो गईं। ऐसी घोषणाएं हो जाने पर वित्त मंत्री जी के लिए मुश्किल होता है कि उन पर अमल कैसे हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सम्मुख इस बजट के पृष्ठ 2 पर जो लिखा गया है वह पढ़कर सुनाता हूँ। इस बजट में इन्होंने लिखा है। But the structural composition of the State's economy revealed that primary sector, which includes agriculture, continues to be the dominant sector despite the fact that its contribution has declined to 29.4 per cent in 2002-03 from 42.5 per cent in 1993-94. स्पीकर साहब, यह सीधा इस बात को दर्शाता है कि (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अभय जी हँस रहे हैं। इसमें सच्चाई यह है कि---

श्री अभय सिंह चौटाला : ऑन ए प्वायंट ऑफ ऑर्डर सर। मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को बताना चाहूँगा कि मैं आपकी बात पर नहीं हंस रहा था। आपने अभी तक किसी किस्म के सुझाव नहीं दिये। मैं वित्त मंत्री जी के पास बैठा था। इन्होंने आपका नाम लिख रखा था और इसमें आगे लिख रखा है-सुझाव। मैं उसको देख कर हँस रहा था कि आपने इतनी देर तक कोई सुझाव नहीं दिये। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि आपने अपनी बात कहने के बाद लॉस्ट में विरोध ही करना है। आपने जो पी०एच०डी० की डिग्री हासिल की है उस वक्त मैं भी उस यूनिवर्सिटी का सदस्य था। आपने किताबें पढ़ कर पी०एच०डी० हासिल की है। जबकि इस बजट को पढ़ करके आप कह देंगे कि मैं तो इसका विरोध करता हूँ। जब आपने विरोध ही करना है तो फिर समय क्यों खराब कर रहे हो।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि सुझाव आने चाहिएं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हिन्दुस्तान की जो एग्रीकल्चर की इकोनामी है उसमें हरियाणा प्रदेश का जो कन्ट्रीब्यूशन है वह लोडेबल कन्ट्रीब्यूशन है, कान्सीडेबल कन्ट्रीब्यूशन है। उसी कन्ट्रीब्यूशन

की वजह से आज देश के अनाज के भण्डार भरे हैं। इसमें जो सीरियस बात है कि वर्ष 2002-03 में डोमिनैंट केवल 29.4 परसेंट का कन्ट्रीब्यूशन रह गया है जबकि 93-94 में यह 42.05 था। इसका सीधा मतलब यह दिखता है कि सरकार का जो कन्ट्रीब्यूशन है वह घाटे का है जबकि आज सारी टैक्नोलोजी बढ़ी है। आज सारे मामले बढ़े हैं। आपकी तरफ से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक नहीं हो रहा और पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में एक ख़ास इलाके के साथ डिस्क्रीमिनेशन है। हम रिजनेलिज्म में विश्वास नहीं रखते लेकिन किसी एक इलाके के साथ अगर डिस्क्रीमिनेशन हो रहा है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि इलाके से प्रदेश बनता है और प्रदेश से देश बनता है। तो मेरा कहना यह है कि किसी इलाके के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हम जहां बैठे हैं यह हरियाणा सरकार की सबसे बड़ी पंचायत है।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप एक मिनट में वाईड-अप करें। (विघ्न)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं तो आज ही आया हूँ और एक डेढ़ दिन तो मैं बाहर था। अध्यक्ष महोदय, आज फिस्कल डैफिशिट कण्ट्रोल से बाहर चला गया है और यदि यही हाल रहा तो कुछ समय बाद बजट पेश करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। प्लॉन एक्सपैंडिचर खत्म हो रहा है और सारा का सारा मामला कर्जों पर आधारित है। कर्ज लिये जा रहे हैं और ब्याज, तनख्वाहें और पैंशन दिये जा रहे हैं। अगर सारा का सारा प्लॉन एक्सपैंडीचर इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो मेरे हिसाब से चार-पांच साल के बाद बजट पेश करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जब अगली सरकार आएगी तो वह इन सारी बातों को देखेगी। स्पीकर साहब, किसी वर्ग को अप-लिफ्ट करने की, किसी वर्ग का उत्थान करने की कोई भी बात इस बजट में नहीं कही गई है। मेरा सुझाव यह है कि इसमें किसानों के हितों की बातें रखनी चाहिए थीं क्योंकि आपको मालूम है कि किसान का इनपुट आज बढ़ रहा है और कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस घटती जा रही है। होल्डिंग ज्यादा और अनइकोनोमिकल बनती जा रही है और जमीन पर पापुलेशन का बर्डन बढ़ता जा रहा है, ऐसे समय में अगर डिस्क्रिमिनेशन इन अन-इक्विटेबल डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ वाटर होगी तो किसान के उत्थान का रास्ता क्या होगा। पिछले बजट में भी मैंने यह सुझाव दिया था कि सरकार इस ओर ध्यान दे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, अब आप बैठें, आपको दिया गया समय समाप्त हो गया है। (विघ्न)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करके बैठ जाऊंगा इसलिए आप मुझे दो-तीन मिनट बोलने के लिए और समय दे दें।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, अब आप बैठें। (विघ्न)

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री कंवर पाल (छछरौली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में जो अच्छी बातें कही गई हैं उनके लिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ। इस बजट में स्टॉम्प ड्यूटी घटाई गई है, यह बहुत अच्छी बात है और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। जहां तक इस सरकार का यह कहना है कि यह सरकार किसानों की सरकार है, यह बात किसानों के साथ बहुत बड़ा मजाक है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के अन्दर एक दुकानदार था और उसने दुकान का नाम रखा हुआ था किसान सेवा केन्द्र लेकिन वह किसानों को नकली खाद बेचता था। वह किस प्रकार की सेवा किसानों की कर रहा था इसका अन्दाजा आप स्वयं ही लगा सकते हैं और वैसे ही यह सरकार किसानों की सरकार है। इस

[श्री कंवर पाल]

सरकार ने फसल बीमा योजना पहले तो लागू ही नहीं की और जब फसल बीमा योजना लागू की तो उसमें 70 प्रतिशत जमीन पर जो खेती होती है यानि गेहूँ, गन्ना और धान इन फसलों को बीमा से अलग कर दिया गया है। किसानों के साथ यह बहुत बड़ी बेइन्साफी है। दूसरे टयूबवैल्ज़ के कनैक्शन्ज़ की बात है, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि इतने टयूब्वैल्ज़ के कनैक्शन्ज़ तत्काल स्कीम के अन्तर्गत हमने दिए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ कनैक्शन्ज़ दिए गए हैं लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि 1985 से जिन लोगों ने कनैक्शन्ज़ के लिए सिक्योरिटीज़ भरी हुई थी, उनके कनैक्शन्ज़ की क्या व्यवस्था है और उनको कब तक कनैक्शन्ज़ दिये जाएंगे? मेरा निवेदन है कि उन लोगों को कनैक्शन्ज़ देने की व्यवस्था करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बार-बार यह कहते हैं कि हम 50 हजार नौजवानों को रोजगार देने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन मुझे यह नहीं लगता है कि वित्त मंत्री जी ने बजट में कहीं पर भी इसके लिए कोई व्यवस्था की है कि ये कहां से रोजगार देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार बार-बार दावा करती है कि यह किसानों की सरकार है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिला यमुनानगर में नारायणगढ़ शूगर मिल और भादसों शूगर मिल में गन्ने के रेट देने में किसानों के साथ बहुत भेद-भाव किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। मैं उस अन्याय की तरफ इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यह सरकार उन किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। जब भी कोई मुख्यमंत्री जी से मिलने जाता है तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी उनसे व्यवहार करते हैं, उस बारे में मेरे लोकदल के साथी भी जानते हैं। हालांकि वे बाहर तो उनके व्यवहार की आलोचना करते हैं लेकिन सदन में इस बारे में कुछ नहीं कहते हैं। मैं इनके इस व्यवहार की निन्दा करता हूँ।

चौ० नफे सिंह राठी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। मैं आपके माध्यम से माननीय साथी से यह जानना चाहता हूँ कि केन्द्र की सरकार ने गन्ने का क्या रेट निर्धारित किया है?

श्री कंवर पाल : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र की सरकार ने जो रेट गन्ने के निर्धारित किए हुए हैं वे सभी स्टेट्स में लागू होते हैं। लेकिन गन्ने के रेट मुख्यमंत्री जी ने जो घोषित किए हैं वे हरियाणा में केवल 75 प्रतिशत एरिया में ही दिए जा रहे हैं। मैं यमुनानगर में उन रेट्स को लेने की बात कर रहा हूँ कि वे रेट्स वहां के किसानों को भी मिलने चाहिएं। एक ही प्रदेश में किसी किसान को कुछ रेट मिले और किसी किसान को कुछ रेट मिले, यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं सरकार का एक दूसरी बात पर भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ और सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने धन अर्जित करने के लिए सोर्स बढ़ाए हैं। इस सरकार ने माईनिंग के क्षेत्र में एक जोन सिस्टम खड़ा कर दिया है, यह बात तो ठीक है कि वहां पर रॉयल्टी एक करोड़ रुपये की थी और आपने उसको चार करोड़ में दे दिया है। लेकिन जिस प्रकार से वहां पर आम आदमी का शोषण हुआ है, वह विचारणीय बात है। इस बात को देखकर और आपकी सारी व्यवस्था को देखकर शक की सूई सरकार की ओर घूमती है। उपाध्यक्ष महोदय, जो रायल्टी थी वह 30 या 40 जगहों पर ली जाती थी लेकिन इस सरकार ने उसको एक जगह पर कर दिया है। इस सरकार की मंशा क्या है, आप इस बारे में आम आदमी से जाकर पूछें क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, आम आदमी यह कहता है कि इस सरकार ने केवल ******। यह सरकार ने सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि ***** के लिए किया है।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : कंवर पाल जी ने जो अनपार्लियामैंट्री बात कही है वह रिकॉर्ड न की जाए।

श्री कंवर पाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली दफा भी यह बात उठाई थी और निवेदन भी किया था कि आने वाले समय में जो बोली होने वाली है, उस बोली के सिस्टम को समाप्त किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं सरकार का ध्यान एक और बात की तरफ दिलाना चाहूँगा कि बी०पी०एल० की गेहूँ गरीब आदमी को मिलती थी लेकिन इस सरकार ने निर्णय लिया है कि अब उनको गेहूँ नहीं देंगे बल्कि आटा देंगे। यह सरकार मुझे यह बताए कि ये आटा क्यों देना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से सदन में यह बताना चाहता हूँ कि यह सरकार केवल इसलिए आटा देना चाहती है क्योंकि आटा पीसने में कमीशन खाया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी गेहूँ को कहीं पर भी पिसवा सकता है। इसके साथ में मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, सदन में यह भी बताना चाहूँगा कि बी०पी०एल० का गेहूँ 50 प्रतिशत से ज्यादा ब्लैक मार्किट में बेचा जा रहा है। इस बारे में आप इन्क्वायरी करवा लें। उपाध्यक्ष महोदय, आज तक मैंने यह बात सुनी थी कि लोग कफन तक बेच देते हैं लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं था। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह सरकार कर रही है वह बिल्कुल कफन बेचने जैसी बात है कि ये गरीब आदमी का गेहूँ बेच कर खा गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट में 'वैट' की बात कही गई है। मैं मानता हूँ कि सरकार ने आमदनी बढ़ाई है। लेकिन मैं इनसे यह कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में वैट लागू नहीं है तो आप हरियाणा में वैट क्यों लागू कर रहे हैं। यहां पर उपभोक्ताओं का और व्यापारियों का शोषण हो रहा है।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। मैं आपके माध्यम से माननीय साथी से यह जानना चाहता हूँ कि वैट की क्या परिभाषा है, वैट क्या है और किस तरीके से वैट से सरकार को फायदा होता है, उपभोक्ता को फायदा होता है और कंवर पाल जी, आपकी तरह के मिडिल मैन को फायदा होता है।

श्री कंवर पाल : उस फायदे के बारे में तो जब धान की बिक्री हुई थी तो सबको पता लग गया होगा और आपको भी पता लग गया होगा। इससे किसानों को क्या फायदा होगा। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के नोर्म्ज फिक्स किए हैं। मुझे नहीं लगता है कि आज सरकार के पास इतनी व्यवस्था है कि अगर आज प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया जाए तो यह सरकार सभी बच्चों को सरकारी स्कूलों में एजुकेशन दे पाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : कंवर पाल जी, आप गवर्नर एड्रैस पर नहीं बल्कि बजट पर बोल रहे हैं आप आंकड़े दें कि किस चीज पर क्या हो रहा है। इसकी तरफ आपको ध्यान रखना चाहिए।

श्री कंवर पाल : हाँ जी, मैं सुझाव ही दूँगा। जिस प्रकार से इन स्कूलों को बंद किया गया है और प्राईवेट स्कूलों के जो नोर्म्ज लागू किए गए हैं वे गलत हैं। अभी मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया था उसने मुझसे कहा कि आपकी सरकार क्या कर रही है? उसने कहा कि मैं स्कूल चलाकर बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ लेकिन आपकी सरकार उसको बंद कर रही है। उसने यह भी कहा कि मेरे स्कूल की बराबर में दो सट्टे की दुकानें तो चल रही हैं लेकिन सरकार उन सट्टे की दुकानों को बंद न करके मेरे स्कूल को बंद कर रही है जबकि मैं तो शिक्षा दे रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ। आखिर मैं क्या अपराध कर रहा हूँ? इस तरह से सरकार ने इस बारे में जो नोर्म्ज स्थापित किये हैं मैं कहता हूँ कि वे

[श्री कंवर पाल]
नोर्म्ज सही नहीं हैं क्योंकि इससे बड़ी भारी मुश्किल गांवों में हो जाएगी।

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह बताना चाहता हूँ कि जो इन स्कूलों के बारे में नियमावली लागू हो रही है तो वह बच्चों के और इस हरियाणा के भविष्य को ध्यान में रखकर ही लागू हो रही है। यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। जो दुकान दो सौ गज या पांच सौ गज में चल रही थी और जिन्होंने सीनियर सैकेंडरी स्कूल की मान्यता ली हुई थी उनके लिए अब नोर्म्ज फिक्स कर दिए गए हैं। क्या यह ठीक है कि दस बाई दस के एक कमरे के अन्दर स्कूल चले? क्या यह अच्छी बात है? इसलिए आपको कम से कम सरकार की इस बात के लिए सराहना करनी चाहिए कि इस तरह के नोर्म्ज बना दिए गए हैं। इससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा इसलिए आप इस तरह की बातें न करें। धन्यवाद।

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने भी गलत नहीं कहा है क्योंकि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। अब इनकी चाबी तो निकल गयी है इसलिए अब इन्होंने दूसरी लाईन पकड़ ली।

श्री कंवर पाल : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने बड़ी व्यवस्था की बात कही है कि यह अच्छा काम किया है। मेरे हल्के में एक राईयावाला गांव है उस गांव के स्कूल में सात अध्यापक होने चाहिएं लेकिन वहां पर एक भी अध्यापक नहीं है तो ये कैसी व्यवस्था चलाना चाहते हैं कैसी एजुकेशन देना चाहते हैं? आप उस दुकान को तो बंद करना चाहते हैं जो पचास रुपये में एक व्यक्ति को एजुकेट कर रही है और आप उस दुकान को चलाना चाहते हैं जो साढ़े तीन सौ रुपये में एक बच्चे को पढ़ा रही है। इसलिए अब यह आपको देखना है कि आप कौन सी दुकान को चलाना चाहते हैं? आप तो छोटी दुकान को बंद करके बड़ी दुकान चलाना चाहते हैं लेकिन इससे लोग क्या महसूस कर रहे हैं यह आपके सामने आयेगा।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : डिप्टी स्पीकर सर, कंवर पाल जी ने बार-बार दुकान बंद करने की बात कही है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इनका तो वैसे चरित्र ही ऐसा रहा है क्योंकि आपको भी याद होगा कि 1989 में चौधरी देवी लाल जी की सरकार को गिराने के लिए इन्होंने चौधरी भजन लाल जी के साथ साठ-गांठ की थी और उनको सरकार गिरवायी थी। उन्हें मुख्य मंत्री बनाया गया था। उस समय भजन लाल जी सारी पार्टी को लेकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गये थे और इन वाले वापस आ गये थे। आपको यह भी याद होगा कि फिर इन्होंने मायावती की सरकार को गिरवाया था, बाइको को अंदर करवाया और प्रकाश सिंह बादल को भी अंदर करवाया तथा उसकी तरफ किसी भी बात में इन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया जबकि वह इनसे बहुत आशा करते थे। पहले तो इनका यह फार्मूला था कि ये किसी भी मुख्य मंत्री की सरकार को गिरा देते थे लेकिन अब इनकी दुकान बंद हो गयी है और अब इनके पेट में यही पीड़ा है कि चौटाला साहब इनके दाव में नहीं आए।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अब आप संभलकर रहना क्योंकि आपको भी अंदर जाना पड़ेगा।

श्री कंवर पाल : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जैसा इन्होंने कहा कि हमने सरकारें गिरायी हैं लेकिन वे सारी सरकारें बनवायी भी हमने ही थीं। चौधरी देवी लाल जी को मुख्यमंत्री हमने ही बनाया था, मायावती को भी मुख्यमंत्री हमने ही बनाया था और अब की बार चौटाला साहब को भी मुख्य मंत्री हमने ही बनाया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब कुछ काम की बात कहना चाहता हूँ। 'सरकार

आपके द्वार' प्रोग्राम का तीसरा फेज तो हमारे यहां लगा ही नहीं और शायद लगेगा भी नहीं लेकिन जो सैकेंड फेज में काम मंजूर हुए थे वे अभी तक भी पूरे नहीं हुए हैं हालांकि सरकार ने ढिंढौरा पीटा है कि हमने काम किए हैं। चाहे वह पुल बनाने का काम था या चाहे वह सड़कें बनाने का काम था। पुल तो एक भी ऐसा नहीं है जहां पर काम शुरू हुआ हो। इसी तरह से मैक्सिमम सड़कें भी ऐसी हैं जिन पर काम शुरू नहीं हुआ है। दूसरा मेरा एक और निवेदन है कि मेरे हल्के में स्टोन क्रशर बहुत हैं और उन स्टोन क्रशर्स से सरकार को आमदनी भी बहुत होती है। मैंने विधान सभा की कमेटी की मीटिंग में भी यह मामला उठाया था कि सरकार स्टोन क्रशर्स से होने वाले पौल्यूशन पर तो बहुत ध्यान देती है लेकिन जिस सड़क से रोजाना एक हजार ट्रक निकलते हैं वह सड़क चौड़ी होनी चाहिए। उन ट्रकों की वजह से गांव के लोगों को बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसकी भी व्यवस्था की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप वाईड-अप करें।

श्री कंवर पाल : मेरे हल्के में गुडिया में पुल बन रहा है फोरैस्ट डिपार्टमैंट ने उसमें स्टे ले लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, वह भी बनना चाहिए। सड़कों के बारे में मैंने कहा था तो कहा गया था कि इस तारीख तक सड़कें बन जाएंगी। बेगोपुर गन्ना वाला सड़क की हालत बहुत खराब है, वहां कहीं भी जरा सा भी तारकोल नजर नहीं आता है। अभी माण्डीवाला का प्रश्न उठाया था तो पशु पालन मंत्री जी का न में जवाब था। मंत्री जी मेरे हल्के में आए थे तो कहा था इस गौसदन को गौशाला में बदलना चाहिए। वहां 171 एकड़ जमीन बेकार पड़ी है, 7-8 पशु होते हैं और जमीन काफी लम्बी चौड़ी है मेरा निवेदन है कि वहां गौशाला खोली जाए ताकि जो पशु बाहर बेकार फिरते हैं, उनकी रहने की सही व्यवस्था हो जाए। इन शब्दों के साथ धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूँ।

राव धर्मपाल (सोहना) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री प्रो० सम्पत सिंह जी ने जो वर्ष 2004-05 का बजट प्रस्तुत किया है (विघ्न) इसमें मैं कृषि और अन्य संबंधित बातों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। उपाध्यक्ष महोदय, 75 प्रतिशत जनसंख्या आज भी गांव में रहती है। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशु पालन है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में कहा गया है कि इसको कृषि एवं इनसे संबंधित गतिविधियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना बनाई है इससे भी किसान को बहुत राहत मिलने की उम्मीद है लेकिन इसमें बाजरा, कपास, मक्का, चना और सरसों की फसलों को लिया गया है हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा फसलें गेहूँ, चावल और गन्ने की होती हैं इन तीनों फसलों को इससे वंचित रख दिया गया है। मैं समझता हूँ कि इससे पूरा लाभ किसान को नहीं हो पाएगा। इसलिए इन तीनों फसलों को इसमें जोड़ा जाना चाहिए यह मेरा सुझाव है। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और बजट में यह बात रखी गई है कि सरकार ने बाजरे का भाव 505 रुपये दिलाया और दो लाख टन बाजरा खरीदा, गेहूँ भी खरीदी और किसान को ठीक रेट दिलाया है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस होता है कहते हुए कि किसानों की जो जमीन है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। मैं पहले राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान इस बारे में चर्चा कर चुका हूँ इसलिए इस बारे में दोबारा से सदन का समय खराब नहीं करना चाहता। परन्तु मैं इतना जरूर कहूँगा कि किसान को फसल के भाव तो मिल जाते हैं, लेकिन उसकी जमीन के भाव किसानों को मार्केट रेट पर नहीं मिल रहे हैं। चाहे किसी भी इलाके के किसान की जमीन हो किसी भी जिले की हो किसी भी गांव की हो। चौधरी धीरपाल सिंह जी बैठे हैं, माजरा साहब बैठे हैं। इस बारे में दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया हुआ है कि 23 लाख रुपये

[राव धर्म पाल]

प्रति एकड़ से कम किसानों की जमीन कहीं पर भी नहीं ली जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, जब दिल्ली सरकार द्वारा फैसला लिया जा सकता है, तो हमारी सरकार क्यों नहीं ऐसा फैसला लेती। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊँगा क्योंकि पहले भी मेरी कार्यवाही नोट है। किसानों की जमीन तीन लाख या चार लाख रुपये प्रति एकड़ के भाव से ली जा रही है और जैसा कि मैंने कल ही पता किया है कि एच०एस०आई०डी०सी० ने आई०एम०टी० में 2200 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कैल्कूलेट किया हुआ है, अगर 4840 गज को 2200 के हिसाब से कैल्कूलेट किया जाये तो एक एकड़ की कीमत एक करोड़ रुपये के करीब बनेगी और एक करोड़ के भाव से एक एकड़ को बेच रहे हैं। जबकि पहले किसानों को 6 लाख रुपये प्रति एकड़ दी जाती थी। उस वक्त जब रेट 1100 रुपये प्रति गज का भाव सरकार ने निकाला था।

श्री उपाध्यक्ष : धर्मपाल जी, दिल्ली में जो स्कीम लागू की है उसकी शुरूआत चौधरी देवी लाल जी के समय हुई थी। यह जमीन के रेट वाली बीमारी 70 हजार रुपये मुआवजे से शुरू हुई थी और इस बारे में चौधरी धीरपाल सिंह जी से कई बार गुजारिश कर चुका हूँ। आप भी पहले मंत्री रहे हैं और काफी लम्बे समय तक रहे हैं। इसमें कोई ऐसा कानून बनाया जाये जो चौधरी देवी लाल जी दिल्ली में बना गये थे। ऐसा दिल्ली के पैटर्न पर कोई कानून बन जाये तो वह सबके लिए फायदेमंद हो, आप इस तरह क्रिटिसाइज करते रहें तो उससे किसानों का फायदा होने वाला नहीं है। किसान को जो मुआवजा मिलता है उसका फार्मूला रिवाइज होना चाहिए। मेरी भी भावना यही है कि इसके लिए कम से कम कलैक्टर रेट तो अवश्य होना चाहिए क्योंकि जो गांव अपनी जमीन नहीं बेचेगा उसका तो कोई कलैक्टर रेट नहीं होगा। मैं तो यही कहूँगा कि दिल्ली के पैटर्न पर कोई फार्मूला जरूर बनना चाहिए। मैं तो चौधरी धीरपाल जी से भी यही कहूँगा।

राव धर्मपाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरा साथ दिया। इसके लिए कोई फार्मूला जरूर बनना चाहिए क्योंकि अब तक तो किसान इसकी मार झेलते रहे लेकिन आगे बर्दाश्त नहीं हो पायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने समय की भी मान लो जब आप मंत्री रहे थे। मैंने तो आज आपका साथ दे दिया है।

Rao Dharampal : Sir, I do agree with you.मैं भी यही कहता हूँ कि कोई फार्मूला जरूर बनना चाहिए।

श्री धीरपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावनाओं की याद दिला रहा हूँ। जब चौधरी बंसी लाल जी इधर बैठते थे उनके समय में माननीय हाई कोर्ट से एक फैसला आया और करीबन सौ करोड़ रुपये की राशि किसानों को उनकी जमीन की बढ़ी हुई राशि के तौर पर वितरित की गई थी परन्तु उसको वापस लेने के आदेश उस समय हाई कोर्ट ने दिए थे। चौधरी बंसी लाल जी ने उस आदेश को अमली जामा पहनाने की कोशिश की थी, उस समय फौजी तो शायद पैदा भी नहीं हुआ था। आपको याद होगा उससे 12 गांव प्रभावित थे और किसानों में काफी नाराजगी थी, उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ और सरकार बनने के बाद करीबन साढ़े चार साल के करीब इस सरकार को बने हो गये, पैसा वसूली की तलवार लटक रही थी, उनको भय था कि कहीं जो राशि खर्च हो गई है, खर्च होने के बाद रिकवरी की प्रक्रिया शुरू न हो

14-00 बजे

जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राव साहब को बताना चाहूँगा कि यह सिस्टम आज का नहीं है जब से यह विभाग बना है तब से है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने इसकी डटकर वकालत की है और आपने यहां तक भावना व्यक्त की है कि सबको एक समान दर से मुआवजा दिया जाना चाहिए। एक ही गांव में, एक ही इलाके में माल अधिकारी के रिकॉर्ड के अनुसार कहीं बरानी जमीन आ जाती है, कहीं सिंचाई वाली जमीन आ जाती है जबकि वहां विकास रिहायशी सैक्टर के आधार पर होना होता है फिर भाव अलग-अलग क्यों दिया जा रहा है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बारे में एक कमेटी बनी हुई है, वह कमेटी पहली वाली सरकारों के समय में भी थी और आज भी है। जिसमें एल०ओ० और डी०टी०पी०ओ० मैम्बर होते हैं और कलैक्टर रेट को ही आधार मानकर रेट तय किये जाते हैं। इस तरह का यह सिस्टम बना हुआ है इसको बदलने में समय लगेगा और इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए तथा नीयत भी ठीक होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : राव साहब, सरकार की नीयत अच्छी है यही कारण है कि अभी तक रिकवरी शुरू नहीं हुई है। धीरपाल जी, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि तीन साल पहले किसी गांव की जमीन 6 लाख रुपये एकड़ मुआवजे के हिसाब से एक्वायर हुई और आज चार साल बाद उसी गांव में 2.50 लाख रुपये मुआवजे के हिसाब से जमीन एक्वायर की जा रही है यह महसूस होने वाली बात है।

श्री धीरपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो HSIDC ने रेट निर्धारित किए हैं उसके आधार पर मुआवजा दिया जा रहा है। उसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : धीरपाल जी, आपके महकमें में भी ऐसा हुआ है। उसके बारे में मैं आपको लिखकर बताऊंगा। मेरे झाड़सां गांव में जो रेट था वह पहले कुछ दिया गया था और अब एक एनाउंसमैंट हुई है और वह ऐसी हुई है कि अगर उसको कोई देखे तो दंग रह जायेगा। यह बात मैं लिखकर आपके नोटिस में लाऊंगा।

राव धर्मपाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बार-बार एक बात यही कह रहा हूँ कि इस पर विचार किया जाये। पहले जो होता रहा है आगे भी उसी प्रथा को चलाया जाये जिससे किसानों पर मार पड़ती हो यह जरूरी नहीं है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : राव साहब, इसमें काफी बदलाव हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जिस किसान की जमीन एक्वायर होती है उसको प्लॉट दिया जाता है और पहले भी जिनकी जमीन एक्वायर हुई थी, उनको भी अब प्लॉट दिए जा रहे हैं। रिहायशी, रिलीजियस और ऐजुकेशनल सभी तरह के प्लॉट अब मिलने शुरू हुए हैं। एक मुआवजे वाली बात रह रही है। इस बारे भी अगर हम सभी मिलकर कहेंगे, तो इसका भी कोई न कोई हल सरकार जरूर निकालेगी।

राव धर्मपाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यदि सरकार को कोई दिक्कत है तो वे दिल्ली सरकार से राय ले लें जैसा कि आपने बताया है कि दिल्ली सरकार ने इस बारे में विधान सभा में बिल पास किया है। उन्होंने किस प्रकार से इस समस्या का समाधान किया है उस बारे उनसे सलाह ली जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आपने बताया है कि जिन किसानों की जमीन एक्वायर होती है उन्हें प्लॉट दिए जाते हैं। लेकिन इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जिन किसानों की जमीन इण्डस्ट्रियल सेक्टर के लिए एक्वायर की जाती है उनके एक-एक बच्चे को योग्यता के

[राव धर्म पाल]
हिसाब से वहां लगने वाले कारखानों में नौकरी मिलनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जमीन मंदे भाव में एक्वायर हो गई और उस पर 20 प्रतिशत कैपिटल गेन लग गया, अब वे लोग कहां जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : राव साहब, कैपिटल गेन के बारे में तो कृष्णपाल जी बतायेंगे। यह सैंट्रल गवर्नमैंट द्वारा लगाया जाता है।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, कैपिटल गेन भारत सरकार ने हटा दिया है। 50 साल से इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया लेकिन हमारी सरकार ने इसे हटा दिया है।

राव धर्मपाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह अभी नहीं हटा है यदि हटा दिया गया है तो हमें ये दिखा देंगे। मैं यह कह रहा था कि जिस घर की जमीन एक्वायर की जाती है उस घर के बच्चे को वहां लगने वाले कारखानों में नौकरी मिलनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, पशुधन के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि पशुधन किसानों के लिए आय का एक साधन है और हमारे राज्य में 2400 के करीब हॉस्पिटल पशुओं के स्वास्थ्य की देख-रेख के लिए चल रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में दूध की मात्रा भी दूसरे राज्यों से अधिक है इसमें कोई दो राय नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, यदि भारतवर्ष के प्रति व्यक्ति की दूध की मात्रा का अनुपात निकालें तो भारतवर्ष के एक व्यक्ति के हिस्से में 256 ग्राम दूध एक दिन का आता है जबकि हमारे हरियाणा में यह मात्रा 656 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आती है जो कि मैं समझता हूँ कि यह उसके स्वास्थ्य के लिए काफी है। डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ने एक पशुधन विकास बोर्ड बनाया हुआ है उसके तहत भी पशुधन को बढ़ाये जाने की कार्यवाही हो रही है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा जब हमारी सरकार थी तो उस वक्त हमने एक पॉलिसी बनायी थी कि हर जिला स्तर पर एक पोलिक्लिनिक टाईप का अस्पताल बनाया जाये ताकि पशुओं का सही तरह से इलाज किया जा सके। उस वक्त 1-2 जगहों पर यह अस्पताल बने भी थे। इसी संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे हल्के के अन्दर भी एक गांव में इस अस्पताल को बनाये जाने के लिए 6 एकड़ जमीन एक्वायर करके उस पर कार्यवाही करते हुए चारदीवारी आदि बना दी गई थी। बाद में उसका काम कैसे रोक दिया गया, यह मुझे पता नहीं। इसलिए मेरी मांग है कि यदि सरकार उस अस्पताल को अब बना देगी तो उससे वहां के किसानों का बड़ा हित होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सहकारिता की बात करना चाहता हूँ। इस बजट में जो 2004-05 का यहां पर रखा गया है, इसमें दिखाया गया है कि हमारे यहां पर 22,545 को-आप्रेटीव सोसाइटीज हैं, 348 बैंक्स हैं और 2430 मिनी बैंक्स हैं। मैं समझता हूँ कि किसानों के 75 प्रतिशत लोन को ये बैंक्स ही पूरा करते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि इन बैंक्स के माध्यम से किसान अपना पैसा ले तो लेता है लेकिन बाद में वह उसे वापस नहीं दे पाता क्योंकि बाद में हालात ही बैंक के कर्मचारी/अधिकारी उस किसान के लिए ऐसे पैदा कर देते हैं कि वह उनसे बच नहीं सकता। मैं इसे घपला कहूँ या कुछ और कहूँ, यह किसानों के लिए बड़ी दु:खदायी बात है। एक तो जब किसान शुरू में लोन लेने जाता है तो सबसे पहले उस वक्त पैसा उनसे मांगा जाता है। बगैर पैसे लिए उसका लोन सैंक्शन नहीं होता। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब उसका लोन सैंक्शन होता है तो उसको पूरा लोन मिलने की बजाय वे अपना हिस्सा काट कर किसान को देते हैं। इतना ही नहीं कहीं-कहीं पर तो ऐसी भी सोसाइटीज हैं जो बोगस दस्तख़त करके पैसा ले लेती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : धर्मपाल जी, मुझे पूरे हरियाणा के दूसरे जिलों के बारे में तो पता नहीं लेकिन

गुड़गांव में एक आदमी ने इसे अपनी निजी जायदाद बनायी हुई थी, उससे हमने लोगों का पीछा छुड़वाया था।

राव धर्मपाल : डिप्टी स्पीकर साहब, आज भी उसमें घप्पले बाजी है। इन मिनी बैंक्स और सोसाइटीज में आज के दिन क्रप्शन बहुत अधिक मात्रा में है। जो किसान इनसे लोन ले लेता है वह इनके चक्र से निकल नहीं पाता तो बाद में संबंधित किसान को कह दिया जाता है कि तेरा पुराना लोन आया हुआ दिखा देते हैं और नया दिखा देते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि ये सोसाइटीज या बैंक्स ऐसा परेशान करते हैं कि बेचारा किसान इनके चक्र से निकल नहीं पाता।

श्री उपाध्यक्ष : राव साहब, आप अपनी बात खत्म करें और बजट पर भी अब आप कुछ बातें कह दें।

राव धर्मपाल : डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं पेयजल विभाग से संबंधित बात कहना चाहूँगा। इस संबंध में पिछले बजट में दर्शाया गया था और मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में विश्वास दिलाया था कि हरियाणा सरकार 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन देगी। आज के दिन यह मात्रा 70 लीटर से घटकर 40 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति रह गई है। बल्कि मैं तो यह भी कहूँगा कि बहुत सारे गांवों में तो यह मात्रा 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की बजाये 10 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति भी नहीं मिल पा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, अलीपुर गांव में एक हरिजन कॉलोनी है जो कि पिछले 25-30 साल से वहां पर बसी हुई है और सरकार ने उन लोगों को प्लॉट्स देकर वहां पर बसाया था। इस कॉलोनी में आज तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। एक बार हमने वहां पर बोर करके देखा था लेकिन वहां पर जो पानी निकला वह खारा था और फिर दोबारा हम बड़ी दूर से उनके लिए पानी लेकर आए, क्योंकि वह पानी काफी दूर से आता था और रास्ते में लोगों ने उस पानी को रोक लिया और किसी ने डायरैक्ट पानी रास्ते में ले लिया या पाईप लगा लिया जिसके कारण उस हरिजन कॉलोनी में पानी नहीं आता है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूँगा कि उस हरिजन कॉलोनी के लिए भी पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे ही कुछेक और गांव हैं जिनमें पीने के पानी की समस्या है। गांव घंघोला, भयपुर, दमदमा, बीहलका और उनके सराउन्डिंग गांव हैं जहां अभी तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हुई है इसलिए इन गांवों को भी पीने का पानी जरूर मिलना चाहिए। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004-05 का जो बजट पेश किया गया है, मैं इसका विरोध करता हूँ और जो वास्तविकता है जब ये जनता में जायेंगे तो वह खुद सामने आ जायेगी। धन्यवाद।

वाक-आउट

श्रीमती अनीता यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया। (विघ्न एवं शोर)

श्री कृष्णपाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बोलने के लिए आपको अपना नाम भिजवाया हुआ है लेकिन आपने अभी तक मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी है इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : कृष्णपाल जी, मैंने अब उनको बोलने के लिए कह दिया है और वे बोलने के लिए खड़ी हैं इसलिए अभी आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न)

श्री कृष्णपाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने का समय नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपनी सीट पर बैठें।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो अन्याय है आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं और मेरे साथ धक्का कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृष्णपाल जी, यह धक्काशाही नहीं चलेगी, आपके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है इसलिए आप अपनी सीट पर बैठें (विघ्न) क्या आपका यह तरीका ठीक है ? आप अपने आप को सुपीरियर मानते हैं लेकिन सदन में सभी सदस्य बराबर हैं। अभी आपकी पार्टी के सम्मानित साथी कंवर पाल जी को बुलवाया है और फिर भी आप इस तरह की बात कह रहे हैं, यह ठीक नहीं है इसलिए अभी आप अपनी सीट पर बैठें। आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए समय दिया जाना चाहिए था लेकिन मुझे अभी तक बोलने का समय नहीं मिला है, यह आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृष्णपाल जी, आपका यह व्यवहार ठीक नहीं है और इस प्रकार का व्यवहार टोलरेट नहीं किया जा सकता है। सभी सम्मानित सदस्यों को बोलने के लिए समय दिया गया है और आपको भी बोलने के लिए समय दिया जाएगा। लेकिन इस प्रकार से धक्केशाही करना आपके लिए ठीक नहीं है। (विघ्न) क्या इन लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए ? अभी थोड़ी देर पहले आपकी पार्टी के सदस्य श्री कंवरपाल जी बोले हैं। आपको बाद में समय दिया जाएगा इसलिए अभी आप अपनी सीट पर बैठें। अनीता जी, आप अपनी बात कन्टीन्यू करें।

श्रीमती अनीता यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो अपनी बात तभी कह पाऊंगी, जब ये बैठेंगे।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय *******

श्री उपाध्यक्ष : कृष्णपाल जी, आपका तरीका ठीक नहीं है, आप अपनी आदतें ठीक करें और इस प्रकार का व्यवहार न करें। अब आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) कृष्णपाल जी की कोई भी बात रिकॉर्ड न करें। कृष्णपाल जी, आपको हर बार बोलने का मौका दिया जाता रहा है। गवर्नर एड्रैस पर भी आप बोल चुके हैं जबकि कई ऐसे मैम्बर्ज हैं जिनको अब तक बोलने का मौका नहीं मिला है, अब आप प्लीज बैठें।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह निवेदन का तरीका है ? आपने इस प्रकार से 10 मिनट का समय खराब किया है इतनी देर में तो दूसरे मैम्बर साहेबान बोल लेते। अब आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं विघ्न) कृष्णपाल जी, आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) कृष्णपाल जी, बीच में खड़े

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

होकर बोलने की आपकी आदत सी बन गई है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आप अपनी सीट पर बैठें।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं, इसके विरोध में हम सदन से वाक-आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के श्री कृष्णपाल गुर्जर, श्री कंवर पाल और श्रीमती सरिता नारायण सदन से वाक-आउट कर गए।)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि पार्टी अपने मैम्बर्ज की लिस्ट आपके पास भेजती है कि उनके फलां-फलां मैम्बर्ज बोलना चाहते हैं लेकिन यह चेयर का अधिकार है कि वह किस समय किस मैम्बर को बुलवाए। सुबह से अब तक आपने और अध्यक्ष महोदय ने कांग्रेस पार्टी के साथियों को, दूसरे सदस्यों को बोलने का समय दिया। चाहे वे सकारात्मक विचार दें, राजनीतिक विरोध करना चाहें कर सकते हैं और जिस विषय में चाहें बोल सकते हैं। जनता ने अपनी बातें कहने के लिए बी०जे०पी० के 6 सदस्य यहां पर चुन कर भेजें हैं और उनमें से एक को बोलने का मौका दे दिया है और दूसरों का जब बोलने का समय आएगा तो उनको भी बोलने का मौका दिया जाएगा, उनको भी समय दिया जाएगा। अब वे अखबारों में सुर्खियां बनाने के लिए बीच में खड़े होकर बोलने लग पड़े कि हमारे पास यह मसाला है, वह मसाला है। अब आप किसी दूसरी सदस्या को बोलने के लिए खड़ा करते हैं तो वे बीच में खड़े होकर बोलने लग जाते हैं कि मैं अभी बोलूंगा, आप मुझे बोलने देंगे या नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या अनीता जो सदन की सदस्या नहीं है। वे भी सदन की सदस्या हैं और आपने उनको बोलने का मौका दिया है तो उनको बोलने दिया जाता। जब उनका समय आता तो वे भी बोल लेते लेकिन उनका मकसद सदन में अपना वाक-आउट दर्ज करवाने का था। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। कल भी उनको बोलने का मौका दिया गया था लेकिन उन्होंने सदन में क्या बोला यह सबको पता है। आज अब बीच में ही खड़े होकर कहने लगे कि मुझे बोलने दिया जाए। ऐसा क्या था उनके पास, क्या कोई तोप का गोला था। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था।

वर्ष 2004-05 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा
(पुनरारम्भ)

श्रीमती अनीता यादव (सालहावास) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 2004-05 के बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं इस बजट के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। इस बजट में जो आंकड़े दर्शाए गए हैं, वे तथ्यों से परे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ज्यादा लगाव डॉ० एम०एल० रंगा जी के साथ है जो स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्ध रखते हैं। वे यह कहते हैं कि हम यह करते हैं और वह करते हैं। बजट में स्वास्थ्य के लिए 406.72 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है जो कि टोटल बजट का 2.40 प्रतिशत बनता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि मेरे सालहावास क्षेत्र में जितनी भी डिसपैंसरीज हैं और जमालपुर में हास्पिटल है, वहां पर डॉक्टर, नर्सिज और दूसरा टैक्निकल स्टाफ नहीं है। इसके अलावा वहां पर ऑप्रेशन थियेटर में जो इन्स्ट्रूमैंट्स हैं वह भी पुराने हैं और उन पर जंग लगा हुआ है जिसकी वजह से वहां पर पिछले दिनों दो केसिज खराब हो गए हैं। पिछले दिनों मैं वहां पर गई थी तो मुझे बताया गया कि डिलीवरी के वक्त उन इन्स्ट्रूमैंट्स की वजह से एक बच्चे की डैथ हो गई थी और एक मां के

[श्रीमती अनीता यादव]

इन्फैक्शन हो गया था। इस बारे में भी इनको ध्यान रखना चाहिए। बजट में जो आंकड़े दिखाए गए हैं, वे गलत हैं और झूठ का पुलिंदा हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी पढ़े लिखे हैं, फिर भी ये सदन में इस तरह की बात करके सदन को और जनता को गुमराह करने की बात करते हैं जो कि इनके लिए उचित नहीं है।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डॉ० एम०एल० रंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो वक्तव्य देता हूँ वह बड़ी सोच समझकर देता हूँ। मैं ऑन रिकॉर्ड बात करता हूँ। सारी रात फोटो कापी करवाकर और फैक्स मंगवाकर मैंने तथ्यों पर आधारित बात की है जबकि इसे यह झूठ का पुलिन्दा बता रही है। अगर यह झूठ का पुलिन्दा है तो या तो ये छोड़ जाएं या मैं छोड़कर चला जाता हूँ। रही बात हाउस को गुमराह करने की तो यह शब्द तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है इसलिए मैं गुमराह करने की बात तो मानता ही नहीं हूँ। यह शब्द तो उन लोगों की डिक्शनरी में है जो लोगों को गुमराह करके यहां पहुंच गए हैं। मैं तो काम करने में विश्वास करता हूँ और काम करके लोगों को बताता हूँ। रही जमालपुर की बात तो मैंने वहां के दोनों डॉक्टर्ज से बात की है उनमें से एक का नाम राकेश है, वे दोनों डॉक्टर्ज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा था कि क्या किसी चीज की जरूरत है अगर जरूरत हो तो बताएं। उपाध्यक्ष महोदय, ये दवाई लेने तो जाती नहीं हैं क्योंकि इनका स्वास्थ्य बढ़िया है। इसलिए ये बिना तथ्यों के आधार पर ही बात करती हैं जोकि इनको नहीं करनी चाहिएं। मेरे पास तथ्य हैं, फैक्टस हैं, ये पढ़ लें और फिर बात करें।

श्रीमती अनीता यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जानना या न जानना तो पब्लिक के हाथ में है, जो आने वाले समय में बता देगी। इनको आगामी समय में पता लग जाएगा कि हैल्थ मिनिस्टर कौन बनेगा? उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते ही हैं कि मेरे हसबैंड भी डॉक्टर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, डैमोक्रेसी में अपने विचार रखने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मैं भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। मैं भी आंकड़ों के मुताबिक ही कह रही हूँ कि हैल्थ के लिए 406.72 करोड़ रुपये दिए गए हैं जोकि बहुत ही कम हैं।

डॉ० एम०एल० रंगा : उपाध्यक्ष महोदय, ये पूरे आंकड़े तो पढ़ती नहीं हैं। यह सारा अमाउन्ट स्वास्थ्य के लिए नहीं है बल्कि यह दवाइयों के लिए ही है। स्वास्थ्य और दवाइयां दोनों अलग-अलग पहलू हैं। इसमें पांच करोड़ रुपये अलग हैं। ये कोने में जाकर फिगर्ज पढ़ लेती हैं क्योंकि इन्होंने यूरोपियन यूनियन के 11 करोड़ रुपये भी नहीं पढ़े हैं, ये सारे आंकड़े पढ़ लें और फिर बात करें।

श्रीमती अनीता यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि वहां पर इंस्ट्रूमैंट्स बहुत ज्यादा जर्जर अवस्था में हैं, उनका वहां पर प्रावधान करने के लिए इस बजट में और पैसा बढ़ा लें, मैंने तो इतना ही कहा है। इसी तरह से जहां तक बिजली की बात है बिजली का बजट 1320.42 करोड़ रुपये रखा गया है। जैसा कि मैंने माननीय गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर भी बताया था कि मेरे क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जहां की बिजली की तारों की हालत बहुत खस्ता है, ऐसा ही एक गांव बिखड़ा गांव है जहां के लोगों ने पचास रुपये प्रति घर के हिसाब से इकट्ठा करके गांवों की बिजली की तारें मंगवायी और अब खिंचवाने के लिए चन्दा इक्ट्ठा किया जा रहा है जो कि बड़े शर्म की बात है। बिजली के मद में पिछली बार भी कम बजट दिखाया था और इस बार भी कम बजट दिखाया गया है। जो पैसा आ रहा है और जा रहा है उसमें पिछली बार के मुकाबले इस बार कमी आ रही है जो पैसा आ रहा है वह 45 प्वायंट समथिंग बनता है और जो पैसा जा रहा है 50 परसेंट से ऊपर बनता है यानी बात तो वहीं

की वहीं खड़ी है। जो पैसा आ रहा है और जो पैसा जा रहा है उसमें घाटा ही नजर आ रहा है। बिजली के लिए जो पैसा अलॉट किया गया है पता नहीं वह किस बेसिज पर अलॉट किया गया है। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र साल्हावास की बिजली की तारें वहीं खड़ी हैं। अगर वे एक बार चढ़ा देते हैं तो वे फिर टूट जाती हैं। इसी तरह से अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो एक महीने तक बदला ही नहीं जाता है। चूंकि यह महकमा माननीय मुख्य मंत्री जी के पास है इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि इस काम के लिए भी बजट में कुछ धनराशि बढ़ाकर रखी जानी चाहिए और साल्हावास विधान सभा क्षेत्र के साथ इस प्रकार की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए और वहां पर बिजली की तारों की समस्या की तरफ ध्यान देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप वाईंड-अप करें।

श्रीमती अनीता यादव : मैं वाईड-अप कर रही हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में कहते हैं कि 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की उपलब्धता है जबकि 1829 गांवों में इन्होंने खुद माना है कि 40 लीटर पानी भी नहीं मिल पा रहा है। उन गांवों की क्या हालत होगी जिनमें पीने का पानी ही नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 8-10 गांव ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी बहुत कड़वा है, काफी दूर से कुएं से दो बाल्टी पानी भरकर लाते हैं तब जाकर खाना बनाते हैं उनके यदि कोई आ जाए तो पीने के लिए पानी तो आधा गिलास मिलता है, दूध चाहे जितना पी लो। खानपुर कलां, खानपुर खुर्द, झांसवा और मनडोढ़ा इन गांवों में पानी की मात्रा बहुत कम है और बजट में पानी के लिए 553.20 करोड़ रुपये की राशि दिखाई गई है इसमें कुछ परसैंटेज और बढ़ा लें जिससे साल्हावास हल्के में पानी मुहैया करवाया जा सके। मेरे हल्के के लोगों में यह गलतफहमी पैदा हो गई है कि अनीता यादव अपोजीशन की मैंबर है इसलिए सरकार हमारे क्षेत्र की अनदेखी करती आ रही है, इस गलतफहमी को आप दूर करने का काम करें। इसी तरह से बार-बार सड़कों का जिक्र आता है। मेरे हल्के में कोई भी रोड़ ऐसी नहीं है जहां दूसरे गीयर से तीसरे गीयर में गाड़ी चल सकती हो। मुझे नहीं पता कि रोड्स सिरसा में बनी हैं या डबवाली में बनी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप वाईड-अप करें।

श्रीमती अनीता यादव : उपाध्यक्ष महोदय, कौसली से जूटी तक की रोड़ पर तारकोल नहीं डाला है। इस तरह की छोटी-छोटी रोड्स हैं एक-एक, दो-दो किलोमीटर के टुकड़े हैं, जिनके बनाए जाने से 5-5, 6-6 किलोमीटर की दूरी को कवर कर सकते हैं। ऐसे ही सादक नगर से नौहड़ा की सड़क यह मात्र डेढ़ किलोमीटर का टुकड़ा है और वहां पर रेत मिट्टी पड़ी हुई है। इससे भी 6-7 किलोमीटर की दूरी कवर हो सकती है। अब मैं परिवहन के बारे में कहना चाहूँगी। बजट में कहा गया है कि 3431 नयी बसें लगा दी हैं और 11 लाख यात्री सफर कर रहे हैं और जो हमारे यहां कालेज की लड़कियां हैं वे जीपों में लटककर जा रही हैं मैंने पिछले सत्र में भी अनुरोध किया था कि वहां कोई टूटी-फूटी बस भेज दी जाए तो उन लड़कियों को सहारा मिल जाएगा और वे पढ़ने के लिए समय पर पहुँच पाएंगी। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए और इस बजट का विरोध करते हुए मैं अपना स्थान लेती हूँ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। हाउस का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2004-05 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा
(पुनरारम्भ)

श्रीमती स्वतंत्र बाला (फतेहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे पहले बजट सत्र में बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं माननीय मुख्य मंत्री जी व अपने हल्कावासियों का भी धन्यवाद करती हूँ जिनके आशीर्वाद से और शुभकामनाओं से हरियाणा के इस महान सदन में मैंने प्रवेश किया है। इस सत्र में मेरे साथी भाई-बहन कुछ पक्ष में बोले हैं कुछ विपक्ष में बोले हैं। मैं आज शिक्षा के क्षेत्र में और महिलाओं के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो विकास के कार्य करवाये हैं उनको लेकर उनका धन्यवाद करने आई हूँ और इस बजट के पक्ष में बोलने आई हूँ। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में और महिलाओं के उत्थान में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके लिए उनका धन्यवाद करती हूँ। शिक्षा जिसके बिना समाज में अन्धेरा ही अन्धेरा है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1213 स्कूलों को अपग्रेड करवाया है और 264 प्राईमरी स्कूलों की ब्रांचों को नियमित करके स्कूलों में बदला है ताकि स्कूलों की व्यवस्था ठीक हो सके। हमारे बच्चे देश के नागरिक हैं जिन्होंने कल को हमारा देश संभालना है, उनका बेस सही बन सके। इसके साथ-साथ प्राईवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलों के अन्तर को कम करने के लिए उनको मंजूरी देकर अपनी नीतियों की व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पहली कक्षा से तीसरी कक्षा के लिए डैस्क उपलब्ध करवाये हैं और पहली कक्षा से कम्प्यूटर की शिक्षा आरम्भ की है और घूमन्तु परिवारों के बच्चों के लिए एक रुपये हाजिरी भत्ते को बढ़ाकर पांच रुपये किया है ताकि अधिक से अधिक बच्चों का शिक्षा की तरफ रूझान बढ़ सके। सर्वशिक्षा अभियान पूरे जोरों से चल रहा है और उसके बहुत अच्छे परिणाम आयेंगे। कम्प्यूटर शिक्षा कितनी बेहतर रही है। मैं प्रिंसिपल रही हूँ और इसके बारे में मैं आपको एक सत्य बात कहने जा रही हूँ। मैं अपने स्कूल के कम्प्यूटर रूम में गई वहां जाकर मैंने देखा कि एक गरीब लड़की कम्प्यूटर चला रही थी। मैंने उस लड़की से पूछा कि बेटे कैसा लग रहा है। उस लड़की ने कहा कि मैडम मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पड़ोस की आंटी के घर कम्प्यूटर था उसके बच्चे जब कम्प्यूटर चलाते थे, मैं जब उनके घर जाती थी तो वे लड़के मुझ से कहते थे कि तुम बाहर जाओ तुम्हारे पैर गन्दे हैं और आज वह लड़की कम्प्यूटर चला रही थी। उस लड़की की बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। इस प्रकार की सोच हमारे मुख्य मंत्री जी की है और किसी की नहीं है। इसी तरह से लड़कियों का रूझान शिक्षा की ओर बढ़ाने के लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने और भी बहुत से कार्य किए हैं। कई मेरे साथी भाई जानते होंगे और उन बच्चों के पेरेन्ट्स बताते ही होंगे कि उनकी लड़की पांचवी कक्षा से आगे पढ़ नहीं सकती क्योंकि हमारे गांव में मिडल स्कूल नहीं हैं और प्राईमरी स्कूल से मिडल स्कूल नॉर्म्स पूरे होने के बाद ही अपग्रेड किये जा सकते हैं। 26 जनवरी को हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की कि पांचवी कक्षा के बाद अगर लड़कियां दूसरे गांव में शिक्षा के लिए जाती हैं तो उनके लिए सरकार साईकल की व्यवस्था अपनी तरफ से करेगी। इसी तरह से सर्वशिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। पहले इंजीनियरिंग और मैडीकल की शिक्षा के लिए हमारे बच्चों को दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता था और हमारे प्रदेश में इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गये हैं और उनमें एडमिशन लेना इतना आसान हो गया है कि आज दूसरे प्रदेशों के बच्चे हमारे यहां शिक्षा ले रहे हैं। ये सब बातें हमारे मुख्यमंत्री जी की अच्छी सोच के कारण हो रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय मैं मुख्य मंत्री जी का सबसे ज्यादा धन्यवाद तो

सिरसा में चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय खोलने के लिए देना चाहती हूँ, जोकि नई आधुनिक तकनीक के साथ खोला गया है। यह भ्रम पैदा किया जा रहा था कि यह विश्वविद्यालय दूर होगा लेकिन कम्प्यूटर की व्यवस्था और चैट चर्किंग द्वारा यह दूरी इतनी नजदीक हो जायेगी कि कोई भी जानकारी हमें घर बैठे उपलब्ध हो जायेगी। जिस प्रकार हम टी०वी० पर न्यूज चैनल देखते हैं, जिन्होंने वर्ल्ड को कितना सीमित कर दिया है। इतना आधुनिक तकनीक का विश्वविद्यालय खोला गया है जोकि हमारे लिए एक गर्व की बात है। शिक्षा के क्षेत्र में जो इस सरकार के वक्त में कार्य किए गए हैं मैं उसके लिए इनका धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ-साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जिनके आशीर्वाद से फतेहाबाद में बी०एड० की शिक्षा शुरू की है, जिससे हमारे बच्चों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो शिक्षक पुरस्कार 2500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किए हैं और जो मान्यता प्राप्त स्कूल और कॉलेज हैं उनके अध्यापकों के लिए पैंशन की व्यवस्था की है उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। अब मैं महिलाओं के बारे में कहना चाहती हूँ। महिलाओं के उत्थान के लिए हरियाणा सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं उनके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी का जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम है जिन्होंने विधवा पैंशन, बुढ़ापा पैंशन, विकलांग पैंशन देकर महिलाओं को एक सहारा दिया है। मातृत्व लाभ योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को खान-पान के लिए 500 रुपये, बालिका समृद्ध योजना के तहत बालिका के जन्म पर 500 रुपये दिए जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं। इसी तरह से किशोरी शक्ति योजना शुरू की है जो कि बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना के तहत गरीब किशोरियों को सिलाई-कढ़ाई का काम सिखाया जाता है और 2.50 रुपये डाईट के भी दिए जाते हैं। यह योजना चार ब्लॉक स्तर से शुरू हुई थी और अब यह 85 ब्लॉक स्तर तक पहुँच गई है और बहुत ही अच्छे ढंग से कारगर साबित हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कन्यादान स्कीम को भी बढ़ाकर बहुत ही अच्छा काम किया है इसके लिए मैं उनको बधाई देती हूँ। पहले इस स्कीम के तहत हरिजन लड़कियों की शादी पर 5100 रुपये सरकार की तरफ से कन्यादान के लिए दिए जाते थे और दूसरी जातियों की माताएं और बहनें हमसे आकर कहती थी कि हम भी गरीब हैं हम कहां जाएं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बी०पी०एल० से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के लिए यह स्कीम अब लागू कर दी है जो बहुत ही अच्छी बात है और महिलाओं के लिए गौरव की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने देवी रूपक योजना चलाकर महिलाओं का मान बढ़ाया है। भ्रूण हत्या के लिए महिलाओं को उकसाता कोई और है लेकिन महिलाओं को उसके लिए कलंकित किया जाता था। अब हरियाणा सरकार पी०एन०डी०टी० के खिलाफ शक्ति से निपट रही है। जिन महिलाओं को दहेज के नाम पर उत्पीड़ित किया जाता था उन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जिला स्तर पर एस०डी०एम० और सिटी मैजिस्ट्रेट लैवल के अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है ताकि अधिक से अधिक इन्क्वायरी हो और महिलाओं को न्याय मिल सके। इस स्कीम को दहेज प्रतिषेद कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इस स्कीम के तहत 50 हजार से बढ़ाकर 20 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है ताकि महिलाओं की पीड़ा दूर की जा सके। आज पुलिस हैल्प लाईन 24 घंटे उपलब्ध रहती है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के सुधार के लिए सरकार द्वारा परिवार परामर्श केन्द्र चलाये जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं किस-किस की तारीफ करूं मौजूदा सरकार ने हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए हैं। राज्य महिला आयोग द्वारा 2004-05 के लिए 30 लाख रुपया महिलाओं के उत्पीड़न को कम करने के लिए खर्च किया जाएगा और वर्ष 2003-04 में भी इतना ही पैसा खर्च किया गया था। इसी तरह से महिला विकास निगम के लिए पांच करोड़ की जगह

[श्रीमती स्वतन्त्र बाला]

10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो जरूरतमंद महिलाओं के प्रशिक्षण पर खर्च किया जायेगा और उनकी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से महिलाओं की भलाई के लिए चलने वाली संस्थाएं जिन्हें सरकार द्वारा सहायता दी जाती है उनके लिए 13 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये का प्रावधान किया है। इसी तरह से महिला पंच प्रशिक्षण व्यवस्था शुरू की गई है। भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है। हमारे यहां महिलाएं अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी को समझ सकें। इसके लिए महिलाएं पंच प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि महिलाएं संवैधानिक जिम्मेवारी को अच्छी तरह से निभा सकें और अपना प्रतिनिधित्व अच्छे ढंग से कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पानी के बारे में भी उचित व्यवस्था की है। हमारे समाज में पानी लाना भी महिलाओं की जिम्मेवारी है। पहले महिलाओं को दूर-दूर से पानी लाना पड़ता था लेकिन माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पूरे प्रदेश में पानी की उचित व्यवस्था की है अब महिलाओं को काफी राहत मिली है। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूँ। बिजली के क्षेत्र में भी आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत काम किया है। आजकल गृहणी ज्यादातर काम बिजली से ही करती हैं जिससे उन्हें शारीरिक थकावट कम होती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा सरकार की नीतियों के बारे में जितना कहूँ उतना ही कम है। माननीय मुख्य मंत्री जी की सरकार बनने के बाद हरियाणा में महिलाओं को एक नई दिशा प्राप्त हुई है। जहां तक खेल नीति का सवाल है, खेल के क्षेत्र में भी महिलाओं ने प्रदेश का नाम रोशन किया है और यह माननीय मुख्य मंत्री जी की अच्छी नीतियों के कारण ही संभव हो पाया है। कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलम्पिक में पदक जीता और सरकार की तरफ से उसे ईनाम दिया गया, हाकी में भी अच्छे खेल के लिए हमारी सरकार ने एक-एक लाख रुपये ईनाम के तौर पर दिए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वह दिन दूर नहीं जब हरियाणा में एक कर्णम मल्लेश्वरी नहीं बल्कि कई-कई कर्णम मल्लेश्वरी होंगी, एक कल्पना चावला नहीं, कई-कई कल्पना चावला होंगी। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट में महिलाओं के विकास के लिए जो प्रावधान किया है और यह इनकी सकारात्मक सोच की वजह से है इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का जितना आभार प्रकट करूं उतना ही कम है। जितनी योजनाओं का लाभ महिलाएं उठा सकती हैं उठावें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। अन्त में मैं बैठने से पहले एक बात और कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं उनका प्रचार और अच्छे ढंग से हो क्योंकि ज्यादा लोग मजदूर हैं और वे 5 बजे तक घर से बाहर रहते हैं। मैं आपके माध्यम से सदन के सामने यह मांग रखती हूँ कि शाम के वक्त सड़क शो करवाए जाएं ताकि माननीय मुख्य मंत्री महोदय और हरियाणा सरकार की नीतियों का अधिक से अधिक प्रचार हो सके और खास करके यह प्रचार जो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं उस के बारे में भी होना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी का जितना आभार व्यक्त करूं वह कम है क्योंकि मेरे हल्के में विकास के कामों की कोई कमी नहीं रही है। मेरे हल्के में बहुत विकास के काम हुए हैं लेकिन फिर भी इच्छाएं कम नहीं होती हैं वे और उभरती हैं। यदि विकास होता है तो इच्छा बढ़ती है। मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूँ कि मेरे हल्के के गोरखपुर गांव में आज सेम की समस्या आ गई है इसका समाधान भी सरकार को तुरन्त करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : बहन जी, आप अपनी बात लिख कर दे दें, अब आप बैठिये।

श्रीमती स्वतंत्र बाला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से एक और मांग है कि मेरे हल्के के गिराना गांव में एक परचेज सैंटर बनाये जाने की बहुत सख्त आवश्यकता है, अतः मेरी मांग

है कि इस गांव में परचेज सैंटर जल्दी से जल्दी बनाया जाये ताकि वहां के किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। इसी प्रकार से मेरे हल्के के गाँव गोरखपुर में हैडमास्टर की कमी है, अतः वहाँ पर हैडमास्टर की कमी को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए आपका तहदिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका, मुख्य मंत्री जी का और सदन में सभी मेरे भाई-बहनों का जिन्होंने अपनी इस सिम्पल बहन को सुना। अन्त में मैं वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका दिल खोल कर समर्थन करती हूँ। धन्यवाद।

चौ० जगजीत सिंह (दादरी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने वित्त मंत्री जी के बजट पर जो इन्होंने कल पेश किया था उस पर मुझे अपनी बात कहने के लिए खड़ा किया है उसके लिए आपका धन्यवाद। वैसे तो इस बजट में नया कुछ भी नहीं है क्योंकि न तो कर लगाये गए जैसाकि वित्त मंत्री जी ने बताया है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को यह बताना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री जी हरियाणा के लोग आंकड़ों को नहीं समझेंगे। हमने क्या दिया, यह बताओ और क्या लिया है, यह बताओ। आप बता रहे हैं कि वैट के जरिये आपने 19 परसेंट पैसा इकट्ठा किया है। आपने लोगों से लिया ही है, दिया कुछ नहीं। इन आंकड़ों में कुछ नहीं है। न तो कोई आम आदमी इन किताबों को पढ़ेगा और न ही उनकी समझ में आयेगा। हम तो थोड़ी बहुत जरूर पढ़ लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो किताब तैयार की है उसके तहत आप बताओ कि आपने हरियाणा की जनता को क्या दिया है, आपने लेने के सिवाय कुछ नहीं किया। इस बजट में आंकड़ों का खेल है और कुछ नहीं है। जिन लोगों ने हमें चुन करके भेजा उनको यह पता है कि उनको इस बजट में कुछ नहीं मिला है। जो आंकड़े आपने दिए हैं उन पर भी मैं नजर दौड़ाऊंगा क्योंकि मैंने भी थोड़ा-थोड़ा इसको पढ़ा है। इसमें आपने मोटे तौर पर 25 टोल टैक्स लगाए हैं। (**इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए**) अध्यक्ष महोदय, कुछ टोल टैक्स तो सरकार ने लागू कर दिए और कुछ आने वाले समय में चालू हो जायेंगे यानी वे अगले एक साल के अन्दर चल जाएंगे और जब लोग अपनी गाड़ियां वहां से ले जाएंगे तो उससे आपको कितना रैवेन्यू मिलेगा यह तो आपको पता होगा लेकिन बेचारे गरीब लोग लुट जरूर जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, सी०ए०जी० की जो रिपोर्ट आई है इसमें 25 त्रुटियां बताई गई हैं। अगर इनको बारीकी से देखा जाए तो इस बजट के अन्दर बड़ी भारी अनियमितता मिलेगी। इस बारे में सरकार को ध्यान रखना चाहिए। आपका वर्ष 2002-03 का वित्तीय घाटा कम हो गया था लेकिन फिर बढ़ना शुरू हो गया और यह लगातार वित्तीय घाटा बढ़ता जा रहा है। आपके ऊपर कर्जा कितना बढ़ रहा है इस बारे में बत्तरा जी व कैप्टन साहब ने सरकार को बताया है। इन्होंने बताया है कि 40 हजार करोड़ रुपये का कर्ज हरियाणा पर है। 40 हजार करोड़ रुपये नहीं है। आपकी यह बुक जो है इसमें हमें जो लिख कर दिया है उसके हिसाब से 31187.2 करोड़ रुपये का कर्ज है। वर्ष 2003-04 में आपकी एस्टिमेटिड रिसीट 11591 थी जबकि आपने 10809.99 करोड़ रुपये अचीव की। एक्सपैंडिचर जो आप हर साल दिखाते हो उससे वह बढ़ जाता है। इस बजट में आपने दिखाया है कि आने वाले साल में 12673 करोड़ रुपये खर्च करोगे जबकि मैं समझता हूँ कि यह एक्सपैंडिचर 15 हजार से कम नहीं होगा क्योंकि इसकी मेन वजह है कि आपका जो प्लान और नॉन प्लॉन का डिफरैंस है, वह 1.4% का है। यानी 2266 करोड़ रुपये प्लॉन और 8988 करोड़ रुपये की नॉन प्लॉन योजना है उसका एक्सपैंडिचर बढ़ेगा जो पैसा आपको आता है उसका सवा 44 प्रतिशत इन्ट्रैस्ट और लोन में वापिस चला जाता है। पिछले पांच साल में सरकार ने इतने लोन लिए हैं कि यह बढ़ कर तीन गुणा हो गया है। अगर पिछले साल के लोन को देखें तो यह ग्यारह हजार करोड़ था जो कि अब बढ़ कर 33 हजार करोड़ रुपये के आस-पास आता है और आपको इन्कम और एक्सपैंडिचर में यह दिखाया हुआ है। पहले आपको 39% लोन देना पड़ेगा

[चौ० जगजीत सिंह]

और उसके बाद आपका काम चलेगा और आपको ग्रान्ट इन ऐड 5 प्रतिशत मिलती है और दूसरी इन्कम 11.16 प्रतिशत आपने खर्च में दिखाई है। 44 प्रतिशत आपका रिपेमैंट ऑफ लोन तथा इन्ट्रैस्ट में चला जाएगा। (विघ्न) प्रोफैसर साहब, अगर मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ तो बता दें, मैं अपने आपको दुरुस्त कर लूंगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं हैल्थ डिपार्टमैंट के बारे में कुछ जिक्र करना चाहूँगा। हमारे रंगा साहब सुबह से ही पूरी तलवार निकाले हुए हैं कि 2.40 प्रतिशत बजट आपने हैल्थ के लिए रखा है। एग्रीकल्चर, जिसके नाम पर आपने खूब धूम मचाई और यह सरकार सत्ता में आई है उसके लिए 3.56 प्रतिशत आपने रखा है। रोड्ज और ट्रांसपोर्ट के अन्दर 11.42 प्रतिशत रखा है, इसमें सारे के सारे पैसे से बसें खरीदी जाएंगी और खूब कमीशन कमाया जाएगा। इरीगेशन के लिए 4.33 प्रतिशत रखा गया है और मेरे ख्याल से इतने पैसे से एक भी नहर नहीं सुधर सकती है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा और भी कई बातें इस बजट के बारे में मुझे कहनी हैं और बहुत सी और बातें हैं जो वित्त मंत्री जी को बजट में करनी चाहिए थीं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के की कुछ बातें भी यहां पर बताना चाहता हूँ और इसके साथ ही मेरा एक सुझाव भी है। सरकार ने जो सरकारी निगम और बोर्ड्ज बना रखे हैं उनमें 3068 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, जिसमें डिविडैंड 1.73 करोड़ रुपये यानी पौने दो करोड़ रुपये से भी कम मिला है। इसके अलावा इनके अन्दर जनता का पैसा भी लगा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह तो इस सरकार की योजना और काम करने का तरीका है। 14 बोर्ड्ज और कारपोरेशंज हैं, इनमें वर्ष 2002-2003 तक सरकार ने 1205.95 करोड़ रुपये निवेश किए और 1210 करोड़ रुपये का इसमें घाटा हुआ है यानि अब तक का निवेश खत्म हो गया।

एक आवाज : आपने ये आंकड़े कहां से लिये हैं?

चौ० जगजीत सिंह : मैंने यह आंकड़े इन बुक्स में से निकाले हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जो आंकड़े दिए गए हैं वे मूर्तरूप में होने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, रैवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से दादरी को जिला बनाने का मामला है। मुख्य मंत्री जी यहां पर बार-बार बड़ी फ्राखदिली से कहते हैं कि यह तहसील बना दी वह तहसील बना दी। मैं पिछले चार वर्षों से हर बार कहता रहा हूँ और इस बारे में मैंने क्वैश्चन भी दिया है कि दादरी को जिला बनाया जाए क्योंकि यह प्रदेश का सबसे बड़ा उप-मण्डल है और यहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं इसलिए इस पर भी गौर फरमाया जाए। (विघ्न) स्पीकर साहब, दादरी में सर्कल बाईपास बनाया जाना चाहिए। एक साईड से रेलवे लाईन जाती है और रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ शहर बसा हुआ है। दिल्ली रोड़ और रोहतक रोड़ की तरफ जो भी लोग नारनौल और महेन्द्रगढ़, पिलानी, भिवानी की तरफ निकलते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। वहां पर रेलवे सर्कल बाईपास बनाया जाना चाहिए, रेलवे का पुल शुरू होना चाहिए। पहले कॉलोनियों के नक्शे पास होते थे, नई कॉलोनी में 500 घर बने हैं जिनमें से 100 घरों के तो नक्शे पास हुए हैं लेकिन 400 घरों के नक्शे पास नहीं हुए हैं। जिन लोगों ने नक्शे पास करवाए हैं वे लोग टैक्स भी दे चुके हैं और उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं इस तरह की बातों पर भी सरकार को गौर करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे दादरी हल्के में कुछ सड़कें हैं जो कि बहुत ही जर्जर हालत में हैं मैंने दूसरी सड़कों का भी जिक्र किया था जैसे कि विरही खुर्द से पैंतावास कलां बाया पांडवान सड़क है।

श्री अध्यक्ष : जगजीत सिंह जी, आप वाईड-अप करें।

चौ० जगजीत सिंह : सर, मैं एक मिनट में खत्म करता हूँ। सर, मानकावास से दादरी बाया चरखी, जयश्री से बास बाया झींझर, भागेश्वरी और अचीना, नीमली से दादरी बाया सातौर भागवी,

लाम्बा से झींझर वाया कौहलावास, अटेला से सारंगपुर वाया ढोका हरिया, रामपुरा, ढोका मौजी से डुडीवाला वाया किशनपुरा की कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनकी बहुत ही बुरी हालत है। गाड़ी तो दूर रही, आदमी भी वहां से निकल नहीं सकता है। इस तरफ इस सरकार को ध्यान देना चाहिए और उनकी रिपेयर करवानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं बजट का विरोध करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : कृष्ण पाल गुर्जर, बी०जे०पी० के बोलें। ये सदन में अवेलेबल नहीं हैं। यह बहुत ही दु:ख की बात है कि बी०जे०पी० की पूरी की पूरी पार्टी बजट सत्र पर सीरियस नहीं है और उनका कोई भी सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है। बी०जे०पी० वाले अब सदन से बाहर जाकर ब्यान देंगे कि हमें सदन में बोलने को समय नहीं मिलता है, जबकि सदन में उनकी पार्टी का एक भी सदस्य नहीं है। कर्ण सिंह जी, आप बोलें।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रो० सम्पत सिंह जी को पिछले बजट की भी याद दिलाना चाहता हूँ। माननीय सम्पत सिंह जी को बजट पेश करने का बहुत ही अच्छा अनुभव है और ये काफी समय से हरियाणा सरकार में वजीर हैं। अध्यक्ष महोदय, आज के आधुनिक जमाने में कम्प्यूटर के माध्यम से, इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से दुनिया के किसी भी देश की अर्थ व्यवस्था के बारे में जाना जा सकता है। इस सरकार ने विधायकों को कम्प्यूटर दिए हैं और मैं उम्मीद करता था कि चौधरी सम्पत सिंह जी उस कम्प्यूटर का इस्तेमाल करेंगे। उस कम्प्यूटर की लाइनों को दुनिया की बेहतरीन अर्थव्यवस्था से जोड़ करके जानने की कोशिश करेंगे कि दूसरे देश किस तरह से तरक्की कर रहे हैं। लेकिन मुझे स्पीकर सर, बहुत दु:ख हुआ है कि जो बजट सम्पत सिंह जी ने इस बार प्रस्तुत किया है उसमें वही घिसी-पिटी बातें ही हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके के सारे अखबारों में चाहे वह हिन्दुस्तान टाईम्ज, दैनिक ट्रिब्यून या दूसरी अखबारें हैं उन्होंने सम्पत सिंह जी के बारे में लिखा है कि उन्होंने बजट के बारे में अलग-अलग वक्तव्य दिए हैं। यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, यह अखबारों में है। अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार प्रदेश के बारे में सही आंकड़े नहीं रखती है तो यह हरियाणा के लिए बहुत ही अफसोस और चिन्ता की बात है। यह प्रदेश के भविष्य के लिए चुनौती है। दैनिक ट्रिब्यून में चौधरी सम्पत सिंह जी आपके बारे में लिखा है कि आप जो बजट के माध्यम से यहां पर बजट प्लान के बारे में बोलते हैं, जो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, वास्तविकता में वे आंकड़े कहीं पर भी नजर नहीं आते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 2001 के बजट के ऐनुअल प्लॉन में 2100 करोड़ रुपये दिखाए थे, मैं इनको यह बताना चाहूँगा कि वास्तविकता में इन्होंने 1838 करोड़ रुपये का ही इस्तेमाल किया था। इसी तरीके से इन्होंने 2002 में ऐनुअल प्लॉन में 1922 करोड़ रुपये दिखाए थे, जबकि असलियत में ये 1850 करोड़ रुपये तक ही सीमित रहे थे। अब की बार अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 2175 करोड़ रुपये का ऐनुअल प्लॉन दिखाया है। इलाके के अखबार और इस सदन के सभी सदस्यों को इस बात की चिन्ता है कि अब की बार भी ये अपनी बात पर खरे नहीं उतरेंगे। अध्यक्ष महोदय, इससे नुकसान हरियाणा के लोगों का ही होगा। आज यही वजह है कि हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ रही है और यही वजह है कि हरियाणा की पर-कैपिटा इन्कम दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में बढ़ने की बजाए कम हो रही है। अध्यक्ष महोदय, पंजाब हमारा पड़ोसी स्टेट है। पंजाब की हरियाणा से ज्यादा पर-कैपिटा इन्कम है जबकि हरियाणा स्टेट दिल्ली के तीन तरफ लगती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रो० सम्पत सिंह जी से और इस सरकार से अनुरोध करूँगा कि अगर इस सरकार की नीयत ठीक है तो ये हरियाणा की पर-कैपिटा इन्कम बढ़ा सकते हैं। हरियाणा के बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिल सकता है। हमारी अर्थ व्यवस्था में सुधार आ सकता है। स्पीकर सर, एच०वी०पी०एन० लिमिटिड को कुछ अधिकार दिये गये थे और पिछले दिनों इस सदन में यह

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

बात आई थी कि यह सरकार आटोनोमस बॉडी के काम में क्यों दखल दे रही है। आज जो इतना घाटा आटोनोमस बॉडीज में नजर आ रहा है उसके बारे में कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की किताब में लिखा हुआ है कि जो बिजली के मीटर्ज इन्होंने खरीदे, वे मीटर कई कम्पनियां कम कीमत में देने के लिए तैयार थीं लेकिन इन्होंने उनके टैंडर्ज को इग्नोर किया और मीटर्ज को अधिक दामों पर लिया तो इस घाटे के लिए कौन जिम्मेवार होगा? क्यों यह सरकार एच०वी०पी०एन०एल० के कामों में दखल देने लग रही है? जब इन्होंने उसको एक प्राइवेट कम्पनी बना दिया तो सरकार को यह अधिकार नहीं है कि उसके कामों में दखल दे। इसी तरह हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी कमीशन है वह भी एक आटोनोमस बॉडी है उसके सदस्य जो इन्होंने अप्वायंट किए हैं वह इस ****** नहीं है। अखबारों में इस बारे में लिखा है।

श्री अध्यक्ष : इनकी यह बात रिकॉर्ड न की जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जो इस रैगुलेटरी कमीशन का मैम्बर है, वह सरकार की गाड़ी को लेकर गांवों में वोट मांगता फिरता है। यह कहां का कानून है? इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिएं। चाहे वह कोई भी हो, इनको निगाह रखनी चाहिए। स्पीकर सर, कई प्राईवेट कम्पनीज हरियाणा में आकर रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना चाहती हैं, मिसाल के तौर पर रिलायंस कम्पनी है, वह हरियाणा में अपना पेट्रोल पम्प देना चाहती है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, अब आप वाईंड-अप करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, मैं कोई गलत बात तो कह नहीं रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : गलत बात तो नहीं कह रहे हैं लेकिन आपका समय तो समाप्त हो गया है। आप दो मिनट में अपनी बात कहकर समाप्त करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, प्राईवेट कम्पनीज के पेट्रोल पम्प हरियाणा में देने के बारे में इन्होंने डी०सीज० को कह रखा है कि पेट्रोल पम्प के एन०ओ०सी० तब तक नहीं दिए जाएंगे, जब तक कि सरकार की तरफ से ऊपर से इशारा न किया जाए।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। इस तरह की अनर्गल बातें कहने से कोई फायदा नहीं है। चाहे वह रिलायंस कम्पनी हो, चाहे वह इंडियन ऑयल कम्पनी हो, चाहे वह हिन्दुस्तान पेट्रोलियम हो या चाहे वह भारत पेट्रोलियम या और कोई कम्पनी हो ये जगह आईडैन्टीफाई करती हैं, एडवरटाईजमैंट करती हैं, ऐलोकेशन होती हैं, लैण्ड देखती हैं और इसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। जो कम्पनीज कंडीशन पूरा करती हैं उनको ही एन०ओ०सी० मिलती है। जो कम्पनी कंडीशन पूरी नहीं करती हैं, उनको कैसे एन०ओ०सी० मिलेगी? इसके लिए बाकायदा एक सिस्टम बना हुआ है जो सिस्टम को पूरा नहीं करेगा उसको कैसे एन०ओ०सी० मिलेगी। इसलिए ऊपर नीचे की बात करना बेकार की बात करना है, इससे कोई फायदा नहीं है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, कोई परमिशन नहीं है आपके लिए, कोई प्वायंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। आप बैठ जाएं। (विघ्न) कैप्टन साहब, आपको बोलने की तमीज होनी चाहिए कि कैसे बोलना

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

है। आपकी पार्टी के दूसरे सीनियर मैम्बर्ज भी बैठे हैं। आप बैठें। दलाल साहब, आप बोलें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से और सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि बेरोजगारी की समस्या के साथ ही साथ एक सबसे बड़ी समस्या हाउसिंग की भी है। आज आप किसी भी शहर में देखें। चाहें आपके पानीपत में देखें या डिप्टी स्पीकर साहब के गुड़गांव में, फरीदाबाद में या और किसी भी शहर में देख लें, गांवों के लोग पलायन करके शहरों में बसना चाहते हैं लेकिन शहरों में सबको सरकार हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार को हाउसिंग की कैटेगरीज बनानी चाहिएं। सरकार ने सैक्टर जरूर डिवैल्प किए हैं लेकिन उनमें तो धनाढ्य लोग ही रह सकते हैं इसलिए इनको चाहिए यह हर तबके के लोगों के लिए मकान बनायें ताकि अनअथोराइज्ड कॉलोनीज डिवैल्प न हों। इनको गरीब लोगों के लिए, हरिजन लोगों के लिए और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अलग से मकान बनाकर प्रोवाइड करवाने चाहिएं।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। अभी जैसाकि दलाल साहब हाउसिंग के बारे में कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हुड्डा के सैक्टर्ज की तरह से कमजोर या गरीब लोगों के लिए भी मकान बनाने चाहिएं। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस सरकार के आने के बाद ई०डब्ल्यू०एस० के लिए भी मकान बनाये गए हैं। इसी तरह से एल०आई०जी० और एम०आई०जी० के लोगों के लिए भी जो 15 हजार मकान बनाये गये हैं उनमें से 95 परसेंट मकान वीकर सैक्शन के लोगों को अलॉट किए गए हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को आप पढ़ें और इसी तरह से पिछली इसकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वह भी आप मंगवाएं। हर विभाग को चाहिए कि कम्पट्रोलर के ऑफिस में अपने महकमें की हर कारगुजारी को भेजें। कम्पट्रोलर को

15-00 बजे

उन महकमों ने रिपोर्ट नहीं भेजी जिन महकमों में धांधली है, हेराफेरी है जिनमें पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आप रिपोर्ट मंगाइए कि कम्पट्रोलर के ऑफिस में दस्तावेज क्यों नहीं भेजे। इससे जाहिर होता है कि वे अपनी धांधलियों को छुपाना चाहते हैं। सरकार को रिपोर्ट्स भेजनी चाहिएं ताकि उन धांधलियों का सदन को पता चले। अध्यक्ष महोदय, आज गांवों में एक बहुत बड़ी समस्या है, जो पुरानी हवेलियां हैं या बड़े-बड़े गांव हैं, उनको बेचकर लोग अपने खेतों में मकान बनाने में लगे हुए हैं और कोई भी सरकार इस समस्या के बारे में जागरूक नहीं दिख रही है, गांव खाली होने लगे हैं और खेतों में लोग बसने लगे हैं। इस प्रदेश की जो संस्कृति है और जो गांव की सभ्यता है वह इससे समाप्त हो जाएगी।

प्रो० सम्पत सिंह : आप क्या चाहते हैं कि ढाणियों में रहने पर भी रोक लगा दें?

श्री कर्ण सिंह दलाल : दूसरे इन्होंने सैक्टर्स के बारे में कहा था कि गांवों में सैक्टर बनाएंगे। मेरा यह सुझाव है कि गांव में जो लाल डोरा है, उसको भी ऐक्सटैंड करना चाहिए। जो गरीब हरिजन हैं, दलित वर्ग के लोग हैं जो बड़े-बड़े गांव हैं वहां की औरतों को कई-कई किलोमीटर दूर लैट्रिन के लिए जाना पड़ता है, गांव में सरकार इसकी सहूलियत मुहैया कराए, जिससे कमजोर वर्ग के लोगों को सहूलियत मिले।

श्री अध्यक्ष : आप वाईड-अप करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं सरकार ने पिछले बजट में 20 हजार नयी नौकरियां सृजित करने के बारे में आश्वासन दिया था वह अब तक सृजित नहीं

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

हुई हैं और इस बजट में कोई भी नयी नौकरी सृजित नहीं की हैं। जो दस्तावेज दिए गए हैं उनमें लिखा है कि दालों का उत्पादन घट रहा है, इन्हें इस बात का इंतजाम करना चाहिए कि हरियाणा में दालों का उत्पादन बढ़े। इसी तरीके से जो इरीगेशन का सिस्टम है आज हरियाणा का किसान नहर, रजबाहे या नाली को काटकर अपनी फसल को पानी दे देता है और उससे क्या होता है कि जो अंतिम छोर पर किसान है उसको पानी नहीं मिल पाता है इसलिए सरकार को स्प्रिंकलर सैट्स को बढ़ावा देना चाहिए इसका लाभ हरियाणा के अंतिम छोर पर बैठे हुए किसानों को होगा और पानी मिलेगा तो कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। मैंने पहले भी कंट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कहा था हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो दिल्ली के तीन तरफ लगता है दिल्ली के लोग आर्गेनिक फूड को बहुत पसंद करते हैं जिसमें खाद और रसायन न हो। अत: मेरा कहना है कि वित्त मंत्री जी कोई कार्पोरेशन इसके लिए बनाएं या अपने किसी डिपार्टमैंट को कहें कि हरियाणा में इसकी व्यवस्था करें कि जो किसान आर्गेनिक खेती करेंगे उनको सरकार रियायत देगी, वित्तीय सहायता देगी। दिल्ली के लोग आर्गेनिक खेती से पैदा हुई सब्जियों को खरीदना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : दिल्ली के लोग ही क्यों खरीदना चाहते हैं, क्या हरियाणा के लोग नहीं खरीदना चाहते हैं? क्या करनाल, पानीपत, फरीदाबाद और गुड़गांव के लोग नहीं खरीदना चाहते हैं?

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़े-बड़े शहरों के लोग आर्गेनिक खेती से पैदा हुई सब्जियां व अन्य पदार्थ खरीदना चाहते हैं लेकिन हरियाणा में इसका कहीं कोई मोटीवेशन नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश के लोग मध्य प्रदेश का गेहूँ खाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठ जाइए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव हैं, वह मैं देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त कर दूँगा। जो आपने एम०एल०एज० के लिए नये फ्लैट्स बनाए हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उसकी दीवारों में अभी से दरारें आनी शुरू हो गई हैं आज कोई भी चीज बनती है उसमें अगले ही दिन से दरारें आनी शुरू हो जाती हैं आपका जो आर्कीटैक्चर डिपार्टमैंट है वह इस चीज की क्या कोई जांच पड़ताल करता है? वे क्यों नहीं जाकर खोज करते हैं कि जो यह दरारें हैं उनसे पानी टपकता है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, अगर ऐसी कोई बात है तो आप इस बारे में अलग से लिखित में दे दें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : गुड़गांव के बारे में मैं कहना चाहता हूँ जो कि माननीय डिप्टी स्पीकर साहब का इलाका है और हरियाणा का एक खूबसूरत शहर है। वहां पर इस बात की जरूरत है कि जितने भी सी०एल०यू० हैं उनको फौरन बंद कर दिया जाए क्योंकि वहां पर आज इतना पोल्यूशन है कि वहां की सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। अगर उस शहर को डिवैल्प करना है तो कोई दूसरी जगह चुन ली जावे। स्पीकर सर, पानीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद में किसानों की जमीन में जहां पर मीठा पानी है, उस जमीन को सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों और सैक्टर बनाने के लिए एक्वायर किया जा रहा है। अगर सरकार ने जमीन एक्वायर करनी ही है तो जो जमीन बंजर है, जिस जमीन के नीचे खारा पानी है, जहां पर खेती नहीं होती उस जमीन को एक्वायर किया जाये और फिर चाहे वहां पर रेजीडैंशियल कॉलोनी बनाई जायें और चाहे यूनिवर्सिटी बनाई जाए। सरकार द्वारा

पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, यमुनानगर में जमीन एक्वायर करके किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। चौधरी सम्पत सिंह जी को बजट बनाने से पहले अच्छे-अच्छे इकोनोमिस्ट्स को बुलाना चाहिये था (विघ्न)।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल जी, आप बैठिये। आपका समय समाप्त हो गया है। इनकी कोई बात रिकॉर्ड न की जाये।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित साथी को बताना चाहता हूँ कि जो इन्होंने अभी जिक्र किया कि सरकार को वह जमीन एक्वायर करनी चाहिये जिसके नीचे खारा पानी है, जो जमीन बंजर है और बेकार हो गई है। माननीय सदस्य को इस बात का ज्ञान होना चाहिये कि जिस जमीन पर सैक्टर या कॉलोनी बनाई जाती है या कोई इण्डस्ट्री लगाई जाती है तो जो आदमी जमीन लेता है वह बाकायदा उस जगह को लेने से पहले इस बात को देखता है कि इस जमीन के नीचे पानी कैसा है और विशेषतौर पर जो इन्डस्ट्री लगाता है वह तो मिट्टी को टैस्ट करवाता है और यह देखता है कि यह मिट्टी इन्डस्ट्री लगाने के काबिल है या नहीं। इतने लम्बे समय तक माननीय सदस्य मंत्री भी रहे हैं और अपने को बी०ए०, एल०एल०बी० बताते हैं। इनको इतना तो ज्ञान होना चाहिये कि बंजर जमीन की कहीं कोई कीमत नहीं हुआ करती है और अगर बंजर जमीन इस तरह सरकार यूज में लेने लगी और अगर सरकार ने जमीन को आगे बेचना शुरू कर दिया तो सरकार के पास रैवेन्यू का साधन ही नहीं रहेगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं इसको सरकार की पोलिसी मान लूं जो कि माननीय सदस्य ने कहा है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इन्होंने तो अपने प्वाईंट ऑफ ऑर्डर पर अपनी बात रखी है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल जी, आप बैठिये इनकी कोई बात रिकॉर्ड न की जाये।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से जवाब तो चौधरी सम्पत सिंह जी देंगे उस समय ये सरकार का जवाब सुन लें।

श्री राम किशन फौजी (बवानी खेड़ा अ०जा०) : अध्यक्ष महोदय, जो बजट माननीय सम्पत सिंह जी ने पेश किया उस पर आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इस बजट के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि जैसे सम्राट जादूगर अपनी जादूगरी दिखाता है ऐसे ही माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बजट पेश करते हुए अपनी जादूगरी दिखाई और बजट पेश करते हुए कहा कि यह टैक्स फ्री बजट है। अध्यक्ष महोदय, बजट पास होते ही सरकार द्वारा रात-दिन टैक्स लगाये जाते हैं, इतने टैक्स लगाये जाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। जिस प्रकार से घाटा बढ़ता जा रहा है उससे तो हरियाणा सरकार का दिवाला ही निकल जायेगा और लोन के पैसे की वापसी हो नहीं पायेगी जिसके

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री राम किशन फौजी]

कारण हमारे किसानों और व्यापारियों पर टैक्स लगेगा, वे लोग टैक्स के बोझ से दब जायेंगे जिसको वे दे नहीं पायेंगे। इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि* * *

श्री अध्यक्ष : राम किशन जी ने जो अनपार्लियामैंट्री शब्द कहे हैं वे रिकॉर्ड न किए जायें।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो सुझाव दे रहा था। सिंचाई के लिए बजट में 734.49 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि दक्षिणी हरियाणा जिसमें भिवानी जिला भी आता है और मेरा हल्का भी आता है वहां के लिए बजट में अलग से पैसा रखना चाहिए था। क्योंकि दक्षिणी हरियाणा रेतीला एरिया है जहां बालू रेत के टिब्बे हैं इसलिए वहां पर सिंचाई के लिए अलग से पैकेज रखना चाहिए। ताकि वहां के किसानों को राहत मिल सके और वे दूसरे किसानों के मुकाबले खेती कर सकें। अध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली के बारे में कहना चाहूँगा कि बजट में 1320.42 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्य मंत्री जी ने भी कहा और सत्ता पक्ष के दूसरे साथियों ने भी कहा कि मौजूदा सरकार ने 36 हजार ट्यूबवैल के कनैक्शनज दिए हैं। मैं इन आंकड़ों में नहीं जाता कि असलियत में कितने कनैक्शनज दिए गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मौजूदा सरकार के समय में जिन किसानों को कनैक्शनज दिए गए हैं वे कितने-कितने लाख रुपये के हिसाब से दिए गए हैं। मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि कनैक्शनज के रेट कम किए जाएं। ज्यादातर किसान ब्याज पर या अपनी जमीन गिरवी रखकर ट्यूबवैल कनैक्शन के लिए पैसा जमा करवाते हैं, इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि पोल और केबल के लिए जो पैसे जमा करवाये जाते हैं, उनकी कीमत कम की जाये। हमारी सरकार के समय में 10 हजार रुपये में ट्यूबवैल कनैक्शन दिया जाता था। (शोर एवं व्यवधान) जिस समय हरियाणा बना उस समय हरियाणा की क्या हालत थी? चौधरी बंसी लाल जी ने ही हरियाणा का विकास किया है। सारे काम उन्होंने ही करवाये हैं।

श्री नफे सिंह जुण्डला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। अध्यक्ष महोदय, जिस समय चौधरी बंसी लाल जी मुख्य मंत्री थे उस समय वे कहते थे कि 24 घंटे में ट्यूबवैल कनैक्शन दिए जायेंगे, 24 घंटे में ट्रांस्फार्मर ठीक किए जायेंगे, 24 घंटे बिजली दी जायेगी। मेरे कहने का भाव यह है कि उन्होंने 24 घंटे की रट पकड़ रखी थी लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। उन्होंने पूरे तीन साल तक इस सदन को और हरियाणा की जनता को गुमराह करके रखा। उसके बारे में भी फौजी भाई जरा सदन को बता दें। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने तो पिछले चार साल में प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ काम किए हैं। इनकी सरकार के समय में एक साल में एक हजार ट्यूबवैल कनैक्शन दिए जाते थे और हमारी सरकार के पिछले चार साल के कार्यकाल में 36 हजार कनैक्शनज दिए गये हैं।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि ये सरकार की चाहे जितनी भी तारीफ कर लें इनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश के अन्दर बिजली के हालात बहुत खराब हैं जबकि मुख्य मंत्री जी का अखबार में एक बार एक ब्यान आया था कि हमने पानीपत थर्मल प्लांट की एक यूनिट इसलिए बन्द करनी पड़ी कि हमने इतनी बिजली पैदा की कि हमारे यहां पर बिजली सरप्लस हो गई थी।

श्री अध्यक्ष : आप ये बातें गवर्नर एड्रैस पर कह चुके हैं इसलिए आप इन बातों को रिपीट न करें।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि किसानों को 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती और जो मिलती है उसमें भी पावर कम होती है जिससे किसान को नुकसान होता है और कई बार उनकी मोटरें भी जल जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि किसानों के लिए बिजली का प्रबन्ध करें, खाली वाह-वाही लूटने की कोशिश न करें। मुख्यमंत्री ने यहां पर बोलते हुए एस०वाई०एल० के बारे में कहा था। एस०वाई०एल० के बारे में इस बजट में भी जिक्र है। चौधरी बंसी लाल जी ने एस०वाई०एल० बनवाई थी। (विघ्न) चौधरी बंसी लाल जी ने तो गांवों के लोगों को व सरपंचों को मौके पर ले जा कर दिखाया था कि नहर बनायी गई है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि बंसी लाल जी ने यह नहर पुंड से निकलवाई। मैं बताना चाहूँगा कि पंजाब की तरफ झगड़ा था इसलिए पहले उन्होंने अपने एरिया में यह नहर बनवाई। चौधरी बंसी लाल जी ने अपने हरियाणा में लास्ट से इसलिए बनाई ताकि आगे के लिए हम क्लेम कर सकें। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि चौधरी बंसी लाल जी ने न कभी नहर में कमीशन खाया और न कभी उनकी कमीशन खाने की तमन्ना थी।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : ऑन-ए-प्वांयट ऑफ ऑर्डर सर, स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जिस समय यह काम शुरू हुआ था उस समय पंजाब के अन्दर कहीं किसी तरह का उग्रवादपन नहीं था। पूरा देश शांतिप्रिय तरीके से चल रहा था इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपनी बात कहें। आपके नेता भी ऐसा ही बोलते हैं और आप भी ऐसे ही बोलते हो। आप हाउस में आंकड़े सही दिया करो। (विघ्न)

Mr. Speaker : At that time, he was a school-boy.

Shir Puran Singh Dabra : Even he may not have been in the world at that time.

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, अब मैं माईन्ज के बारे में बात कहना चाहता हूँ। जब इस सरकार ने पहले पहाड़ों की बोली छोड़ी थी तो उस वक्त सरकार ने बड़ी वाह-वाही लूटी थी। (विघ्न) * * * *

श्री अध्यक्ष : इनकी यह बात रिकॉर्ड न की जाए।

श्री रणबीर सिंह : ऑन ए प्वाईंट ऑफ ऑर्डर सर,। स्पीकर साहब मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर भगवा वस्त्रों की एक गरिमा है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसका चरित्र कैसा भी हो। जो आदमी भगवा वस्त्र धारण करता हो उसके आगे सब नत-मस्तक होते हैं। इन लोगों ने उन भगवा वस्त्रों की भी गरिमा नहीं छोड़ी। ये लोग उस वक्त भगवा वस्त्र की झण्डी लगाकर शराब की तस्करी कर रहे थे। * * *

श्री अध्यक्ष : इनकी यह बात रिकार्ड न की जाये।

श्री राम किशन फौजी : स्पीकर साहब, शराब की तस्करी वे करते थे जो ग्रीन ब्रिगेड के सदस्य थे। वह ग्रीन ब्रिगेड चौधरी देवी लाल जी के समय में बनाई गई थी। उस ब्रिगेड में रामबीर जी भी थे। इन्होंने उस वक्त शराब की तस्करी की थी। (विघ्न) वह तुम्हारे से पीछा छुड़वा गया। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : राम किशन जी, आपका समय समाप्त हो गया है कृपया आप बैठ जाएं।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

चौ० जय प्रकाश : निकम्मे ग्रीन ब्रिगेड वालों को छोड़कर मैं वहां से यहां आ गया। (विघ्न) सारा निकम्मापन उधर छोड़कर आ गया।

श्री अध्यक्ष : तो आप ग्रीन ब्रिगेड के सदस्य थे।

श्री जय प्रकाश : मैं तो 1990 में छोड़कर आया था। (विघ्न) आप भी मेरी ग्रीन ब्रिगेड के सदस्य थे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हम तो थे नहीं ग्रीन ब्रिगेड में। जो अपने आपको ग्रीन ब्रिगेड के सदस्य समझते थे वे छोड़ कर उधर चले गये हैं। (विघ्न)

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, यमुना माईन्ज पर करोड़ों रुपया कमाया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के रैवेन्यू का नुकसान हो रहा है और हमारी जो रोड़ एक लाख रुपये में एक किलोमीटर बनती थी, अब वह 10 लाख रुपये में बनती है क्योंकि इन्होंने माईन्ज की रोड पर जो लोग बिठा रखे हैं वे 100 फुट बजरी पर 350 रुपये लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह जनता के साथ बहुत ही ज्यादती है। मैं यह निवेदन करता हूँ कि इस पैसे को सरकारी खजाने में लाया जाए ताकि हमारे बजट का जो घाटा है वह कुछ हद तक कम हो सके (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, 600 रुपये की 100 फुट जो बजरी मिलती थी आज उसकी कीमत बढ़कर 1400 रुपये हो गई है, यह बहुत ही चिन्ता की बात है। जिस तरह से ये कीमतें बढ़ा रहे हैं, यह बिल्कुल गलत बात है, इस पर सरकार को सोचना चाहिये और इस बारे में जांच करवाई जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : फौजी साहब, अब आप बैठें। (विघ्न) आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन मिनट का और समय लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कुछ और बातें कहनी हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आपने तो चौधरी बंसी लाल जी का टाईम भी ले लिया है, अब आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने के लिये और समय नहीं दे रहे हैं आपने बोलने के लिये मुझे जो समय दिया है उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आपकी तीसरी लिस्ट मेरे पास आ गई है क्या कोई चौथी लिस्ट तो नहीं है? आज ही हमने बजट पर डिस्कशन समाप्त करनी है और 16 तारीख को माननीय वित्त मंत्री जी अपनी रिप्लाई देंगे। अगर आपने किसी और मैम्बर को बुलवाना है और चौथी लिस्ट देनी है तो वह भी दे दें। जिसको भी बुलवाना है, आप आज ही बुलवा लें मण्डे को किसी को भी बोलने के लिए समय नहीं मिलेगा।

श्री अनिल विज : (अम्बाला छावनी) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बजट सत्र में प्रोफैसर सम्पत सिंह वित्त मंत्री हरियाणा ने जो अपना बजट प्रस्तुत किया है उस पर अपने विचार प्रकट करने के लिए आपने मुझे अवसर प्रदान किया है। अध्यक्ष महोदय, प्रोफैसर सम्पत सिंह

जी का यह पांचवा बजट है जो इस हरियाणा विधान सभा में पेश किया गया है। इससे पहले भी ये चार बजट प्रस्तुत कर चुके हैं इसलिये इस बजट पर चर्चा करने से पहले मैं समझता हूँ कि पिछले वर्ष में जो बजट प्रस्तुत किया गया था और इकोनोमिक सर्वे यहां पर प्रस्तुत किया गया है उसका अवलोकन करना अत्यावश्यक है। From the perusal of the economic survey presented by the department, अगर हम इसको गौर से देखें तो इसमें 5.2 ग्रोथ रजिस्टर्ड होना बताया गया है। अगर हम इसको सैक्टरवाईज देखें कि इस 5.2 % में सैक्टरवाईज इसमें क्या कण्ट्रीब्यूशन है। तीन सैक्टर्ज जो इम्पोर्टैंट सैक्टर्ज हैं उनमें कण्ट्रीब्यूट करते हैं। प्राईमरी सैक्टर में it has registered a decline of 0.8% स्पीकर सर, प्राईमरी सैक्टर में जो हमारा एग्रीकल्चर सैक्टर का कण्ट्रीब्यूशन है जिसमें एग्रीकल्चर सैक्टर से जुड़ी हुई चीजें शामिल की जाती हैं तो एक तरह से यह चिन्ता का विषय है। हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि में पिछली बार डिक्लाईन रजिस्टर्ड की थी और इस बार भी डिक्लाईन रजिस्टर्ड की है जो कि चिन्ता का विषय भी है और इण्डिकेटिड भी है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को किस दिशा में लेकर जाना चाहिये और किस दिशा में इसको आगे बढ़ाना चाहिये ताकि हम अपने प्रदेश को, इक्नोमिक ग्रोथ को , फाईनैंशियल मैनेजमैंट में जो हमारे साधनों की प्राथमिकता है, हम इस ढंग से नियोजित कर सकें ताकि उसको ठीक ढंग से व्यवस्थित किया जा सके। इसी प्रकार से सैकेण्ड सैक्शन जिसमें मैन्यूफैक्चरिंग आती है, ट्रेडिंग आती है उसमें we have registered a growth of 5.8 % यह भी इण्डिकेटिड है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर अनर्गल प्रचार करते हैं कि हरियाणा से उद्योग धन्धे बन्द हो कर चले गए कारखाने बन्द हो गए। स्पीकर सर, कोई झूठ बोल सकता है, विपक्ष के नेता झूठ बोल सकते हैं, मैं झूठ बोल सकता हूँ लेकिन आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं। यह जो ग्रोथ 5.8 % रजिस्टर्ड की है। it is indicated कि हमारी स्टेट में इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ अपनी अहम भूमिका निभा रही है। हमारे कारखाने बढ़ रहे हैं। हमारे प्रदेश की मैनुफैक्चरिंग एक्टिविटी में इजाफा हो रहा है और यह बहुत बड़ी कन्ट्रीब्यूशन 5.8 प्रतिशत की जी०एस०जी०पी० में मैनुफैक्चरिंग साईड से आई है। अध्यक्ष महोदय, जो तीसरा सैक्टर है, जिसमें ट्रेडिंग आती है, इसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग आनरशिप, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अदर सर्विसिज सैक्टर्ज आते हैं it has also recorded an excellent growth of 9.2 % स्पीकर सर, कुल मिलाकर हमारे वित्तिय प्रबन्धन किस दिशा में जा रहे हैं, यह बहुत ही सीरियस बात है, इसकी बहुत ही उचित तरीके से व्यवस्था की जा रही है। स्पीकर सर, यह जो बजट 2175 करोड़ रुपये का प्रस्तुत किया गया है, इसके लिये मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने इसमें घाटे को कम करने का प्रयास किया है। आज सारे देश के अर्थशास्त्री इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं कि हमारे फिसकल डैफिसिट जल्दी से जल्दी कम किये जायें और यह खत्म होनी चाहिये। हमारे प्रोफैसर साहब ने इस बार हमारा जो घाटा है, उसमें लगभग 99 करोड़ रुपये का इजाफा हो रहा है, उसको काफी कम करने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूँ कि इसको और कम किया जा सकता है, हमें इसको और कम करना चाहिये। मैं इस बारे में सुझाव देना चाहूँगा कि हम अपने कुछ खर्चों में कटौती कर सकते हैं और इन खर्चों में कटौती करके जनता का कोई नुकसान नहीं होगा। स्पीकर सर, जैसे हमारे प्रदेश में चार डिवीजन हैं और हम इन डिविजन्ज को खत्म कर सकते हैं। चार डिविजन्ज में चार डी०आई०जीज० लगाये हुये हैं। अध्यक्ष महोदय, यह उस वक्त की व्यवस्था थी जब संदेश घोड़ों के माध्यम से पहुंचाये जाते थे। आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग का जमाना है। आज मुख्यमंत्री और चीफ सैक्रेटरी सीधे बैठकर डी०सीज० से जोकि हर जिले के अन्दर एग्जीक्यूटिव एजैंसीज हैं, से रूबरू होकर बात कर सकते हैं। आज ये जो बड़ी-बड़ी कोठियों में बड़े-बड़े दफ्तर हैं, यह सब अंग्रेजों के

[श्री अनिल विज]

टाईम की व्यवस्था थी, अगर सरकार चाहे तो इनको बंद करके उनके ऊपर होने वाले खर्चों को बचा सकती है। अगर हमने लोगों को सुविधा ही देनी है तो हमारे स्टेट में 47 सब-डिविजन्ज हैं, यह सरकार उनको बढ़ा करके 90 कर सकती है। हर विधान सभा क्षेत्र के लिये एक सब-डिवीजन बना सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, तोशाम को सब-डिवीजन बनाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, कभी कहीं से सब डिवीजन की मांग आती है और कभी कहीं से मांग आती है। हम यह सैद्धांतिक तौर से कर सकते हैं कि हर विधान सभा क्षेत्र को हम एक सब-डिवीजन का दर्जा दें। अध्यक्ष महोदय, इनमें लोगों का सीधा वास्ता पड़ता है, कमिश्नर से किसी को वास्ता नहीं पड़ता है और न ही कमिश्नर के पास किसी को जाना पड़ता है। सब-डिवीजन में हर आदमी को लाईसैंस बनवाने के लिये या किन्हीं दूसरे कामों के लिये जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, अगर यह सरकार चाहे तो 47 सब-डिविजन्ज को 90 किया जा सकता है। इसके साथ ही तहसील भी 67 हैं उनको भी बढ़ाकर 90 किया जा सकता है। लेकिन जो कमिश्नर की पोस्ट पर और डी०आई०जी० की पोस्ट पर बैठे हुये हैं, जोकि सिर्फ मिडल मैन का काम करते हैं, सिवाए इसके उनका वहां पर कोई काम नहीं है क्योंकि एग्जीक्यूटिव एजैंसीज डी०सीज० और एस०पीज० होते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह कहना है कि इस व्यवस्था को खत्म करके हम काफी पैसे बचा सकते हैं। इसी प्रकार से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यह मेरी व्यक्तिगत राय है हालांकि यह बात हाउस की परिव्यू में नहीं आती है, हाउस के परिव्यू से बाहर की है लेकिन केन्द्र सरकार गवर्नर की पोस्ट को भी खत्म कर सकती है। उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, गवर्नर का काम खाली ओथ दिलाना है, तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी ओथ दिला सकता है। अध्यक्ष महोदय, आज हम जब राष्ट्र के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर सब उपायों के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हम इन सब चीजों के बारे में गौर कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसी और भी पोस्ट्स हैं जो अपने काम को कोई अंजाम नहीं देती हैं जैसे ड्रग इंस्पैक्टर्ज, शौप इंस्पैक्टरर्ज, और लेबर इंस्पैक्टरर्ज हैं ये सिर्फ पैसे इक्कठे करने के सिवाए कोई और काम नहीं करते हैं। यह सरकार इस प्रकार की पोस्ट्स को भी छांटकर खत्म कर सकती है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर सदन की सहमति हो तो सदन का समय एक घण्टे के लिये बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन का समय एक घण्टे के लिये बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2004-05 के लिये बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा
(पुनरारम्भ)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, यह बजट 2175 करोड़ रुपये का प्रस्तुत किया गया है, इस बजट में इस अमाउन्ट का विभाजन बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार का मुख्य काम यह होता है कि वह एक अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाईड करे। स्पीकर साहब हमारा प्रदेश

दिल्ली के साथ लगता हुआ प्रदेश है इसी कारण पूरे हिन्दुस्तान में विदेशी निवेश के लिये सबसे उपयुक्त कोई प्रान्त है तो वह हरियाणा प्रान्त है। आज फोरेन पूंजी निवेश भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। अगर हरियाणा प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर और ज्यादा ध्यान दिया जाये तो ठीक रहेगा। जिस तरह से पिछले पांच वर्षों से हम इन्फ्रास्ट्रक्चर पर पूरा जोर दे रहे हैं। पूरी तवज्जो दे रहे हैं वैसी ही तवज्जो इस बार भी बजट में दी गई है। इस बार प्रस्तावित परिव्यय का 43.3 फीसदी इस पर खर्च करने का प्रावधान है। यह एक सराहनीय कदम है। अध्यक्ष महोदय, सरकार की दो मुख्य जिम्मेवारी हैं एक जिम्मेवारी है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की और दूसरी जिम्मेवारी है सोशल सैक्टर पर ध्यान देने की। इस बार भी बजट में सोशल सैक्टर के लिये 919.87 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जोकि कुल परिव्यय का 42.3 फीसदी है। यह भी एक सराहनीय कदम है। सोशल सैक्टर में सरकार पहले ही कई सराहनीय काम कर रही है। स्पीकर साहब, मैं इनमें से केवल चंद बातों का वर्णन करना चाहूँगा क्योंकि सदन में काफी आंकड़ेबाजी हो चुकी है। 'सरकार आपके द्वार' जो कार्यक्रम है इसकी जितनी भी सराहना की जाये उतनी ही कम है। मैं समझता हूँ कि बाकी प्रदेशों की सरकारों को भी इस बारे में यहां पर लाकर ट्रेनिंग दी जानी चाहिये कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री हर जिले में हर क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनके काम करते हैं। इसी तरह से बजट में गांवों में जो सैक्टर बनाने की बात कही गयी है वह भी एक अच्छी सोच है। बजट में इसके लिये प्रावधान भी किया गया है। अब गांव वालों को शहरियों की तरह सुविधायें दी जायेंगी ताकि गांव वाले शहरों की ओर न भागें तथा शहर और कंजस्टेड न हो जायें। हर जिले के एक गांव में इस तरह के सैक्टर बनाने का प्रावधान किया गया है। इन सैक्टरों में सिवरेज की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था होगी, अच्छी सड़कें दी जायेंगी ताकि आज जो लोग भागकर शहरों में आकर नाजायज बस्तियों में बस रहे हैं वे वहां आने के बजाये अपने गांवों में ही रहकर इन सुविधाओं का लाभ उठायें। ऐसा करने से उनके गांव भी माडर्न गांव बन सकेंगे और वे वहीं पर रहकर अपनी खेतीबाड़ी को भी देख सकेंगे तथा शहर जैसी सुविधाओं का फायदा भी वे उठा सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, बिजली के क्षेत्र में भी सराहनीय काम हुये हैं। 2003 में रिकॉर्ड बिजली की वृद्धि की गयी है। 560 लाख यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से बिजली पैदा की गयी है। इन्डस्ट्रीज के क्षेत्र में भी सराहनीय काम हुये हैं। इस साल लगभग 197 बड़े उद्योग और लगभग 4500 छोटे उद्योग हमारे प्रदेश में लगे हैं। इसी से मैं समझता हूँ कि आज प्रदेश में व्यापारियों को कई सहूलियतें दी जा रही हैं, लोगों को अपना धंधा लगाने के लिये एकल खिड़की की सुविधा प्रदान करवायी जा रही है। अब लोग आकर्षित होकर अपना कारोबार लगा रहे हैं। विदेशी पूंजी निवेश भी 3132 करोड़ रुपये तक बढ़ा है। जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा खुशी की बात है वह यह है कि हरियाणा ने साफ्टवेयर एक्सपोर्ट में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्ष 2002-2003 के दौरान साफ्टवेयर एक्सपोर्ट 4450 करोड़ रुपये तक हो गया है और अभी इसमें और आगे बढ़ने की गुंजाईश है क्योंकि हमारे प्रदेश में सब तरह की सुविधाएं प्राप्त हैं। इसी तरह से हमारा एजुकेशन के हिसाब से भी सबसे अच्छा है। यहां पर 34 इंजीनियरिंग कालेज खोले जा चुके हैं जिनमें 10631 सीट्स का प्रावधान है इसके अलावा कई और इंजीनियरिंग कालेज भी खोले जा रहे हैं। इन कालेजों में सरकार ने छात्रों को एम०बी०ए०, एम०टैक० और एम०सी०ए० आदि कोर्सिज करने की सुविधायें दी हैं। इसी तरह से मैडीकल के क्षेत्र में भी सरकार प्रदेश में अच्छा काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक योजना जो सरकार द्वारा मुहैया करवायी जा रही है, का वर्णन जरूर करना चाहूँगा। जो प्राईवेट डॉक्टर्ज हैं वे शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले शहरी गरीब लोगों का इलाज करेंगे। शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिये व्यवस्था की गयी है कि वे

[श्री अनिल विज]

प्राईवेट डॉक्टर से जहां पर अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हों और जहां टैस्ट की व अन्य सभी सुविधाएं हों, उनको वहां से ट्रीटमैंट की सुविधा प्रदान की जा रही है जिसका खर्च सरकार वहन करेगी। जो गरीब आदमी है और प्राईवेट डॉक्टर से इलाज कराने की इच्छा रखता है उसके लिये एक बहुत ही शानदार योजना शुरू की गई है। हरियाणा में जो ये शानदार ऐक्सपैरिमैंट शुरू किया गया है उसके लिये मैं हैल्थ मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इससे प्राईवेट इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधायें गरीब जनता को मिल सकेंगी।

श्री अध्यक्ष : आप वाइंड-अप करें।

श्री अनिल विज : देखी रक्षक योजना जो शुरू की गई है उसके लिये भी सरकार की जितनी सराहना की जाये कम है। सर मुझे अपने हल्के के बारे में एक दो महत्वपूर्ण बातें और कहनी हैं। सर, 2007 में आजादी की पहली लड़ाई की 150वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी और मैं पहले भी इस सदन में इस बारे में कह चुका हूँ कि 1857 में आजादी की पहली लड़ाई अम्बाला छावनी से आरम्भ हुई थी जैसा मंगल पांडे की किताबों में वर्णन आता है वैसे तो यह है कि मेरठ से आजादी की लड़ाई का बिगुल बजाया गया था लेकिन मैंने दस्तावेजों का अध्ययन किया है और पाया है कि आजादी की पहली लड़ाई की शुरुआत अम्बाला छावनी से की गई थी। 60वीं इन्फैंट्री जिसे काली पलटन भी कहते थे उसके हिसाब से सुबह 9.00 बजे हथियार उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया गया था और अम्बाला छावनी से क्रांति आरम्भ हुई थी और उसकी तिथि 10 मई रखी गई थी। मैं ऐसा भी मानता हूँ कि सारे हिन्दुस्तान में क्रांति बराबर शुरू हुई थी लेकिन शुरुआत अम्बाला छावनी से की गई थी। और 10 मई को ही की गई थी। 10 मई को संडे था, उस दिन एक नये चर्च का उद्घाटन होना था और जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ऐसी योजना बनाई थी कि दस मई को संडे के दिन सारी अंग्रेज फौज और उनके अफसर चर्च में एकत्रित होंगे। वहां से आजादी की लड़ाई को आरम्भ करना था। हमारी सरकार ने शहीदों के लिये बहुत कुछ किया है। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुये)** शहीदों के लिये और स्वतंत्रता सेनानियों के लिये रोहतक में स्मारक बनाये जा रहे हैं। इसी तरह से 1857 की घटना भी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। उसके लिये भी एक समिति बनाई जाये वही सारे तथ्यों को उजागर करे कि 2007 में सारे हिन्दुस्तान में 150वीं वर्षगांठ जो मनाई जाएगी इसको प्रदेश स्तर पर उन वीरों की याद में अम्बाला छावनी में मनाया जाये क्योंकि 15 अगस्त और 26 जनवरी को उन वीरों की रूहें रोती हैं कि आखिर इस आजाद हिन्दुस्तान के वासियों ने हमें क्यों भुला दिया। इसे प्रदेश स्तर पर अम्बाला छावनी में मनाया जाये। और अम्बाला छावनी में एक स्मारक उनकी याद में बनाया जाये ताकि उन वीरों को सम्मान दिया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो बातें और कहना चाहता हूँ सरकार ने कर रहित बजट प्रस्तुत किया है और बजट में काफी सारे रिलीफ दिये हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। लेकिन समय की कमी है। एक सुझाव जोकि बहुत महत्वपूर्ण है, वह मैं सरकार को देना चाहता हूँ कि सरकार ने एक प्रोफैशनल टैक्स लगाया हुआ है, जो छोटे-छोटे दुकानदार हैं जिनकी मुश्किल से एक हजार रुपये की आमदनी होती है, साल में एक बार उनको यह टैक्स देना पड़ता है, उससे सरकारी खजाने में भी कोई ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है, जबकि लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। यह सरकार बड़ी दरियादिल है और गरीबों का हित सोचने वाली सरकार है, सभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका देने वाली सरकार है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रोफैशनल टैक्स से हरियाणा के लोगों को निजात दिलाई जाये। मेरे हल्के की कुछ योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं जैसे

कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम है। इसी प्रकार से फ्लड रोकने के लिये गुड़गुड़िया नाला है, उसका सब काम मंजूर हो चुका है, पैसा मंजूर हो चुका है लेकिन विभाग की सुस्ती चल रही है, उस कार्य को गति प्रदान की जाये। हमारे शहर में अनाज मण्डी की जगह 80 एकड़ जमीन एक्वायर की जा चुकी है जहां पर हुड्डा सैक्टर बनाने जा रहा है और भूमि एक्वायर हो चुकी है वहां पर मण्डी बनाने का कार्य शुरू किया जाये। जो अनएथोराईज्ड कालोनीज हैं, वहां पर 18000 परिवारों में 60000 लोग रहते हैं और पिछले 30-40 सालों से रह रहे हैं और उनमें से 70-80 प्रतिशत लोगों ने अपना नक्शा पास करवाकर डिवैल्पमैंट चार्जिज देकर के अपने मकान बनाये हैं फिर भी उन परिवारों पर अनएथोराईज्ड कालोनी की तलवार लटक रही है और उन्हें रोजाना कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन मकानों को रैगुलर किया जाये। नेता जी पार्क का कार्य पूरा किया जाये। केन्द्रीय सरकार की तर्ज पर सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने वेतन का 50 प्रतिशत डी०ए० मूल वेतन में शामिल करने की घोषणा करके अपने यहां भी उसे लागू करने की इच्छा जाहिर की है और इस बारे में एक प्रस्ताव पास किया है।

श्री उपाध्यक्ष : विज़ साहब, अब आप वाईड-अप करें।

श्री अनिल विज़ : जिन टैम्प्रेरी कर्मचारियों की सेवा काल को तीन वर्ष हो गये हैं उनको रैगूलर करने का काम करके सरकार ने एक सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। कुछ कार्पोरेशन के कर्मचारी जैसे एम०आई०टी०सी० वगैरह के जिनको सरकार ने नौकरी से निकाल दिया है, उनको भी बहाल करके सरकार के किसी विभाग में समायोजित किया जाये। हमारे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को एच०आर०ए० केन्द्र सरकार की तर्ज पर नहीं मिल रहा है जबकि पंजाब, यू०टी० और केन्द्र के कर्मचारियों को जो एक ही बिल्डिंग में बैठते हैं उनको मूल वेतन का 15 प्रतिशत एच०आर०ए० मिल रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह जो अन्तर है, इसको दूर करने की कोशिश की जाए।

श्री अध्यक्ष : विज़ साहब, आप बैठिये।

श्री अनिल विज़ : उपाध्यक्ष महोदय, अम्बाला कैंट में सांईटिफिक उद्योग काफी हैं और एक समय था जब अम्बाला कैंट सांईटिफिक गुडज के केन्द्र के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज वह धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है, उनको रियायत देने का काम किया जाये। दूसरे स्टेटों में इन उद्योगों पर टैक्स माफ कर रखा है क्योंकि इन उद्योगों में जो सामान बनता है उसका ज्यादातर सरकारी दफ्तरों में ही प्रयोग होता है इसलिए इन उद्योगों पर जो टैक्स लगता है उसको खत्म किया जाना चाहिए। मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ धन्यवाद।

आई०जी० (से०नि०) शेर सिंह (जुलाना) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रो० सम्पत सिंह जी ने 12 तारीख को जो बजट प्रस्तुत किया उस पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और बजट के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वैसे तो सम्पत सिंह जी मेरे दोस्त हैं और हमारे अंदर बहुत सी समानताएं भी हैं। ये जो बजट आंकड़े बनाये गये हैं इनके बारे में मैं सुबह से सुन रहा हूँ। ये आंकड़े सही हैं या गलत हैं ये तो समय ही बतायेगा। लेकिन बजट में reflection है और ऑडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि fiscal performance of the State was unsatisfactory due to continued revenue deficit and fiscal deficit. इस तरह के रैवेन्यू पर जो खर्चा है, यह संतोषजनक नहीं है। अब मैं उस बात पर आना चाहूँगा कि जो ऑडिट ब्रांच वालों ने किताब में लिखा हुआ है, इसे देखकर मुझे निराशा होती है और आप लोगों को भी होती होगी कि

[आई०जी० (से०नि०) शेर सिंह]

हमारा प्रदेश कहां जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश हैं, जहां किसान और मजदूर लोग रहते हैं, जिनकी संख्या 75 प्रतिशत या उससे अधिक है और ये लोग कृषि पर आधारित हैं तथा गावों में रहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि मौजूदा सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है। चाहे पानी की बात हो या बिजली की बात हो। खेतीबाड़ी से जो पैदा होता है उसी पर हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था निर्धारित है। हमारे प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर भी कृषि पर ही आधारित है और उसी से हमारे प्रदेश का स्तर ऊंचा होता है। बजट में खेतीबाड़ी के लिए कितना पैसा रखा गया है यह बताने की जरूरत नहीं है। किसानों की इनपुट क्या है इस और ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो वे खर्चा करते हैं चाहे पानी पर, बिजली पर, बीज पर, कटाई पर , खाद पर वह कितना कर रहे हैं। क्या इसका हिसाब लगाया गया है और उनको मिल कितना रहा है। जो वे मेहनत कर रहे हैं वह उनको मिल रही है या नहीं मिल रही यह देखने वाली बात है। यानि जो वे खर्च कर रहे हैं वह उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जब वे अपनी फसल को बेचने के लिए जाते हैं तब उनको फायदा मिलता है या नहीं मिलता है यह गौर करने वाली बात है। यदि उनको इसमें फायदा नहीं है तो इस पर विचार करना बहुत जरूरी है और कहीं वे जा नहीं सकते। इस पर सरकार को उनको सबसिडी देनी चाहिए। इसकी हमें चिंता रहनी चाहिए क्योंकि किसानों के श्रू ही हम अपना पेट भरते हैं। जहां तक रोजगार की बात है यह समस्या और किसी की समस्या नहीं है किसानों और मजदूरों की यह समस्या है। यह लोग नौकरी के लिये दर-दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। क्योंकि उनको पता है कि यदि छोटी सी नौकरी उनको मिल जायेगी तो वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पायेंगे और उनका भविष्य उज्ज्वल बना सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हर साल नौकरियां कम होती जा रही हैं और लोगों को नौकरी देने की बजाए नौकरी से निकाला जा रहा है। पिछले चार साल में हमने यह देखा है।

श्री उपाध्यक्ष : शेर सिंह जी प्लीज आप वाईंड-अप करें।

आई०जी० (से०नि०) शेर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही वाईंड-अप करता हूँ? मैं नौकरी के बारे में बात कर रहा था। यह गौर करने वाली बात है कि सरकार सभी को नौकरी नहीं दे सकती, कोई भी सरकार नहीं दे सकती लेकिन उनके लिये दूसरे प्रयोजन किए जा सकते हैं। हमारे यहां जो कारखाने लगे हुए हैं, उन कारखानों में हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। इसका दूसरा समाधान यह भी है कि यदि हम सबको नौकरी नहीं दे सकते तो सरकार को कम दर पर कुछ पैसे का प्रावधान पढ़े लिखे नौजवानों के लिये करना चाहिये ताकि वे अपना धन्धा कर सकें और अपना जीवन यापन ठीक ढंग से कर पायें। इस ओर सरकार को नौजवानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नौजवानों का आने वाला भविष्य अंधकारमय दिखता है। उपाध्यक्ष महोदय, सभी ने अपने-अपने हल्कों की समस्याओं का जिक्र किया, मैं भी करूंगा लेकिन सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या की है, जिस पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है उस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इस पर गंभीरता से सबको विचार करना चाहिए। मौजूदा सरकार ने देवी रूपक योजना चलाई है, यह बहुत अच्छी योजना है। लेकिन इसका फायदा कौन उठा पाएगा। हमारी ज्यादातर जनता अनपढ़ है और गांवों में रहती है वे लोग इस पर विश्वास नहीं करते। इसका फायदा उठाने वालों की संख्या बहुत कम है, ये आंकड़े भी बता रहे हैं, केवल एक हजार लोगों ने ही देवी रूपक स्कीम का फायदा उठाया है। हम अपने प्रदेश की जनसंख्या दर में किस प्रकार से कमी ला सकते हैं इस पर गौर करने वाली बात है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि बाहर से जो लोग यहां पर आते हैं, आजकल गुड़गांव और

फरीदाबाद में बहुत आ रहे हैं। कितने लोग आये हैं, कहां से आये हैं, क्या सरकार के पास उनका कोई आंकड़ा है। सरकार को उन आंकड़ों को देखने की जरूरत है। आज हम अपने यहां सस्ते दामों पर मजदूर तो लगा लेते हैं लेकिन वह ही कल हमें आने वाले समय में बाहर निकालेगा। इसमें देखने की जरूरत है, इसमें तवज्जोह देने की जरूरत है कि कितने आदमी बाहर के राज्यों से आने वाले यहां पर रह जाते हैं और यहीं पर समा जाते हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए जगह नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी जगह पर तो वह बाहर से आने वाला व्यक्ति कब्जा कर लेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं टैक्स लगाये जाने बारे अपनी बात कहना चाहता हूँ। सरकार कहती है कि हम टैक्स नहीं लगाते और वित्त मंत्री जी भी कह रहे हैं कि पिछले 4 सालों से कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं जबकि आपकी वजह से पिछले चार साल से लोग चिल्ला रहे हैं। चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो या कर्मचारी हो, सब टैक्स लगाए जाने की वजह से चिल्ला रहे हैं। अब सरकार ने जो कर्मचारियों का डी०ए० बढ़ाया है क्या उस पर लगने वाले टैक्स को ये माफ करेंगे क्योंकि जो पैसा सरकार अब बढ़ाने जा रही है वह पैसा उनकी इन्कम टैक्स की स्लैब में आ जाएगा। एक तरफ से तो पैसा बढ़ा देते हैं और दूसरी तरफ से पैसा काट लेते हैं। आपको इस सिस्टम को बंद करना पड़ेगा तभी जाकर किसी को राहत मिल पाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : आई०जी० साहब, इन्कम टैक्स वाला मामला सम्पत सिंह जी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। आप वाईंड-अप करें। अभी आपके दूसरे साथियों ने भी बोलना है, इसलिये अब आप बैठ जाएं।

आई०जी० (सेवा निवृत) शेर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के जुलाना की बात करना चाहूँगा। मेरा हल्का टोटली रूरल एरिया है। मेरे हल्के में केवल एक छोटा सा शहर जुलाना है। पहले जुलाना में एक छोटी सी कमेटी हुआ करती थी। उस कमेटी के पास अपनी जमीन है और दूसरी चीजें हैं। हमारी वह छोटी सी कमेटी पूरे नौकरशाही को पैसा दिया करती थी। अब मैं आपके माध्यम से सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि इस जुलाना शहर की कमेटी को सरकार ने तोड़ दिया है। जो कमेटियां सरकार ने तोड़ी थीं उसमें से बहुत सारी कमेटीज को सरकार रेस्टोर कर चुकी है इसलिए मेरी मांग है कि मेरे क्षेत्र की इस कमेटी को भी रेस्टोर किया जाये क्योंकि वहां पर जन-स्वास्थ्य की बड़ी भारी समस्या है। वहां पर पहले सिवरेज सिस्टम शुरू किया गया था लेकिन बाद में बन्द कर दिया गया था। वहां पर इस काम के लिए सरकार का डेढ़ करोड़ रुपया भी लग चुका था। (घण्टी) मेरी आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग है कि इस कमेटी को पुन: रेस्टोर किया जाये ताकि वहां की नालियों व सिवरेज सिस्टम को ठीक किया जा सके। धन्यवाद।

राव दान सिंह (महेन्द्रगढ़) : परम आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका तहदिल से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय चौधरी सम्पत सिंह वित्त मंत्री जी ने यह 5वां बजट पेश किया। इनके पिछले 4 सालों के बजट को देख कर तो ऐसा लगता है कि इन्होंने नया कुछ भी इस बजट में नहीं दिया जबकि ये इसको लोक-लुभावना बजट कह रहे हैं। इस बजट में वित्त मंत्री जी ने न तो कोई नया कर लगाया और न ही लोगों को कोई राहत दी। इस बजट में अगर कोई चीज देखने को मिलती है तो वह है घटता हुआ राजस्व और बढ़ता हुआ खर्च। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा की पहचान कृषि से की जाती है और कहा जाता है कि There is no culture in Haryana except agriculture. यह एक इतना महत्वपुर्ण क्षेत्र है कि इसको बजट के अन्दर अनदेखा किया गया है। इसका जीता-जागता उदाहरण है यह बजट। इस बजट में केवल मात्र टोटल बजट का 3.56 परसेन्ट हिस्सा ही कृषि पर खर्च किया जा रहा है जबकि इस

[राव दान सिंह]

इन्कम में से 44.24 परसेन्ट हमारे द्वारा लोन लिए हुए कर्जे की रि-पेमैंट और ब्याज पर दिया जा रहा है यानि हम मांगे हुए पैसे से दीवाली मनाना चाहते हैं और प्रदेश की जनता को एक ऐसी तस्वीर पेश करना चाहते हैं जो कि बहुत गुलाबी नजर आये जबकि हम सच्चाई से और गहराई से इस बारे में सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आज इस प्रदेश की 75 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है और बढ़ती हुई औद्योगिक तीव्र गति के बाद हमारी मुख्य आजीविका कृषि है। कृषि को इस तरह अनदेखी करना किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। यहां का किसान इतना मेहनती है जो धरती का सीना चीर कर उसे अपने पसीने से भिगोकर अनाज पैदा करने की क्षमता रखता है। इस बजट में किसानों को कोई इन्सैन्टिव या प्रोत्साहन नहीं दिया गया है और न ही किसानों को विविधीकरण फसलों के बारे में बताया गया है और न ही उनको सस्ते भाव पर डीजल और बिजली दी गई है। किसानों की फसलों के बीमे की योजना भी अभी तक खटाई में पड़ी है। जब कहीं पर औद्योगिक विकास किया जाना होता है तो उस वक्त किसानों की जमीन को ओने-पोने भाव पर खरीद लिया जाता है। जब दिल्ली सरकार 23 लाख रुपये पर एकड़ का रेट दे सकती है तो हरियाणा गवर्नमैंट क्यों नहीं दे सकती है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से तथा माननीय वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि हरियाणा में भी ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि यहां के किसान को भी कुछ राहत मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं इन्फ्रास्ट्रक्चर का जिक्र करता हूँ। बजट के अन्दर इन्होंने बहुत ही कम पैसे का प्रावधान रखा है। वैसे किसी भी प्रदेश और देश के विकास के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी है। एक तरफ तो हम कैलिफोर्निया, सिंगापुर, यूरोप और अमेरिका से कम्पेयर करना चाहते हैं और दूसरी तरफ इन्फ्रास्ट्रक्चर के डिवैल्पमैंट के लिए मात्र 14.71 प्रतिशत पावर, ट्रांसपोर्ट, रोडस एण्ड बिल्डिंग पर खर्च करते हैं। यह पैसा बहुत ही कम है। दिल्ली के चार तरफ नहीं बल्कि तीन तरफ हरियाणा पड़ता है और हमारी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि अगर कोई उद्यमी राजधानी में आएगा तो उसकी नजर सबसे पहले हरियाणा पर जाएगी। अगर कोई व्यक्ति निवेश करने के लिए यहां पर आएगा तो सबसे पहले निवेश करने के लिए उसकी नजर हरियाणा पर जाएगी। अगर हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्रोंग होगा तो निश्चित तौर पर हमें उसका फायदा मिलेगा। जहां तक सॉफ्टवेयर का सवाल है, सरकार ने बहुत अच्छे आंकड़े दिए हैं और मैं समझता हूँ कि इस मामले में किसी हद तक काम किया गया है लेकिन हम से ऊपर बंगलौर और आन्ध्र प्रदेश के अन्दर हैदराबाद का नम्बर आता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि अगर इस पर और ध्यान दिया जाए तो हम उनसे कहीं और आगे हो सकते हैं तथा नम्बर एक स्टेट बनाने का जो स्वप्न हमने देखा है उस स्वप्न को साकार किया जा सकता है। डिप्टी स्पीकर साहब, शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए सरकार ने पिछले 2-4 दिनों में अपने विचार यहां पर रखे हैं और अपनी खूब बढ़ाई की है। मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि हम तो शिक्षा के इस सागर में रह कर भी प्यासे हैं। एक तरफ विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षा संस्थान, मैडीकल कॉलेज और डैंटल कॉलेज हैं लेकिन दूसरी तरफ जहां उपाध्यक्ष महोदय आपका क्षेत्र भी आता है, कोई डैंटल कॉलेज नहीं है कोई मैडीकल कॉलेज नहीं है। इतनी बड़ी असमानता है, शिक्षा का मौलिक अधिकार हमें भी मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : दान सिंह जी, आपने मेरे हल्के का नाम लिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मेरे हल्के में 50 साल में केवल दो कॉलेज थे लेकिन इन चार सालों के अन्दर दो नये कॉलेज बने हैं और तीसरा डैंटल कॉलेज बना है। आपके क्षेत्र से चुने हुए व्यक्ति कई साल तक शिक्षा मंत्री रहे हैं और अगर वहां पर कोई कॉलेज नहीं खुले हैं तो उसके लिए आप उन्हें दोष दें।

राव दान सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी बात मान ली, मैं उनको दोष दूंगा साथ ही इस सरकार से भी कहूंगा कि वहां पर शिक्षा संस्थान खुलने चाहिएं। मेरी यह मांग है कि वहां पर लॉ कॉलेज और गवर्नमैंट कॉलेज के लिए प्रावधान किया है यह बात बिल्कुल सत्य है लेकिन इन्जीनियरिंग और मैडीकल कॉलेज अभी भी वहां पर कोई नहीं है और वहां पर एक विश्वविद्यालय की भी आवश्यकता है। हमारे जिले के अन्दर कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है जबकि यूनिवर्सिटी का यह रिकॉर्ड है कि पढ़ाई के अन्दर हमारे बच्चे हमेशा उत्तम स्थान पर रहे हैं। इस प्रकार से हमारे साथ शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव किया जा रहा है और मैं यह चाहूँगा कि सरकार इस तरफ पूरा ध्यान दे और आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के अन्दर कम से कम एक विश्वविद्यालय अवश्य दें ताकि हमारे बच्चे भी पढ़-लिख कर अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए सोच सकें। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं औद्योगिक विकास की बाबत अपनी बात कहना चाहूँगा।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डॉ० एम०एल० रंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, राव दान सिंह जी ने दक्षिणी हरियाणा की बात कही है तो मैं इनके ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि करना चाहूँगा। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जो रीजनल सैंटर मन्जूर किया है, उसकी आधारशिला 19 तारीख को दोपहर बारह बजे रख रहे हैं, वहां पर कई कोर्सिज चलाए जाएंगे जिससे बच्चों को सुविधा होगी। रिवाड़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज पहले से ही चल रहा है, जे०बी०टी० सैंटर की आधारशिला वहां पर रखी जा चुकी है, साथ में जो पोलिटैक्निक वहां पर खुलना है, उसका जमीन का स्टे ऑर्डर खाली हो चुका है और वह भी पाइप लाइन में है।

राव दान सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन सब बातों से हमारा पेट नहीं भरता। जब तक कोई मैडीकल कॉलेज नहीं खुलता कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती तब तक मैं कह सकता हूँ कि हमें समान रूप से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जल संसाधनों की बात है, यह प्रगति का मुख्य आधार है। हमारे यहां पर जलस्तर दिन-प्रतिदिन नीचे जा रहा है और 1700 फुट की गहराई तक हमने जमीन को खोद कर देख लिया है वहां पर मीठी मिट्टी तक नहीं मिली। सिंचाई की बात तो छोड़िये वहां पर तो पीने के पानी की भी समस्या बनी हुई है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया और बजट के अन्दर इसके लिए कोई पैसा निर्धारित नहीं किया जो हमारे काम आए। जो भू-जलस्तर गिरता जा रहा है उसके लिए मेरा एक सुझाव है कि जो नहरें निकलती हैं या बरसात होती है तो उसके पानी से रिचार्जिंग हो सकती है। जो बरसात का पानी आता है उसको हारनैस्ट करने के लिए वहां पर बोरिंग किए जाने चाहिएं जिससे बरसात का पानी नीचे जाए और रिचार्ज होकर हमारे गिरते जलस्तर को रोक सके। ऐसे बोरिंगज के लिए सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है।

16-00 बजे

श्री उपाध्यक्ष : दान सिंह जी, आप बैठ जाएं। आपका समय समाप्त हो गया है। मैं सदन के बाकी सदस्यों से कहना चाहूँगा कि अगर कोई बोलना चाहता है तो वह अपना नाम भेज दें ताकि बाद में कोई यह नहीं कहे कि उसको बोलने का मौका नहीं दिया गया है।

राव दान सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा समय और दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर नगर विकास मंत्री जी बैठे हुए नहीं हैं। मैंने सदन में सुबह भी कहा था कि हमारे यहां पर म्यूनिसिपल कमेटी की बहुत दयनीय हालत है। उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को दो महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। उपाध्यक्ष महोदय, जब कर्मचारियों को तनख्वाह ही नहीं मिल रही है तो बाकी के विकास कार्य क्या हो रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो मंत्री जी सदन में पढ़ रहे थे

[राव दान सिंह]

कि एक-एक कमेटी को अढ़ाई-अढ़ाई करोड़ रुपए दिए गए हैं जबकि हमारी कमेटी के पास स्टाफ को देने के लिए तनख्वाह भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि हमारे साथ यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है। दूसरी बात मैं यहां पर यह कहना चाहता हूँ कि कनीना में अंग्रेजों के समय की आजादी से पहले की सब-तहसील थी, उसको तोड़ दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पुनः सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सब-तहसील तृतीय श्रेणी में सबसे मजबूत स्थिति में थी, उसको पुनः रेस्टोर किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ़ की बगल में रोड़ जाती है और वहां पर एक रेलवे ट्रैक है जहां पर घंटों-घंटों ट्रैफिक जाम रहता है, इस बारे में मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां पर फलाई ओवर बनाया जाए। धन्यवाद।

चौ० जय प्रकाश (बरवाला) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने हमारी गैरहाजिरी में कल जो यह बजट पढ़कर सदन में सुनाया है, यह कोई बजट नहीं है। यह इस सरकार का पांचवा बजट है और प्रोफैसर साहब ने इस बजट में सिर्फ पिछले बजट की आंकड़ों की अदला बदली की गई है। आज पूरे प्रदेश ने जब अखबारों के माध्यम से इस बजट के बारे में पढ़ा तो उन्होंने यह कहा कि यह बजट क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ लोक सभा के चुनावों को देखते हुए यह बजट पेश किया गया है। यह सरकार हर साल कहती है कि हमने कर-मुक्त बजट पेश किया है। लेकिन जैसे ही सोमवार को ये यह बजट पास करवा लेंगे, उसके बाद करों की भरमार लगा दी जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, जितने कर इण्डियन नेशनल लोकदल ने लगाए हैं, उतने कर किसी भी पार्टी की सरकार के वक्त में नहीं लगाए गए हैं, अब बी०जे०पी० का पता नहीं कि वे इनके साथ है कि नहीं हैं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के बारे में जो कर-मुक्त बजट होने की बात कही गई है, इस बारे में बहुत से लोग प्रचार करेंगे और बजट पास होने के बाद तो प्रो० साहब भी यह प्रचार करेंगे कि देखा हमारी सरकार ने कर-मुक्त बजट पेश किया है, कोई भी कर नहीं लगाया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहूँगा कि इन्होंने सबसे ज्यादा कर लगाए हैं और वे कर हरियाणा के किसान पर लगाए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार पहली ऐसी सरकार है, मैं तो यह कहूँगा कि यह बाई-चांस बनी हुई सरकार है जिसने हमारे इलाके में राईस सूट लगाया है। उस पर पहले 150 रुपये लगते थे, उसको इन्होंने बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया है। पहले जो फरद फीस देते थे, उसके भी चार्जिज इस सरकार ने बढ़ा दिए हैं और तो और जो ड्राईविंग लाईसेंस लेते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन फीस भी बढ़ा दी है। उपाध्यक्ष महोदय, अब इन्होंने किसान पर दो-दो मार कर दी हैं। एक तो लाईसेंस फीस बढ़ा दी है, दूसरे इन्होंने डीजल पर डेढ़ रुपए प्रति लिटर बढ़ा दिए हैं तथा टोकन टैक्स भी बढ़ा दिया है। चानि के हर मामले में इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए हैं। धोबी, नाई और तो और बढ़ई को भी इस सरकार ने नहीं छोड़ा है। आपने पब्लिक के हर वर्ग पर टैक्स लगाए हैं, जिसकी मैं घोर निन्दा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : जय प्रकाश जी, आप इस बात के लिए श्योर हैं कि राईस सूट की फीस 150 रुपये थी। (शोर) आप यह बताएं कि आप श्योर हैं।

चौ० जय प्रकाश : जी हाँ, मैं श्योर हूँ।

श्री राम पाल माजरा : नहीं, आपको इस बारे में सही पता ही नहीं है।

चौ० जय प्रकाश : पहले यह फीस 30 रुपये थी, फिर यह 150 रुपये की गई और अब यह

1500 रुपये कर दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, राम पाल माजरा जी जो सदन में कह रहे थे कि हमने 36,000 ट्यूबवैल कनैक्शन दे दिए हैं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा हालांकि राम पाल जी रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। जब बिजली की बात आती है तो ये अधिकारियों द्वारा लिखे हुए दस्तावेजों को पढ़ना शुरू कर देते हैं इसलिए रिप्लाई देना इनके वश की बात नहीं है। इनकी मजबूरी है। जो सरकार की नयी पॉलिसी है जिसमें इन्होंने कहा कि दस हजार, बीस हजार या एक लाख रुपये देकर किसान कनैक्शन ले सकता है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश में पांच एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसान बहुत कम बचे हैं इसलिए वे एक-एक लाख रुपये ट्यूबवैल के कनैक्शन के लिए बिजली बोर्ड में सरकार कनैक्शन कैसे ले सकते हैं? इसलिए इस बारे में मेरा कहना यह है कि यह पैसा कम करो और अगर आपने पूरी तरह से वाहवाही लूटनी है तो यह बिल्कुल माफ कर दो।

श्री कृष्ण लाल पंवार : सर, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। ये कह रहे हैं कि एक-एक लाख रुपया जमा करवाकर उनको कनैक्शन नहीं मिला है। पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हमारी सरकार आने के बाद 36 हजार ट्यूबवैल के कनैक्शंज दिए गए हैं। पूर्व सरकारों के समय की जो 75 हजार टैस्ट रिपोर्ट पैंडिंग थी उनमें से 36 हजार क्लीयर करके कनैक्शंज दिए गए हैं और इसके बाद भी यदि किसानों को तीन महीने के अंदर-अंदर कनैक्शन नहीं मिलता तो जो किसानों की राशि जमा है उस पर बैंक के इंट्रस्ट के हिसाब से उनको ब्याज दिया जाएगा। (इस समय श्री अध्यक्ष पधासीन हुए)

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, कृष्ण पाल जी ने याद दिलवा दी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी सरकार की विश्वसनीयता ही जब लोगों में खत्म हो चुकी है तो आपका तीन महीने कौन विश्वास करेगा? इन्होंने चुनावों के समय भी अपने घोषणा पत्र में कहा था कि गले की बकाया राशि पर सरकार ब्याज देगी लेकिन बाद में मना कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बिजली के स्लैब रेट लगाने की बात है। कहीं पर कम और कहीं ज्यादा बिजली के स्लैब रेट लगाए हुए हैं जबकि लाईट तो सब जगह उतनी ही जलाते हैं इसलिए मेरा कहना यह है कि इस से किसानों को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। प्रो० सम्पत सिंह जी बड़ी चर्चा कर रहे थे कि हमने नेशनल हाई-वे पर हाई-वे सिक्योरिटी आर्गेनाइजेशन का गठन किया है लेकिन उनका काम क्या है, उनका काम यह है कि वे हाई-वेज पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाने में मदद करें, लोगों की सुरक्षा करें और यदि कोई ऐक्सीडैंट हो गया है तो लोगों को उपचार हेतु ले जाने में मदद करें। लेकिन वे कर यह रहे हैं कि वे लोगों के व्हीकल्ज रूकवाकर लाईसैंस चैक करते हैं जिससे हाईवेज पर जाम का जाम लग जाता है। मेरा निवेदन है कि जो उनका काम है वह वही काम करें क्योंकि चैकिंग करने का काम उनका नहीं है।

श्री पूर्ण सिंह दाबड़ा : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। सर, मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मैम्बर को बता देना चाहता हूँ कि हाई-वे ट्रैफिक के बारे में जो हरियाणा सरकार ने कदम उठाया है, वह पूरे हिन्दुस्तान में किसी भी प्रदेश की सरकार ने नहीं उठाया है। सबसे पहले आपके प्रदेश की सरकार ने यह कदम उठाया है। इसके बाद से ऐक्सीडैंट्स के रेशो में बहुत कमी आयी है और कितने ही लोगों की लाईफ सेफ हुई है। (विघ्न) लेकिन ये इस चीज की तरफ ध्यान नहीं कर रहे हैं कि सरकार कितने लोगों की लाईफ सेफ कर रही है। इनका ध्यान तो सिर्फ इस तरफ है कि मेरी जीप को क्यों रोक दिया, मेरी सुमो को क्यों रोक दिया। इसीलिए इनको परेशानी है। ये एम०एल०ए० हैं इसलिए ये महसूस करते हैं कि मेरी गाड़ी न रुके। They have got every right to stop you

[श्री पूर्ण सिंह दाबड़ा]

and to ask you for your vehicle's documents. ये इसीलिए अप्वायंट किये गये हैं ताकि हाई-वेज पर कोई नाजायज व्हीकल्स न गुजरे, कोई गलत कार्रवाही न हो। चूंकि इनके गलत साथी इसमें लगे हुए हैं इसलिए इनको परेशानी हो रही है। (विघ्न)

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कह तो दिया लेकिन ये किस-किस क्षेत्र में सफाई देंगे। पहले तीन आर०टी०ओ० होते थे लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर पर डी०टी०ओ० भी लगा दिए। आपने जी०एम० को, सिटी मैजिस्ट्रेट को, शूगर मिल के जनरल मैनेजर को और रोड़वेज के मैनेजर को, सबको यह पॉवर दे दी और सरकार ने आज हालत यह कर दी कि किसान के ट्रैक्टर के ऊपर भी पैनल्टी लगानी शुरू कर दी जिस ट्रैक्टर को चौधरी देवी लाल जी ने गड्डा घोषित किया हुआ था उन ट्रैक्टरों के सरकार ने चालान करने शुरू कर दिए और चालान भी 2-2, 3-3 हजार रुपये के करने शुरू कर दिए।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, जो ट्रैक्टर कैरियर चैनल में यूज होते हैं उनके चालान करते हैं, जो किसान के ट्रैक्टर हैं उन पर हम कभी चालान नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, अब आप वाईड-अप करें।

चौ० जय प्रकाश : सर, मैं अभी वाईड-अप करता हूँ। जो कैरियर चैनल होते हैं उनका चालान करते हैं आपने यह बात तो कह दी क्योंकि आपका तो जुगाड़ चल रहा है। अध्यक्ष महोदय आप भी किसान हैं मैं भी किसान हूँ। सर, सोमवार को मैं रिकॉर्ड लाकर दिखा दूंगा। जो दस एकड़ या पांच एकड़ जमीन का जमींदार है, वह ट्रैक्टर ले लेता है उससे वह लोडिंग अनलोडिंग का काम कर ले तो किसान का फायदा है। ये सारी मार किसान को देते हैं, गोली चलानी हो तो किसान पर चलाते हैं, वाटर टैक्स लगाने की बात हो तो किसान पर लगाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि किसान को परेशान किया जाता है। गांवों में पेयजल के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, वैसे तो होर्डिंग लगने तो मारुति कार, पैप्सी कोला और कोका कोला के चाहिए थे लेकिन आज क्योंकि हरियाणा सरकार की जनता के मन में विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है इसलिए सरकार जगह-जगह होर्डिंग लगा रही है पेयजल योजनाओं के बारे में बड़ी-बड़ी बातें की गई हैं। मैं प्रोफैसर साहब को अपने हल्के के गांव के बारे में बताना चाहता हूँ। खरक पूनियां गांव में वाटर सप्लाई की नयी स्कीम के तहत पाइप लाइन डाली थी वह सारी की सारी पाइप लाइन फूट गई उसके आस-पास लीकेज हो गई और उससे कई लोगों के मकान खराब हो गए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जनता के खून पसीने की कमाई जो सरकारी खजाने में आती है क्या उसमें आप यह देखते हैं कि जो मैटीरियल लगाया जा रहा है वह सही है या नहीं? ऐसे लोगों को ठेके दे दिए गए हैं जो सरकार के समर्थक हैं और आज ऐक्सीयन, एस०ई० की हिम्मत नहीं है कि जाकर के उनका मैटीरियल या क्वालिटी चैक कर लें। यदि कोई चैक करता है तो उसका तबादला हो जाता है। मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि उस गांव में जो फिटिंग हुई है, उसकी चैकिंग करवाई जाए। जहां तक खेल की बात है। हरियाणा सरकार जगह-जगह कहती है कि खेल में यह कर दिया, वह कर दिया। मुख्यमंत्री जी अभी बैठे नहीं हैं। परसों मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं जो पत्थर रख देता हूँ वह काम जरूर करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि वैसे तो 1990 में उन्होंने कहा था कि जींद में टैक्नीकल इंस्टीच्यूट बनाएंगे। जब मेहम की जनता ने इस बारे में कहा, उस समय मैं भी उनके साथ शामिल था, उनकी मांग को ठुकरा दिया था। अब एक साल

पहले यह कहा गया था कि जीन्द में सर छोटू राम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी लेकिन प्रोफैसर साहब ने जो बजट पेश किया है उसमें उसका कहीं जिक्र नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि वह यूनिवर्सिटी बनेगी कि नहीं ?

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत से इशूज हो गए हैं इन इशूज का तो मैं मौके पर ही जवाब दे देता हूँ। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की एनाउंसमैंट हरियाणा सरकार ने नहीं की थी। हिसार में केन्द्र के स्पोर्ट्स मिनिस्टर आये थे उन्होंने वहां प्रोग्राम देखा, हरियाणा के स्पोर्ट्स पर्सन्स की अचीवमैंट को देखा, सारी चीजों को देखा, गैदरिंग को देखा, लोगों के उत्साह को देखा तो उन्होंने वहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की थी और सिर्फ वहीं यूनिवर्सिटी नहीं है। गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने ही मातनहेल में पीछे डिफैंस मिनिस्टर साहब आए थे और उन्होंने वहां पर डिफैंस यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी अब वे दोनों यूनिवर्सिटीज की फाइल गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के पास पैंडिंग है। नॉर्थ जॉन सैन्टर की एनाउंसमैंट भी की थी आपको पता है कि नॉर्थ जॉन सैंटर सोनीपत में बन रहा है, रोड़ पर ही हाई-वे के साथ वह बन रहा है, उसका काम काफी तेजी से चल रहा है। गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने इन दोनों यूनिवर्सिटीज की घोषणा की है और वह जल्दी बनेंगी इसलिए उनके लिए हरियाणा के बजट में पैसा रखने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे हिन्दुस्तान में अब तक ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है इनको तो गवर्नमैंट का धन्यवाद करना चाहिए कि गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने जगह जीन्द चुनी है।

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद किस बात का मैं तो खेद प्रकट करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा करते हैं और वित्त मंत्री महोदय कहते हैं कि पैसा सैंटर से आवेगा। जीन्द जिले की वोट लेने की वाहवाही लूटने के लिए तो यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप वाईड-अप कीजिए और बैठिये।

चौ० जय प्रकाश : प्रो० साहब, जो बात आप आज कह रहे हैं वह बात आप एक साल पहले भी कह सकते थे क्योंकि जब जीन्द के लोगों का दबाव आया तो पिछले बजट में यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही थी और उसके लिए बजट में प्रावधान भी किया था लेकिन इस साल नहीं किया। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अगर बनानी थी तो सिरसा में बना लेते। चौधरी देवी लाल जी के नाम पर अब सिरसा में पढ़े-लिखों के लिए यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी जो घोषणा करते हैं उस पर कभी खरे नहीं उतरते। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आपको काफी समय दिया जा चुका है।

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूँगा। सरकार ने पहली जमात से अंग्रेजी शुरू की है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अधिकारियों के कहने पर और सरकार की दाब पड़ने पर सम्पत सिंह जी ने हरियाणा प्रदेश की जनता को आंकड़ों में घेर दिया है और एक अच्छा बजट पेश नहीं किया है। यह सरकार सरकारी तन्त्र के हाथों में खेलकर हरियाणा की जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। मैं इस बजट की निन्दा करता हूँ यह बजट हरियाणा के लोगों के साथ खिलवाड़ है और बहुमत का नाजायज फायदा उठाकर सरकार ने यह बजट पेश किया है इसके लिए आने वाले लोकसभा के चुनावों में जनता इसका फैसला कर देगी और मैं समझता हूँ कि इस सरकार को दस में से एक भी सीट नहीं मिलेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आज बजट पर बहस की चर्चा चल रही है। कोई माननीय सदस्य अगर बोलना चाहता है तो उसको इजाजत है। कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों के सभी सदस्यों को बोलने के लिए पूरा समय दिया गया है अब 16-2-2004 को वित्त मंत्री प्रो० सम्पत सिंह जी बजट पर रिप्लाई देंगे। Now, the House stands adjourned till 11.00 A.M. on Monday, the 16th February, 2004.

*16.18 hrs. (The Sabha then *adjourned till 11.00 A.M. on Monday, the 16th February, 2004.

38064—HVS—H.G.P., Chd.